वर्ष 12 • अंक 281 • 12 पृष्ठ • मूल्य 5 रुपये

सोमवार 13 जनवरी 2020

कोलकाता, चंडीगढ़, **नई दिल्ली**, पटना, भोपाल, मुंबई, रायपुर और लखनऊ से प्रकाशित।

भारत का पहला संपूर्ण हिंदी आर्थिक अखबार

बिज़नेस स्टैंडर्ड

www.bshindi.com

▶▶ पृष्ठ 2

बीएस-6 डीजल मॉडल की कीमत में कम बढ़ोतरी

नरेंद्र मोदी ▶▶ पृष्ठ 12

ममता पर मोदी का तीखा प्रहार

एक नज़र

तिमाही नतीजों, वैश्विक रुख से तय होगी बाजार की दिशा

शेयर बाजार की दिशा इस सप्ताह कंपनियों के तिमाही नतीजों, मुद्रास्फीति के आंकड़ों तथा अमेरिका-चीन के बीच व्यापार शुरुआती व्यापार करार जैसे घटनाक्रम से तय होगी। विश्लेषकों का कहना है कि इस सप्ताह तीसरी तिमाही के परिणाम तथा बजट-पूर्व गतिविधियों से बाजार प्रभावित होगा। इस सप्ताह सोमवार को खुदरा मुद्रास्फीति तथा मंगलवार को थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति के आंकड़े आने वाले हैं।

200 लड़ाकू विमान खरीदेगी वायुसेना

रक्षा सचिव अजय कुमार ने रविवार को कहा कि वायुसेना की जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार 200 लड़ाकू विमान खरीदने की प्रक्रिया में है। उन्होंने कहा कि एचएएल द्वारा बनाए गए 83 हल्के लड़ाकू विमान तेजस मार्क 1 ए के लिए अनुबंध अंतिम चरण में है। इसके अलावा 110 विमानों की खरीद के लिए अभिरुचि पत्र जारी किया गया है। इस तरह करीब 200 विमानों के अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है।

कैप्सस्टोन से एडलवाइस का संबंध नहीं : रशेष शाह

एडलवाइस ने रविवार को कहा कि समूह की इकाइयों का कैप्सस्टोन फॉरेक्स के साथ कोई संबंध नहीं है। प्रवर्तन निदेशालय करोड़ों रुपये के विदेशी मुद्रा लेनदेन के मामले में इस कंपनी की जांच कर रहा है। साथ ही कहा कि कैप्सस्टोन के साथ कथित संबंध के कारण जांच के घेरे में आए संजय एन शाह का समूह के साथ कोई और संबंध नहीं है। एडलवाइस समूह के चेयरमैन शाह ने कहा कि विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के उल्लंघन के आरोप गलत हैं। शाह को सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश होना है। इससे पहले उन्हें 9 जनवरी को पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन व्यक्तिगत व्यस्तता के कारण उन्होंने कुछ समय मांगा था।

सऊदी अरामको का आईपीओ रिकॉर्ड स्तर पर

सऊदी अरब की दिग्गज पेट्रोलियम कंपनी सऊदी अरामको का आईपीओ रिकॉर्ड 29.4 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। यह पूर्व में घोषित आंकड़े से अधिक है। कंपनी ने ग्रीन शू विकल्प का इस्तेमाल कर निवेशकों की मांग को पूरा करने के लिए लाखों और शेयर बेचे हैं, जिससे आईपीओ की राशि बढ़ गई है।

आज का सवाल

क्या अधिग्रहण संहिता से अल्पांश शेयरधारकों के हितों की होगी रक्षा

www.bshindi.com **पर राय भेजें।**
आप अपना जवाब एसएमएस भी कर सकते हैं। यदि आपका जवाब हां है तो **BSP Y** और यदि न है तो **BSP N** लिखकर **57007** पर भेजें।

पिछले सवाल का नतीजा

क्या इन्फोसिस के नतीजे आईटी क्षेत्र में सुधार के संकेत हैं?	हां	81.82%
	नहीं	18.18%

फिर आएगी रियायत योजना!

बजट में हो सकती है घोषणा, पहले साल 50 हजार करोड़ रुपये मिलने की उम्मीद

दिलाशा सेठ और सुदीप्त दे
नई दिल्ली, 12 जनवरी

राजस्व की तंगी से जूझ रही केंद्र सरकार अगले आम बजट में करदाताओं के लिए कर रियायत योजना लेकर आ सकती है। इसके तहत वे अपनी पिछले 5-6 वर्षों की अतिरिक्त आय का खुलासा कर सकते हैं। इस पर उन्हें कोई जुर्माना नहीं भरना होगा और न ही उन्हें कोई सजा होगी। अभी इस प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। इससे करदाता पिछले मामलों के खुलने या सजा की आशंका के बिना अपनी घोषित आय को संशोधित कर सकते हैं। इससे न केवल कर अनुपालन में सुधार होगा बल्कि सरकार का राजस्व भी बढ़ेगा।

सरकार को इस योजना के क्रियान्वयन के पहले वर्ष कम से कम 50,000 करोड़ रुपये मिलने का अनुमान है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के सदस्य अखिलेश रंजन की अगुआई वाले प्रत्यक्ष कर कार्य बल ने इसका सुझाव दिया था।

एक अधिकारी ने कहा, 'कई लोग अपने पिछले साल की आय का खुलासा करना चाहते हैं लेकिन वे ऐसा करने से डरते हैं। उन्हें लगता है कि जैसे ही वे ऐसा करेंगे, उनके रिकॉर्ड की जांच शुरू हो जाएगी और उन्हें जुर्माना भरना होगा। इस तरह उन्हें मोटी रकम देनी होगी। प्रत्यक्ष कर कार्य बल द्वारा दिए गए सुझाव पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है।' चालू वित्त वर्ष में देश के प्रत्यक्ष कर राजस्व में भारी कमी आई है। 15 दिसंबर तक के आंकड़ों के मुताबिक प्रत्यक्ष कर संग्रह की वृद्धि दर (रिफंड के बाद) महज 0.7 फीसदी रही है जबकि इसका बजटीय लक्ष्य 17.3 फीसदी की बढ़त के साथ 13.35 लाख करोड़ रुपये है। तीसरी किस्त के बाद अग्रिम कर संग्रह 2.51 लाख करोड़ रुपये रहा जबकि पिछले साल समान अवधि में यह 2.47 लाख करोड़ रुपये रहा था। इस तरह इसकी वृद्धि महज 1.6 फीसदी रही।

एक अधिकारी ने कहा, 'इस कदम से मुकदमेबाजी पर भी लगाम लगने की उम्मीद है। विभाग को मुकदमों पर भारी राशि खर्च करनी पड़ती है लेकिन उसे केवल 20 फीसदी मामलों में ही जीत मिलती है।' अदालतों और पंचाटों में कई वर्षों से करीबन 500,000 मामले लंबित हैं जिनमें विवाद की राशि करीब 7-8 लाख करोड़ रुपये है। नांगिया एंडरसन कंसल्टिंग के चेयरमैन राकेश नांगिया ने कहा कि अधिकांश कर विवादों में आय कर विभाग अपीलकर्ता या याची है। इसलिए इस तरह की योजना से न केवल सरकार को अतिरिक्त राजस्व मिलेगा बल्कि पंचाटों और अदालतों पर भी लंबित मुकदमों का बोझ कम होगा। उन्होंने कहा, 'इससे कारोबारी समुदाय और विदेशी निवेशकों के बीच सकारात्मक संदेश जाएगा कि सरकार बेकार की मुकदमेबाजी और विवादों को कम करने के लिए कृतसंकल्प है।'

अगस्त 2019 में कर मुकदमेबाजी की सीमा में उल्लेखनीय बढ़ोतरी की गई थी।

(शेष पृष्ठ 7 पर)

कर संग्रह का कठिन लक्ष्य

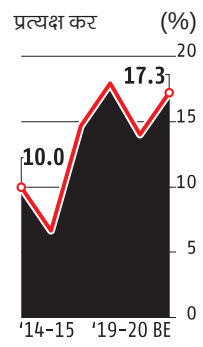

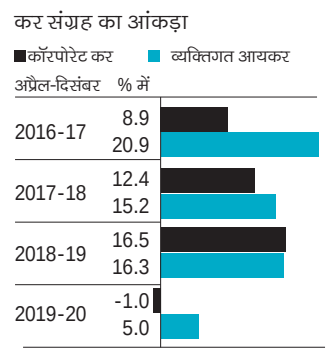

BE: बजट अनुमान

स्रोत : महालेखा नियंत्रक, भारत सकार

गैर-सूचीबद्ध फर्मों के लिए आएगी अधिग्रहण संहिता

रुचिका चित्रवंशी
नई दिल्ली, 12 जनवरी

कंपनी मामलों का मंत्रालय गैर-सूचीबद्ध कंपनियों के लिए अधिग्रहण संहिता को अंतिम रूप देने में लगा है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा कि इसे जल्द ही जारी किया जाएगा। प्रस्तावित नए नियमों के अनुसार गैर-सूचीबद्ध कंपनी में अकेले या अन्य पक्षों के साथ 75 फीसदी हिस्सेदारी लेने वालों को पूरी हिस्सेदारी लेने के लिए राष्ट्रीय कंपनी विधि पंचाट (एनसीएलटी) जाने की अनुमति होगी।

गैर-सूचीबद्ध कंपनियों के लिए कोई औपचारिक अधिग्रहण संहिता नहीं है और शेयरों का हस्तांतरण अनुबंध और समझौते के आधार पर किया जाता है। वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा, 'हम ऐसी व्यवस्था लाना चाहते हैं जो ज्यादा कठिन नहीं हो लेकिन कानून के मुताबिक हो। हम इस तरह के अधिग्रहण की प्रक्रिया और मानदंड तैयार करेंगे।'

वर्ष 2014 में सरकार ने कंपनी अधिनियम में धारा 230 (11) के तहत एक प्रावधान जोड़ा था, जिसमें कहा गया है, 'अधिग्रहण की पेशकश सहित किसी तरह के करार या समझौते इस प्रकार होंगे : सूचीबद्ध कंपनियों के मामले में अधिग्रहण भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा तैयार नियमन के अनुसार होंगे।'

धारा 230 (12) में आगे कहा गया है, 'असंतुष्ट पक्ष सूचीबद्ध कंपनियों से इतर किसी कंपनी की अधिग्रहण पेशकश से जुड़ी किसी शिकायत की स्थिति में पंचाट के पास आवेदन कर सकता है। पंचाट आवेदन के गुण-दोष के आधार पर आदेश पारित कर सकता है।' हालांकि इस संशोधन को क्रियान्वित नहीं किया गया था क्योंकि अधिग्रहण संहिता पर काम चल रहा था।

(शेष पृष्ठ 7 पर)

- **कंपनी अधिनियम की धारा 230 (11) में गैर-सूचीबद्ध कंपनियों के लिए अधिग्रहण संहिता का है प्रावधान**
- **इस उप-धारा को 2014 में जोड़ा गया था लेकिन अभी अधिसूचित नहीं किया गया है**
- **प्रस्तावित संहिता के तहत 75 फीसदी हिस्सेदारी वालों को शेष अधिग्रहण के लिए एनसीएलटी की लेनी होगी मंजूरी**

बिना अनुमति चल रहे स्वास्थ्य संस्थान होंगे बंद!

बीएस संवाददाता
नई दिल्ली, 12 जनवरी

- **अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लीनिक, पैथ लैब आदि को जैव डीपीसीसी से अनुमति लेना अनिवार्य**
- **डीपीसीसी जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम के अनुपालन के लिए कर रहा है सर्वेक्षण**

दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति की अनुमति के बिना चल रहे अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लीनिक, डिस्पेंसरी और पैथोलॉजी प्रयोगशाला जैसे स्वास्थ्य देखभाल सेवा संस्थानों को भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है।

डीपीसीसी एक अधिकारी ने बताया कि जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम के तहत सभी स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं अस्पताल, नर्सिंग होम, डिस्पेंसरी, पशु चिकित्सा संस्थान, ब्लड बैंक, रिसर्च लैब आदि किसी भी रूप में जैव चिकित्सा अपशिष्ट उत्पन्न करने, संग्रहीत करने, लाने-ले जाने के लिए डीपीसीसी से अनुमति लेना अनिवार्य है। डीपीसीसी ने कई बार जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम के तहत अनुमति लेने के लिए सार्वजनिक सूचनाओं के माध्यम से जानकारी दी है। इन सूचनाओं में बिना डीपीसीसी की अनुमति के चलने वाले इन संस्थानों को बंद करने और इनसे हर्जाना वसूलने जैसी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई थी। इन संस्थानों को पिछले साल अप्रैल-मई में आवेदन के लिए 20 शिविर का भी आयोजन किया गया था। इसके बावजूद कुछ संस्थानों के बिना अनुमति के चलने की शिकायतें मिल रही है। अब डीपीसीसी द्वारा नियमित रूप में सर्वेक्षण किया जा रहा है और नियमों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों को बंद किया जाएगा।

कम कमाई वाले हवाई मार्गों पर प्रीमियम श्रेणी बंद करेगी विस्तारा

अरिंदम मजूमदार
नई दिल्ली, 12 जनवरी

निजी क्षेत्र की विमानन कंपनी विस्तारा ने अपनी रणनीति में व्यापक बदलाव करते हुए अपने कुछ विमानों में बिजनेस और प्रीमियम इकनॉमी क्लास हटाने का निर्णय किया है। टाटा संस और सिंगापुर एयरलाइंस की संयुक्त उपक्रम विस्तारा अपनी उड़ानों में तीन श्रेणियों के कैबिन सुविधा प्रदान करती है और शुरू से ही भारतीय बाजार में प्रीमियम ब्रांड के तौर पर खुद को अलग बताती रही है। हालांकि भारतीय बाजार में किफायती विमानन सेवा का वर्चस्व है और कड़ी प्रतिस्पर्द्धा की वजह से किराया बढ़ाने की गुंजाइश काफी सीमित है। पूर्ण सेवाओं वाली विमानन कंपनी की रणनीति में बदलाव से परिचालन जटिलता और ग्राहकों के बीच भ्रम भी हो सकता है। एयर इंडिया और बंद पड़ी जेट एयरवेज पहले इस तरह की रणनीति आजमा चुकी है। हालांकि जेट ने बाद में अपना निर्णय बदल दिया था।

विमानन सलाहकार फर्म सीएपीए की रिपोर्ट में कहा गया है, 'भारतीय बाजार में पूर्ण सेवा प्रदान करने वाली विमानन कंपनी की लागत किफायती विमानन कंपनियों से करीब 50 फीसदी ज्यादा है। ऐसे में वे लागत घटाने के बजाय किराये में कमी से मुकाबला करने का प्रयास करते हैं।' विमानन कंपनी के बेड़े की योजना पर नजर रखने वाले सूत्रों का कहना है कि कंपनी ने 50 नैरो-बॉडी ए 320 और ए 321 विमानों के ऑर्डर दिए हैं, वहीं उसने एयरबस से कहा है कि 10 विमानों की आपूर्ति पूरी तरह से इकनॉमी श्रेणी की सुविधा वाली की जाए। इन विमानों में 180 सीटें होती है जबकि तीन श्रेणियों के कैबिन होने से सीटों की संख्या घटकर 164 रह जाती है। सूत्रों ने बतया कि विस्तारा इन विमानों का परिचालन छोटे और मझोते शहरों में करेगी जहां प्रीमियम क्लास के सीटों की मांग अपेक्षाकृत कम होती है। हालांकि अभी तक की योजना के मुताबिक कंपनी सभी विमानों में उड़ान के दौरान खाना मुहैया कराना जारी रखेगी। विस्तारा की प्रवक्ता ने इस योजना की पुष्टि की लेकिन स्पष्ट किया कि इन विमानों के यात्रियों को उड़ान के दौरान खाना मुहैया कराया जाएगा। उन्होंने कहा, 'विमान की सीटिंग व्यवस्था में बदलाव से कारोबार मॉडल को लेकर किसी तरह का भम्र नहीं होगा। हमारी सभी उड़ानों में पूर्ण-सेवा मुहैया कराई जाएगी।'

विस्तारा की रणनीति का अध्ययन करने वाले विशेषज्ञों ने कहा कि भारत के मार्ग वितरण दिशानिर्देशों (आरडीजी) के अनुसार कंपनियों को क्षेत्रीय मार्गों पर परिचालन करना अनिवार्य होता है, जिसकी वजह से विमानन कंपनियों को हाइब्रिड रणनीति अपनाने को मजबूर होना पड़ रहा है। आरडीजी के तहत घरेलू मार्गों को तीन श्रेणियों में बांटा गया है। श्रेणी -1 में महानगरों के 20 सर्वाधिक मुनाफे वाले रूट शामिल हैं। श्रेणी-2 में पूर्वोत्तर, जम्मू कश्मीर और लक्षद्वीप शामिल हैं। श्रेणी-3 में महानगर से गैर-महागनर जैसे कोयंबत्तूर, कोच्चि, वाराणसी आदि शामिल हैं। विस्तारा जैसी विमानन कंपनियों को बिजनेस और प्रीमियम कैबिन की कम मांग वाले सीटों पर परिचालन करने से लागत बढ़ रही है।

विस्तारा का बढ़ता घाटा

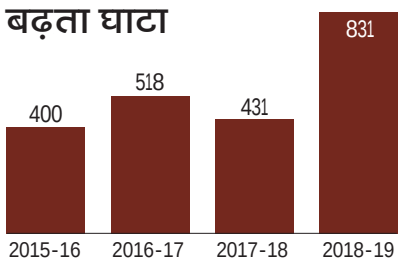

स्रोत : कंपनी

संक्षेप में

म्युचुअल फंडों ने रीट, इनविट में किया बड़ा निवेश

रियल एस्टेट निवेश न्यास (रीट) और बुनियादी संरचना निवेश न्यास (इनविट) जैसे नए निवेश साधनों में अब निवेशक दिलचस्पी लेने लगे हैं। म्युचुअल फंडों ने पिछले साल इन माध्यमों में 12 हजार करोड़ रुपये का भारी-भरकम निवेश किया। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के आंकड़ों के अनुसार, 2019 में म्युचुअल फंडों ने रीट में 670 करोड़ रुपये और इनविट में 11,347 करोड़ रुपये का निवेश किया। पिछले एक साल के दौरान रीट और इनविट में म्युचुअल फंडों की दिलचस्पी तेजी से बढ़ी है। म्युचुअल फंडों ने रीट और इनविट में जनवरी, 2019 में क्रमश: मात्र ?सात करोड़ रुपये और 611 करोड़ रुपये का निवेश किया था। दिसंबर, 2019 में यह निवेश बढ़कर क्रमश: 72.5 करोड़ रुपये और 948 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। *भाषा*

भारतपे करेगी प्रबंधकों, इंजीनियरों की नियुक्ति

फिनटेक मंच भारतपे की योजना इस साल अपनी प्रौद्योगिकी टीम का विस्तार करते हुए 75 इंजीनियरों और परियोजना प्रबंधकों की नियुक्ति करने की है। इसके अलावा कंपनी का इरादा विस्तारित टीम के लिए दिल्ली में एक प्रौद्योगिकी हब बनाने का भी है। कंपनी ने एक बयान में कहा, भारतपे अपनी विस्तारित उत्पाद एवं प्रौद्योगिकी टीम के लिए दिल्ली में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी हब बना रही है। कंपनी की योजना इस साल 75 इंजीनियरों और परियोजना प्रबंधकों की नियुक्ति की है। कंपनी ने कहा कि यह प्रौद्योगिक हब भारतपे के उत्पाद विकास और नए नवोन्मेषण में प्रमुख भूमिका निभाएगा। *भाषा*

ओमान के टिकट रद्द करने पर नहीं लगेगा शुल्क

गोएयर ने ओमान के सुल्तान के निधन के कारण सेवाओं में आ रहे व्यवधान को देखते हुए 14 जनवरी तक ओमान आने-जाने वाली उड़ानों के टिकट रद्द करने अथवा यात्रा की योजना में बदलाव करने पर लगने वाले शुल्क को हटाने की रविवार को घोषणा की। कंपनी ने कहा, ओमान ने सुल्तान के निधन के मद्देनजर शोक की घोषणा की है। इसके कारण राजधानी मस्कट की उड़ानों में अगले तीन दिन तक व्यवधान हो सकता है। गोएयर इस दौरान यात्रा रद्द करने या बदलाव पर लगने वाले शुल्क को पूरी तरह से हटाने की पेशकश करती है। यह पेशकश 14 जनवरी तक मान्य है। *भाषा*

बीएस-6 डीजल मॉडलों की कीमत में कम बढ़ोतरी

2.5 लाख रुपये तक की बढ़ोतरी के अनुमान के उलट टोयोटा ने 39,000 रुपये से लेकर 1,12,000 रुपये तक बढ़ाए दाम

शैली सेठ मोहिले
मुंबई, 12 जनवरी

टोयोटा किर्लोस्कर मोटर और किया मोटर्स ने बीएस-6 डीजल मॉडलों की कीमतों में फिलहाल कम से कम बढ़ोतरी करना तय किया है। इस कदम से टाटा मोटर्स, महिंद्रा ऐंड महिंद्रा (एमऐंडएम) जैसी कंपनियां बीएस-6 मॉडल उतारते समय प्रतिस्पर्धी कीमत की रणनीति अपनाने के लिए प्रोत्साहित हो सकती हैं। इन दोनों कंपनियों के पास डीजल वाहनों का अहम पोर्टफोलियो है।

पिछले हफ्ते बहुद्देश्यीय वाहन की अग्रणी कंपनी टोयोटा ने बीएस-6 मानकों से लैस इनोवा क्रिस्टा उतारने का ऐलान किया, जिसने काफी लोगों को चौंकाया क्योंकि इसकी कीमत प्रतिस्पर्धी रखी गई है। कीमतों में 2.5 लाख रुपये तक की बढ़ोतरी के अनुमान के उलट कंपनी ने कीमतों में 39,000 रुपये से लेकर 1,12,000 रुपये तक की बढ़ोतरी की गई है।

टोयोटा किर्लोस्कर के वरिष्ठ उपाध्यक्ष (बिक्री व ग्राहक सेवा) नवीन सोनी ने कहा, अगर हम इनोवा क्रिस्टा डीजल को बीएस-4 से बीएस-6 में उन्नयन की पूरी लागत का हस्तांतरण किया होता तो खरीदारों के लिए यह वाहन 2 लाख रुपये से 2.5 लाख रुपये तक महंगा हो गया होता। इतनी भारी कीमत बढ़ोतरी से ग्राहक दूर हो जाते। ऐसे में हमने अपने मुख्यालय से इस बारे में इजाजत मांगी कि हमें अपनी बैलेंस शीट पर थोड़ा झटका झेलने की अनुमति दी जाए। सोनी ने स्पष्ट किया, यह पेशकश सीमित अवधि के लिए है। इस मॉडल के लिए बुकिंग शुरू हो गई है, लेकिन अप्रैल से पहले इसकी डिलिवरी होगी और तब तक बीएस-6 ग्रेड वाला ईंधन उपलब्ध होने की उम्मीद है।

कंपनी के जेड एक्स ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन (एटी) 2.8 लीटर मॉडल में अब 2.4 लीटर का मानक इंजन होगा, जिसके परिणामस्वरूप वाहन महज 39,000 रुपये महंगा हुआ है।

ज्यादातर यात्री वाहन निर्माताओं ने बीएस-6 के विभिन्न मॉडलों और उसकी कीमतों का ऐलान नहीं किया है। 1 अप्रैल से भारत के वाहन बाजार में बीएस-6 उत्सर्जन मानक वाले वाहन ही चलेंगे। इंजन के आकार के मुताबिक बीएस-6 में जाने पर डीजल वाहन बीएस-4 मॉडलों के मुकाबले 10 से 15 फीसदी महंगा हो सकता है। पिछले साल अगस्त में भारतीय बाजार में सेल्टॉस (बीएस-4 इंजन) के साथ उतरने वाले कोरियाई वाहन निर्माता की स्थानीय इकाई किया मोटर्स ने पेट्रोल इंजन वाले की कीमत 30,000 रुपये और डीजल वाहनों की कीमत 35,000 रुपये बढ़ाने का ऐलान किया है।

कई मायनों में बाजार में देर से प्रवेश का किया को फायदा मिला है। किया मोटर्स इंडिया के बिक्री व विपणन प्रमुख मनोहर भट्ट ने कहा, दुनिया के बेहतर संयंत्रों में से एक भारत के संयंत्र ने लागत ढांचे में मदद की है।

साथ ही बीएस-4 मॉडलों में निहित स्वार्थ न रहना भी उसके हक में गया है। इस बीच, व्यापक प्रवृत्ति के उलट सेल्टॉस का डीजल मॉडल खरीदारी के लिहाज से आकर्षक बना हुआ है। भट्ट ने कहा, अगस्त से अब तक बेचे गए 50,000 वाहनों से आधे से ज्यादा डीजल वाहन बिके हैं। उन्होंने इसकी वजह पेट्रोल व डीजल ईंधन के बीच अपेक्षाकृत स्थायी अंतर को इसकी वजह बताया। भट्ट ने कहा, डीजल व पेट्रोल वाहनों का फैसला औसत परिचालन व अधिग्रहण लागत से तय होता है। साथ ही दोनों तरह के ईंधन की कीमत का अंतर भी इसमें भूमिका निभाता है।

मारुति समेत कई विनिर्माताओं की तरफ से छोटे डीजल इंजन वाले क्षेत्र से बाहर निकलने की घोषणा भी सेल्टॉस की बिक्री में इजाफे के हक में गई है।

इस बीच, देसी कंपनी डीजल पोर्टफोलियो के वर्चस्व वाली महिंद्रा ऐंड महिंद्रा और टाटा मोटर्स अभी चुप है। एमऐंडएम के अध्यक्ष (ऑटोमोटिव) राजन वढ़ेरा ने कहा, महिंद्रा के डीजल यात्री वाहन की कीमत मौजूदा स्तर से औसतन 6 से 10 फीसदी तक बढ़ सकती है। उन्होंने यह बताने से मना कर दिया कि क्या यह बढ़ोतरी एक बार होगी या फिर चरणों में। उन्होंने कहा, मैं यह रणनीति नहीं बता सकता।

टाटा मोटर्स के प्रबंध निदेशक व सीईओ गुंटर बट्सचेक ने कहा, हमें इस समय बीएस-6 वाहनों की कीमत की घोषणाओं से बहुत ज्यादा मतलब नहीं निकाल सकते। उन्होंने कहा, हमें देखना होगा कि 1 अप्रैल के बाद वास्तविक स्थिति कैसी रहती है जब ज्यादातर विनिर्माता बीएस-6 वाहन उतार देंगे और कीमतों में बढ़ोतरी करेंगे।

उन्होंने कहा, बीएस-6 वाले इनोवा व सेल्टॉस बीएस-4 के माहौल में उतारे गए हैं। बाजार के मौजूदा हालात में इनमें से कुछ कीमत प्रतिस्पर्धी हैं। भारत में यात्री वाहनों की बिक्री लगातार छह तिमाही से घट रही है क्योंकि अर्थव्यवस्था में सुस्ती ने नई कार की खरीद पर असर डाला है।

आईएचएस मार्किट के सहायक उपाध्यक्ष पुनीत गुप्ता ने कहा, टोयोटा, एमऐंडएम, टाटा मोटर्स जैसी कंपनियां डीजल पर ज्यादा निर्भर हैं, लिहाजा ये कंपनियां एक बार में पूरी लागत का भार ग्राहकों पर नहीं डाल सकतीं।

इनोवा क्रिस्टा (डीजल) की कीमतें (लाख रुपये)

मॉडल	बीएस-4	बीएस-6	कीमत का अंतर
जेड एक्स (ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन)	22.63	23.02	39,000
जेडएक्स (मैनुअल ट्रांसमिशन	21.33	22.13	80,000
वीएक्स एमटी	19.47	20.59	1,12,000
जीएक्स एटी	17.66	18.17	51,000
जीएक्स एमटी	16.25	17.17	92,000
जी	15.22	16.14	92,000

स्रोत : कंपनी

आईफिन ने की तीसरे पक्षकार से 1,380 करोड़ रुपये की कर्ज वसूली

सुब्रत पांडा
मुंबई, 12 जनवरी

आईएलऐंडएफएस की एनबीएफसी इकाई आईएलऐंडएफएस फाइनैंशियल सर्विसेज (आईफिन) ने करीब 30 देनदारों और आईएलऐंडएफएस समूह की इकाइयों से नवंबर 2019 तक 1,380 करोड़ रुपये की वसूली की।

आईफिन को आईएलऐंडएफएस के निदेशक मंडल ने रेड इकाई के तौर पर वर्गीकृत किया है, जिसका मतलब यह है कि आईफिन कर्ज देनदारी पूरा नहीं कर सकती, यहां तक कि सुरक्षित वित्तीय लेनदारों को भी नहीं चुका सकती। आईफिन, आईएलऐंडएफएस समूह की प्रमुख होल्डिंग कंपनी में से एक है और उसने तीसरे पक्षकार देनदारों और आईएलऐंडएफएस समूह की कई इकाइयों को उधार दिया है।

मार्च 2019 तक आईफिन की लोनबुक 12,945 करोड़ रुपये की थी, जिसका 96 फीसदी गैर-निष्पादित था। हालांकि आईएलऐंडएफएस बोर्ड की तरफ से एनसीएलएटी के सामने रखी रिपोर्ट के मुताबिक, नवंबर 2019 के आखिर में आईफिन के कर्ज का करीब 97 फीसदी सकल एनपीए था। कुल मूलधन बकाया और तीसरे पक्षकार लेनदेन के पास बकाया 1 अक्टूबर 2018 को 8,356 करोड़ रुपये था। इसके अतिरिक्त आईफिन ने आईएलऐंडएफएस समूह की इकाइयों को कर्ज दिया है और उनमें निवेश भी किया है।

तीसरे पक्षकार देनदारों से मिले 1,310 करोड़ रुपये में से 1,050 करोड़ रुपये उसकी उधारी (ब्याज समेत) से मिले जबकि 260 करोड़ रुपये निवेश से मिले।

बीएस बातचीत

फॉर्मूले के बजाय आकलन के आधार पर हो एनपीए प्रावधान

एनबीएफसी क्षेत्र में नकदी संकट से लेकर आर्थिक मंदी में पिछले एक साल के दौरान श्रेय इन्फ्रास्ट्रक्चर ने कई परेशानी का सामना किया। श्रेय इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनैंस लिमिटेड के वाइस चेयरमैन **सुनील कनोड़िया** ने **ईशिता आयान दत्त** व **नम्रता आचार्य** को दिए साक्षात्कार में बैंकिंग क्षेत्र में हुए सुधार मसलन समय के आधार पर एनपीए के प्रावधान को खत्म करना और लेनदार व देनदार के संबंधों को गोपनीय रखने जैसे मसलों पर विस्तार से बातचीत की। पेश हैं मुख्य अंश...

इस साल के आम बजट से आपकी क्या उम्मीदें हैं?

हमें सरकारी खर्च बढ़ाना होगा ताकि पूंजी निर्माण और आर्थिक रफ्तार बहाल हो। मध्यम से लंबी अवधि के लिहाज से भारत की प्रगति की कहानी अभी भी अक्षुण्न है। ऐसे में अभी भी विदेशी निवेश होगा, लेकिन यह कुछ निश्चित क्षेत्रों तक सीमित होगा। सरकारी खर्च की भूमिका अहम होगी, जिसके चलते पूंजी निर्माण होगा और यह निवेश लागएगा व भारत की आर्थिक रफ्तार को बहाल करेगा। इस साल के बजट में सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए।

क्या देश के वित्तीय सेवा क्षेत्र की परेशानी खत्म हो गई?

मुझे लगता है कि भारत की वित्तीय स्थिति की समस्या के समाधान के लिए टुकड़ों में उठाए गए कदम कारगर नहीं हुए हैं। वित्तीय क्षेत्र अर्थव्यवस्था के लिए अहम होता है। भारत में डेवलपमेंट फाइनैंशियल इंस्टिट्यूशन बनाने की तत्काल जरूरत है। मजबूत क्षमता व प्रबंधन टीम के साथ यह संस्थान लंबी अवधि यानी 20-25 साल के लिए अर्थव्यवस्था को फंडिंग का सहारा दे। दुनिया के करीब-करीब सभी देशों में ऐसे संस्थान हैं, जिसका स्वामित्व सरकार के पास है। भारत में ऐसे संस्थान की दरकार है।

गैर-निष्पादित आस्तियों की स्थिति पर आपकी क्या राय है?

हम जिस तरह से एनपीए को पारिभाषित करते हैं उसकी समीक्षा होनी चाहिए। वैश्विक स्तर पर चाहे अमेरिका हो या यूरोप, बैंकों को नियामक नहीं बताते हैं कि उनका प्रावधान डिफॉल्ट के पहले दिन, 60 दिन, 90 दिन या 180 दिन के आधार पर होना चाहिए। लेनदारों को प्रावधान से पहले परिसंपत्ति/प्रतिभूतियों के अलावा भविष्य के नकदी प्रवाह का आकलन करना चाहिए। हमें ऐसे वैश्विक चलन को भारत में लाना चाहिए। किसी फॉर्मूले के आधार पर प्रावधान नहीं होना चाहिए, इसके बजाय यह आकलन पर आधारित होना चाहिए। साथ ही वैश्विक बैंकों को डिफॉल्टर के नामों का खुलासा करने की अनुमति नहीं है। अगर नाम का खुलासा हो जाता है तो देनदार ने एक ही दिन के डिफॉल्ट क्यों न किया हो, कोई बैंक उसे लोन की पेशकश नहीं करेगा। यह कुछ उसी तरह का मामला है कि किसी व्यक्ति को सर्दी लगी हो और आप उसे वेंटिलेटर पर रख देते हैं। लेनदार व देनदार का संबंध गोपनीय मामला है। हमने ये सिफारिशें एसोचैम के माध्यम से की है।

क्या भविष्य में एनपीए से संबंधित और झटका लग सकता है?

कीमत के लिहाज से एनपीए की ज्यादातर समस्या का समाधान हो गया है। लेकिन एमएसएमई क्षेत्र को पिछले कुछ सालों में काफी रकम मिली है और वहां एनपीए से संबंधित समस्या हो सकती है। इसकी वजह यह है कि किसी अर्थव्यवस्था में छोटी व मझोली कंपनियों का अस्तित्व काफी हद तक बड़े कॉरपोरेट पर निर्भर करता है। ऐसे में कीमत के लिहाज से हम हालांकि एनपीए में ज्यादा बढ़ोतरी नहीं देख रहे हैं, लेकिन एमएसएमई क्षेत्र में दबाव के कारण एनपीए खाते की संख्या ज्यादा हो सकती है। मुझे लगता है कि एमएसएमई क्षेत्र में एनपीए अनुपात दो अंकों में रहेगा।

इस साल दिवालिया संहिता कितनी कामयाब होती दिख रही है?

यह सुनिश्चित करने में न्यायपालिका अहम भूमिका निभाता है कि परिसंपत्ति प्रदर्शन करे और कानूनी प्रक्रिया तेजी से पूरी हो। कानून का मकसद कारोबार की बहाली है, न कि कानूनी अड़चन पैदा करना। साथ ही मैं धारा 29 (ए) के हक में नहीं हूं। आप किसी उद्यमी को खुद की परिसंपत्तियों के लिए बोली लगाने से रोक नहीं सकते जबतक कि वह धोखेबाज न हो। अगर वह धोखेबाज हो तो आप उनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई शुरू कर सकते हैं। लेकिन लेनदारों की समिति के पास यह तय करने का अधिकार होना चाहिए कि किसी उद्यमी को खुद की परिसंपत्तियों के लिए बोली लगाने की अनुमति दी जाए या नहीं।

एफपीआई ने बाजार से निकाले 2,415 करोड़ रु.

अमेरिका और ईरान के बीच तनाव को देखते हुए विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) सतर्कता बरत रहे हैं। जनवरी में अब तक उन्होंने भारतीय पूंजी बाजार से 2,415 करोड़ रुपये निकाले हैं। डिपॉजिटरी के ताजा आंकड़ों के अनुसार, एक जनवरी से 10 जनवरी के दौरान एफपीआई ने शेयरों में 777 करोड़ रुपये डाले, जबकि ऋणपत्रों या बॉन्ड बाजार से 3,192.7 करोड़ रुपये निकाले। इस तरह एफपीआई ने घरेलू पूंजी बाजार से 2,415.7 करोड़ रुपये की शुद्ध निकासी की। एफपीआई इससे पहले सितंबर, 2019 से लगातार हर महीने शुद्ध निवेशक रहे हैं। मॉर्निंगस्टार इन्वेस्टमेंट एडवाइजर इंडिया के वरिष्ठ विश्लेषण प्रबंधक (शोध) हिमांशु श्रीवास्तव ने कहा, भारतीय शेयर बाजार में निवेश करने से पहले विदेशी निवेशक वैश्विक मोर्चे पर चल रही गतिविधियों को नजदीकी से देख रहे हैं और सतर्कता बरते रहे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव ने वैश्विक शेयर बाजारों को प्रभावित किया है। *भाषा*

दूरसंचार कंपनियों की नतीजे पूर्व समीक्षा

डेटा ग्राहक व एआरपीयू से प्रदर्शन रहेगा दमदार

रोमिता मजूमदार
मुंबई, 12 जनवरी

अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में परिचालन के मोर्चे पर दूरसंचार कंपनियों का प्रदर्शन दमदार रह सकता है क्योंकि नए ग्राहक जोड़ने और औसत राजस्व प्रति ग्राहक (एआरपीयू) में सकारात्मक बढ़ोतरी दिख रही है। डेटा के ज्यादा इस्तेमाल और नए ग्राहकों के जुड़ाव को देखते हुए दूरसंचार कंपनियां राजस्व में बढ़ोतरी दर्ज कर सकती हैं, वहीं रिलायंस जियो की तरफ से शुरू किए गए इंटरकनेक्ट यूजेज चार्जेज (आईयूसी) से उन्हें फायदा मिल रहा है। हालांकि देश भर में इंटरनेट पर लगाई गई पाबंदी का असर और टैरिफ में हुई हालिया बढ़ोतरी पर ग्राहकों की प्रतिक्रिया पर नजदीकी नजर होगी।

एमके ग्लोबल के शोध विश्लेषक नवल सेठ ने कहा, दूरसंचार कंपनियां क्रमिक आधार पर वायरलेस राजस्व में सुधार दर्ज कर सकती हैं, जिस पर डेटा ग्राहकों के जुड़ाव, जम्मू-कश्मीर में सेवाओं की बहाली और आईयूसी टॉप-अप वाउचर लागू करने के कारण जियो की तरफ से कुछ वॉयस टैरिफ दूसरी तरफ जाने का असर दिखेगा।

विश्लेषकों ने हालांकि कहा कि तीसरी तिमाही में टैरिफ बढ़ोतरी का मामूली असर होगा क्योंकि ग्राहकों ने टैरिफ बढ़ोतरी से पहले रीचार्ज कराया होगा। सेठ ने कहा, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया के लिए एआरपीयू में अनुमानित सुधार तिमाही दर तिमाही क्रमश: 6 फीसदी और 7 फीसदी रह सकता है। जियो की रफ्तार हालांकि नए शुल्क की वजह से थोड़ी प्रभावित हो सकती है।

आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के शोध विश्लेषक संजेश जैन ने कहा, हमें आशंका है कि वोडाफोन आइडिया एकीकरण पर ग्राहक आधार में 50 लाख की कमी दर्ज कर सकती है, वहीं एयरटेल ग्राहक संख्या में करीब 30 लाख की बढ़ोतरी दर्ज कर सकती है क्योंकि उसे नई कंपनी जियो की तरफ से वॉयस के लिए शुल्क वसूलने और जम्मू-कश्मीर में स्थिति सामान्य होने का फायदा मिल सकता है। हम एयरटेल और वोडाफोन आइडिया के डेटा ग्राहकों में क्रमश: 1.3 करोड़ व 50 लाख की बढ़ोतरी देख सकते हैं।

एयरटेल का भारतीय राजस्व तिमाही दर तिमाही 3 फीसदी (सालाना आधार पर 7.2 फीसदी) बढ़कर 150 अरब रुपये रहने की उम्मीद है, जिसकी अगुआई मुख्य रूप से मोबाइल सेगमेंट करेगा। इसके अलावा एबिटा तिमाही दर तिमाही 2.1 फीसदी घटकर 62 अरब रुपये रहने की संभावना है, जो बिक्री के सामान्य होने, सामान्य व प्रशासनिक लागत के कारण होगा। वोडाफोन आइडिया का राजस्व तिमाही आधार पर 1.5 फीसदी बढ़कर 110 अरब रुपये पर पहुंच सकता है, जो बेहतर एआरपीयू के कारण होगा।

मॉर्गन स्टैनली के इक्विटी विश्लेषक पराग गुप्ता ने कहा, जियो का एआरपीयू बढ़कर 123 रुपये (दूसरी तिमाही में 120 रुपये) रहने की संभावना है, जो तिमाही दर तिमाही राजस्व में 9 फीसदी की बढ़ोतरी के तौर पर नजर आएगा। हमें उम्मीद है कि एबिटा मार्जिन तिमाही आधार पर सुधरेगा, जिसे राजस्व की रफ्तार और कम इंटरकनेक्ट लागत का फायदा मिलेगा, जिसकी आंशिक भरपाई नेटवर्क लागत में हुई बढ़ोतरी कर देगा। आईयूसी शुल्क हालांकि अब हर कंपनी वसूल रही है, लेकिन पुरानी दूरसंचार कंपनियों को इस तिमाही में आईयूसी का अहम फायदा शायद नहीं दिखेगा, लेकिन टैरिफ में बढ़ोतरी से आंकड़े सुधरेंगे।

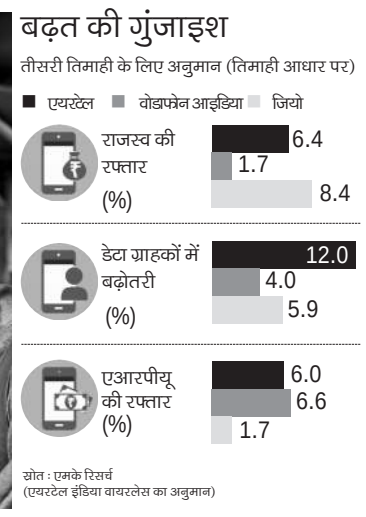

स्रोत : एमके रिसर्च
(एयरटेल इंडिया वायरलेस का अनुमान)

देश के हीरा निर्यात में आई तेज गिरावट

बदलते रुझान और सीमा शुल्क विभाग द्वारा उठाए गए कदमों से कमजोर हुआ निर्यात

राजेश भयानी
मुंबई, 12 जनवरी

वित्त वर्ष 20 के पहले आठ महीने में तराशे हीरों के निर्यात में 19.4 प्रतिशत की गिरावट आई है। इससे रत्न और आभूषणों का कुल निर्यात 5.8 प्रतिशत गिरकर 25.5 अरब डॉलर रह गया है। इस बास्केट में तराशे और विभिन्न रत्नों का प्रदर्शन काफी फीका रहा। हालांकि सोने और चांदी के गहनों के साथ-साथ कृत्रिम रत्नों में सकारात्मक रुख नजर आया है। उद्योग के सूत्रों का कहना है कि प्रमुख उपभोक्ता देशों में आर्थिक मंदी, बैंकों के साथ वित्तीय मसले चिंताजनक होने और कच्चा माल आयात करने के प्रति सीमा शुल्क विभाग का प्रतिकूल रुख उद्योग के लिए बड़ी अड़चन है।

प्रयोगशाला में तैयार किए गए हीरों की बढ़ती लोकप्रियता और युवा उपभोक्ताओं की बदलती पसंद की वजह से निर्यात में गिरावट आ रही है। पिछले वित्त वर्ष के पहले आठ महीने (अप्रैल से नवंबर) की तुलना में वित्त वर्ष 20 की समान अवधि के दौरान तराशे हीरों का निर्यात 19.40 प्रतिशत गिरकर 13.27 अरब डॉलर रह गया। जहां तक विभिन्न रत्नों के निर्यात की बात है, तो यह 20.73 प्रतिशत गिरकर 26.3 करोड़ डॉलर रहा।

अप्रैल के बाद से सीमा शुल्क विभाग तीन अधिसूचनाएं जारी कर चुका है जिन्होंने निर्यात को फीका करते हुए धारणा को प्रभावित कर दिया। जून में जारी की गई अधिसूचना शुल्क भुगतान किए बिना आयात बकाये का लाभ लेने से संबंधित थी। मई में सीमा शुल्क विभाग ने कच्चे हीरों के आयात और निर्यात के मूल्यों की संदिग्ध गलत घोषणाओं के संबंध में कई प्रकार के खुलासे करने के लिए कहा था। मई की अधिसूचना के बाद से कच्चे हीरों का आयात करने वाले निर्यातक खेप नहीं उठा पाए थे। इन सब मसलों ने इस क्षेत्र में निर्यात को नुकसान पहुंचाया है।

रत्नों का निर्यात भी गिरा

- तराशे हीरे और रत्नों के निर्यात का प्रदर्शन रहा फीका
- सोने-चांदी के गहनों और कृत्रिम रत्नों का सकारात्मक रुझान
- अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध का भी फायदा नहीं उठा सका उद्योग
- पिछले वित्त वर्ष की तुलना में वित्त वर्ष 2020 में तराशे हीरों का निर्यात 19.40 प्रतिशत गिरकर 13.27 अरब डॉलर रहा
- इस अवधि में विभिन्न रत्नों का निर्यात 20.73 प्रतिशत गिरकर 26.3 करोड़ डॉलर रहा

निर्यातकों को बजट से आस

परिषद को अब वर्ष 20-21 के लिए 1 फरवरी को पेश किए जाने वाले आम बजट से भी राहत की उम्मीद है। परिषद ने कारोबार सुगमता से संबंधित उपाय करने की मांग की है।

निर्यात में इस गिरावट के लिए क्रिसमस की मांग को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। यह मांग शायद जारी न रह पाए और वित्त वर्ष 20 रत्नाभूषण निर्यातकों के लिए दूसरा फीका वर्ष साबित हो। हीरों और विभिन्न रत्नों के निर्यात में यह गिरावट उद्योग के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात है।

कोलिन शाह ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि सरकार इस महत्त्वपूर्ण क्षेत्र से होने वाले निर्यात में गिरावट पर नजर रखे हुए है जो बड़ी संख्या में रोजगार देता है। उन्होंने कहा कि आने वाले बजट से हमें उम्मीद है कि सरकार हमारे निर्यात में गिरावट पर ध्यान दे रही है तथा सोने, प्लैटिनम और हीरे पर शुल्क कटौती, सीमा शुल्क के मसलों से संबंधित करोबार सुगमता, जीएसटी इनपुट क्रेडिट विवाद के समाधान और नई प्रगतिशील एसईजेड नीति के हमारे लंबे अनुरोधों के संबंध में कुछ राहत देगी। वित्त वर्ष 20 के शुरुआत में सीमा शुल्क विभाग की ओर से जारी अधिसूचनाओं और परिपत्रों ने काफी परेशानी पैदा कर दी थी जिससे वास्तविक निर्यात को नुकसान होना शुरू हो गया। इसके अलावा ये इकाइयां पहले ही दो सालों से कार्यशील पूंजी की कमी का सामना कर रही हैं। उद्योग अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध का लाभ भी नहीं उठा पाया है। कई निर्यातक अपना आधार चीन से भारत में स्थानांतरित करना चाहते थे, लेकिन माना जाता है कि उन्होंने भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र की नीतियों को अपने लिए उपयुक्त नहीं पाया।

निर्यात में महत्त्वपूर्ण रूप से योगदान करने वाला एक अन्य खंड स्वर्णाभूषण होता है और इसका निर्यात 5.3 प्रतिशत की हल्की-सी बढ़त के साथ 8.66 अरब डॉलर रहा है। सरकारी नीतियों को कड़ा करने जैसी प्रतिकूल स्थिति और स्कोशिया बैंक के बंद होने के कारण ऐसा हुआ। इसने निर्यातकों की सेवाओं को प्रभावित कर दिया। इस मामूली वृद्धि का अन्य कारण भुगतान किए गए आयात शुल्क की जांच के लिए सीमा शुल्क विभाग द्वारा पूरी आपूर्ति शृंखला का विवरण मांगे जाने के बाद शुल्क ड्रॉबैक के दावे में मुश्किल आना भी है।

उद्योग अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध का भी फायदा नहीं उठा सका था, जबकि चीन में केंद्र रखने वाली कई कंपनियां भारत में स्थानांतरित होना चाहती थी, लेकिन निर्यात क्षेत्रों में इकाइयों के लिए भारत के नियम उनके लिए उपयुक्त नहीं थे।

अलबत्ता इस मसले पर ध्यान देने के लिए रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्द्धन परिषद (जीजेईपीसी) ने बहु-आयामी कार्य योजना तैयार की है। परिषद के वाइस चेयरमैन कोलिन शाह ने कहा कि देश का रत्न एवं आभूषण निर्यात मुख्य रूप से अमेरिका, यूएई और हॉन्ग कॉन्ग में केंद्रित रहता है। उन्होंने कहा कि हमने निर्यात बढ़ाने के लिए नए बाजारों की पहचान की है। तराशे हीरों के लिए रूस, ब्राजील, ब्रिटेन, वियतनाम, सिंगापुर, फ्रांस, इटली और जर्मनी जैसे देशों पर ध्यान दिया जा सकता है। स्वर्णाभूषण उत्पाद निर्यात के लिए ब्रिटेन, फ्रांस, कतर, ऑस्ट्रेलिया और थाईलैंड के बाजार तलाशे जा सकते हैं। श्रमिकों का बढ़ता कौशल, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल में इजाफा और नई पीढ़ी के उपभोक्ताओं के लिए उत्पाद नवोन्मेष ऐसी अन्य रणनीतिक चीजें हैं जिन पर निर्यातकों को विचार करना चाहिए।

परिषद ने निर्यातकों को अमेरिका को सोने, चांदी और नकली गहनों का निर्यात बढ़ाने का भी सुझाव दिया है। चीन द्वारा अमेरिका को किए जाने वाले सोने, चांदी और नकली गहनों के निर्यात में योगदान क्रमशः 13 प्रतिशत, 20 प्रतिशत और 73 प्रतिशत रहता है।

फसल नुकसान से बढ़े घरेलू धान के दाम

वीरेंद्र सिंह रावत
लखनऊ, 12 जनवरी

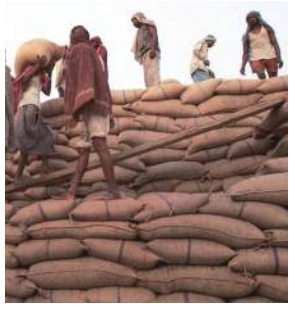

- बासमती का सबसे बड़ा खरीदार है ईरान, वर्ष 2018-19 में करीब 1.5 अरब डॉलर रहा निर्यात

अमेरिका-ईरान के बीच मौजूदा टकराव के कारण अटकी खेपों के संबंध में भारत के बासमती निर्यातकों को गतिरोध का सामना करना पड़ रहा है। इससे गैर-बासमती धान के दामों में मजबूती आ रही है। पिछले साल की भारी बारिश और इसके परिणामस्वरूप प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों में बाढ़ के बाद फसल क्षति की खबरों से कुछ स्थानीय बाजारों में दामों में इजाफा हो रहा है।

ईरान को भेजी जाने वाली बासमती की खेपों को कुछ समय के लिए रोकने संबंधी अखिल भारतीय चावल निर्यातक संघ (एआईआरईए) की सलाह के बाद बासमती के कारोबार पर आशंका के बादल छा गए हैं। इसका असर इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज (आईसीईएक्स) के दामों में गिरावट के रूप में नजर आया है।

ईरान भारतीय बासमती चावल का सबसे बड़ा खरीदार है और वर्ष 2018-19 के दौरान करीब 1.5 अरब डॉलर की खेप भेजी गई थी।

हालांकि चौबेपुर मंडी में गुरुवार को गैर-बासमती धान (ग्रेड 3) का भाव 2,440 रुपये प्रति क्विंटल रहा जो एक महीना पहले 9 दिसंबर, 2019 के भाव 2,310 रुपये प्रति क्विंटल की तुलना में 5.62 प्रतिशत अधिक है। इसी तरह कानपुर में धान का भाव 2,350 रुपये प्रति क्विंटल रहा, जबकि 9 दिसंबर, 2019 को भाव 2,150 रुपये प्रति क्विंटल था। इस तरह एक महीने के दौरान दामों में 9.30 प्रतिशत का इजाफा हुआ है।

अन्य बाजारों में भी यही रुख नजर आया है जो यह बताता है कि धान की फसल क्षति के परिदृश्य से गैर-बासमती किस्म के घरेलू दामों को मदद मिली है। मुंबई के चावल व्यापारी और निर्यातक देवेंद्र वोरा ने बिज़नेस स्टैंडर्ड को बताया कि घरेलू धान के दाम पहले ही नीचे आ चुके हैं और आगे चलकर इनमें इजाफा होने की उम्मीद है।

राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान (एनआरआरआई) के प्रमुख वैज्ञानिक डॉ. विश्वजित मंडल के अनुसार खरीफ सत्र 2019-20 के दौरान भारत के कुछ हिस्सों में असामान्य बारिश हुई। इसके परिणामस्वरूप चावल उत्पादन नौ करोड़ टन रहने की उम्मीद है जो पिछले साल के अनुमानित उत्पादन 10.2 करोड़ टन की तुलना में 12 प्रतिशत कम है।

इसके अलावा नवंबर 2019 के दौरान लगातार बारिश की वजह से भारी बाढ़ के कारण खरीफ फसल वाले क्षेत्रों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। इनमें महाराष्ट्र, कर्नाटक, पंजाब, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश जैसे प्रमुख चावल उत्पाद क्षेत्र भी शामिल हैं। इस बीच कुछ राज्यों में हाल ही में बेमौसम बारिश के भी समाचार मिले हैं जिनमें ओडिशा के तटीय क्षेत्र भी शामिल है जिससे मौजूदा खरीफ विपणन सीजन 2019-20 के दौरान धान की खरीद पर असर पड़ रहा है।

स्थानीय खबरों में दावा किया गया है कि ओडिशा के कुछेक जिलों में परंपरागत मिलें बारिश के लिहाज से उचित भंडारण क्षमता के अभाव का हवाला देते हुए मंडियों से धान नहीं उठा रही हैं। मौजूदा सत्र में ओडिशा 60 लाख टन धान खरीद का लक्ष्य रखकर चल रहा है जिसमें से 1 जनवरी, 2020 तक केवल 12 लाख टन की ही खरीद हो सकी है, जबकि पंजाब और उत्तर प्रदेश में क्रमशः एक करोड़ टन और 27 लाख टन से ज्यादा की खरीद हो चुकी है। हालांकि भारती खाद्य निगम (एफसीआई) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि बड़ी मात्रा में धान खरीद की जा चुकी है। खास तौर पर उत्तरी राज्यों में। इसके अलावा ओडिशा समेत शेष राज्यों में हाल के दिनों में खरीद प्रक्रिया प्रभावित करने वाली बारिश की कोई सूचना नहीं है। ओडिशा में खरीद मुख्य रूप से राज्य सरकार की एजेंसियों द्वारा संचालित की जाती है।

इस बीच कारोबार के विश्लेषक अजय केडिया के अनुसार खाड़ी संकट को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के नरम रुख के बाद बासमती धान के दामों में दो प्रतिशत तक की उछाल आई है।

सहालग का सीजन, आभूषण खरीदार नदारद

सिद्धार्थ कलहंस
लखनऊ, 12 जनवरी

सहालग के सीजन में सराफा बाजार में सन्नाटा पसरा हुआ है। अमेरिका-ईरान युद्ध की आशंका और बीते 10 दिनों से सोने के दामों में हो रही बढ़ोतरी के चलते इस पीक सीजन में खरीदार बाजार से गायब हैं। राजधानी लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, आगरा सहित प्रदेश के सभी प्रमुख शहरों में सराफा बाजार का यही हाल है।

लखनऊ के सराफा कारोबारियों का कहना है कि बीते कई वर्षों में बाजार में इस तरह सन्नाटा कभी नहीं देखा गया है। कारोबार घटकर एक चौथाई रह गया है। सामान्य दिनों के बराबर भी कारोबार सहालग के इस सीजन में नहीं मिल पा रहा है। उत्तर भारत में सहालग 15 जनवरी के बाद से शुरू हो रही है। सहालग के पहले के 15 दिनों से लेकर होली तक सराफा बाजार के लिए पीक सीजन माना जाता है। इन दिनों सामान्य से दोगुना कारोबार होता है। राजधानी के सराफा कारोबारियों का कहना है कि ब्रांडेड शोरूम से लेकर छोटे व कम कीमत के गहने बेचने वालों तक के यहां खरीदारों का टोटा है।

दरअसल ईरान के साथ अमेरिका की तनातनी के बाद पिछले 10 दिनों में सोने कीमतों में दो से तीन हजार रुपये का इजाफा हुआ है। आने वाले दिनों में इसके और भी ऊपर जाने का अंदेशा है। लखनऊ के सराफा कारोबारी अनिल वर्मा का कहना है कि सहालग के चलते बड़ी तादाद में लोगों ने गहनों का स्टॉक जोड़ लिया था, अब पैसे फंस गए हैं और ग्राहक आ नहीं रहे हैं। उनका कहना है कि जीएसटी और दूसरी बंदिशों के कारण गहनों की बिलिंग डिलिवरी वाले दिन ही करनी होती है। ग्राहकों को डिलिवरी वाले दिन का रेट लगाना होता है जिसके चलते अग्रिम बुकिंग भी नहीं हो रही है। वर्मा का कहना है कि पिछले एक सप्ताह में कम से कम 100 करोड़ रुपये का नुकसान अकेले लखनऊ के सराफा बाजार को हुआ है।

लखनऊ के अलावा पूर्व में वाराणसी और पश्चिम में आगरा का सराफा बाजार है। लेकिन इस बार सहालग में इन शहरों में भी धंधा मंदा ही जा रहा है। राजधानी के पुराने सराफा कारोबारी अमित गुप्ता का कहना है कि सहालग के सीजन में सराफा कारोबारी दिहाड़ी पर कारीगर रखते थे लेकिन इन दिनों अपने कर्मचारियों के लिए ही काम नहीं है। गुप्ता के मुताबिक गुरुवार को सोने के दाम राजधानी में 40,900 रुपये प्रति दस ग्राम था और आशंका है कि यह और भी बढ़ेगा। सहालग की खरीदारी के नाम पर अगर कुछ हो रहा है तो वह पुराने गहनों की अदला-बदली या उन्हें नए सिरे से बनवाने का काम आ रहा है। सहालग में आमतौर पर लखनऊ में हर रोज 50 करोड़ रुपये आभूषण बिकते हैं जो इस बार महज 15 करोड़ रुपये पर सिमट गया है।

सोने के साथ ही चांदी के दामों में भी तेजी आने से इसके भी ग्राहक घटे हैं। छोटे बाजारों में तो चांदी की खरीदारी में कुछ तेजी है लेकिन वह भी बड़ी मात्रा में नहीं हो रही है।

सराफा बाजार

- अमेरिका-ईरान के तनाव के बाद सोने के दाम चढ़े
- इस सीजन में 50 करोड़ का कारोबार 15 करोड़ में ही सिमटा
- पिछले एक सप्ताह में कम से कम 100 करोड़ रुपये का नुकसान अकेले लखनऊ के सराफा बाजार को हुआ

12 प्रमुख बंदरगाहों ने 5,240 लाख टन माल की ढुलाई की

देश के प्रमुख 12 प्रमुख बंदगाहों पर माल ढुलाई चालू वित्त वर्ष के पहले 9 माह अप्रैल से दिसंबर में 0.98 फीसदी बढ़कर 5,240.2 लाख टन पर पहुंच गई। भारतीय बंदरगाह संगठन (आईपीए) ने इसकी जानकारी दी। इन बंदरगाहों ने पिछले साल 5,189.3 लाख टन माल की ढुलाई की थी। इन प्रमुख 12 बंदरगाहों में दीनदयाल (पूर्ववर्ती कांडला), मुंबई, जेएनपीटी, मोर्मुगाव, न्यू मेंगलूर, कोचिन, चेन्नई, कमरजार (पूर्ववर्ती एन्नोर), पारादीप, वी.ओ. चिदंबरनार, विशाखापत्तनम और कोलकाता (हल्दिया समेत) शामिल हैं। *भाषा*

नेपाल की चाय के आयात से लुढ़के दार्जिलिंग चाय के दाम

अभिषेक रक्षित
कोलकाता, 12 जनवरी

नेपाल चाय की निरंतर आवक और उपलब्धता ने प्रतिष्ठित दार्जिलिंग चाय के दामों पर सीधा असर डाला है। एक साल के दौरान इसके दामों में 20 से 25 प्रतिशत तक की गिरावट आई है। नेपाल से आयातित परंपरागत किस्म वाली चाय को आम तौर पर हिमालय की चाय के रूप में जाना जाता है। स्वाद और सुगंध में यह दार्जिलिंग चाय का विकल्प होती है, लेकिन उत्तरी पश्चिम बंगाल की पहाड़ियों की चाय की तुलना में यह 50 प्रतिशत से भी ज्यादा सस्ती होती है।

नेपाल की इलाम चाय के कारण दार्जिलिंग चाय उद्योग को हर साल करीब 120 करोड़ रुपये का नुकसान

उद्योग के अधिकारियों का आरोप है कि खास तौर पर खुली पत्ती वाले बाजार में लगे खरीदार इस चाय की खरीद कर रहे हैं और बेईमान व्यापारियों का एक वर्ग नेपाल की चाय को दार्जिलिंग चाय के रूप में पेश कर रहा है जो भौगोलिक संकेत ट्रेडमार्क से संरक्षित है। कानूनी तौर पर मुक्त व्यापार समझौते के तहत भारत में कोई भी नेपाल से स्वतंत्र रूप से चाय का आयात कर सकता है। हालांकि थोक बिक्री में दार्जिलिंग चाय के दाम प्रति किलोग्राम औसतन 320 रुपये से 360 रुपये के बीच रहते हैं, लेकिन नेपाल की परंपरागत किस्म वाली चाय के दाम इससे आधे भी नहीं रहते। वर्ष 2019 में दार्जिलिंग चाय के दामों में प्रति किलोग्राम 70 से 80 रुपये तक की गिरावट आई है।

दार्जिलिंग में बागान संभाल रही चाय कंपनी के एक अधिकारी ने कहा कि उपभोक्ता के लिए यह समझना संभव नहीं होता है कि वह नेपाल की चाय पी रहा है या दार्जिलिंग चाय क्योंकि ये दोनों स्वाद और सुगंध में इस कदर एक जैसी होती हैं। कुछ बेईमान विक्रेता इसी आधार पर नेपाल चाय को दार्जिलिंग चाय के रूप में पेश कर देते हैं। उद्योग के सूत्रों ने कहा कि हर साल करीब 1.6 करोड़ किलोग्राम नेपाल चाय भारत में आती है जिसमें से लगभग 30 से 40 लाख किलोग्राम चाय परंपरागत किस्म वाली होती है। चाय की यह किस्म दार्जिलिंग की उपज को प्रभावित करती है। स्वाद, सुगंध और दिखने के लिहाज से नेपाल की खास तौर पर इलाम किस्म वाली चाय दार्जिलिंग चाय की निकटतम विकल्प होती है। यहां तक कि विशेषज्ञों और पारखियों के लिए भी इन दोनों के बीच अंतर करना मुश्किल रहता है। उद्योग के अधिकारी ने कहा कि दार्जिलिंग चाय को लेकर खास तौर पर घरेलू बाजार में बुरी परिपाटी चलती आ रही है जिससे दार्जिलिंग चाय के दामों में गिरावट आ रही है। पश्चिम बंगाल और असम में गुडरिक ग्रुप के कई बागान हैं और वह इन क्षेत्रों से शीर्ष गुणवत्ता वाली चाय का उत्पादन करती है। गुडरिक के लिए दार्जिलिंग चाय के दामों में 18 प्रतिशत तक की गिरावट आई है, जबकि असम और डुआर्स के दामों में क्रमशः तीन और 1.5 प्रतिशत तक का इजाफा हुआ है। इसी प्रकार जहां एक ओर नेपाल की अधिकांश चाय कीटनाशक और अवशिष्ट रहित प्रमाण-पत्र के बिना होती है, वहीं दूसरी ओर दार्जिलिंग के 87 बागान की 70 प्रतिशत चाय प्रमाणित उपज होती है। मोटे तौर पर अनुमान लगाया गया है कि दार्जिलिंग चाय के रूप में नेपाल की इलाम चाय के कारण दार्जिलिंग चाय उद्योग को (थोक और खुदरा बिक्री समेत) हर साल करीब 120 करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है।

ई-कॉमर्स के नियमन पर मिश्रित प्रतिक्रिया

पीरजादा अबरार और नेहा अलावधी
बेंगलूरु/नई दिल्ली, 12 जनवरी

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) द्वारा ई-कॉमर्स फर्मों के स्वनियमन के सुझाव पर उद्योग जगत से मिली जुली प्रतिक्रिया आई है। सीसीआई ने 'भारत में ई-कॉमर्स पर बाजार अध्ययन' नाम से एक अध्ययन बुधवार को जारी किया था।

दिल्ली की टेकलेजिस एडवोकेट्स ऐंड सोलिसिटर्स के मैनेजिंग पार्टनर सलमान वारिस का कहना है कि इस रिपोर्ट का सबसे महत्त्वपूर्ण हिस्सा स्व नियामक कदमों को लेकर है। उन्होंने कहा, 'सीसीआई का यह प्रस्ताव विवादास्पद हो सकता है क्योंकि इसमें ई कॉमर्स कंपनियों को अपने ही मामले में न्यायधीश बना दिया गया है और उन्हें अनुचित व्यवहार के समाधान के मामले में स्वनियमन की अनुमति देने की मेरिट को लेकर उचित सवाल उठते हैं, जो उसी कंपनी द्वारा खुद किया गया हो।'

कैट के महासचिव प्रवीन खंडेलवाल ने कहा, 'हमने देखा है कि स्वनियमन काम नहीं करता क्योंकि इसकी कोई कानूनी बाध्यता या जवाबदेही नहीं होती।' उन्होंने कहा, 'भारत का फिल्म उद्योग इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। उसमें स्वनियमन है, लेकिन कोई उसका पालन नहीं करता है। ई-कॉमर्स बाजार को ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा बहुत ज्यादा बिगाड़ा जा रहा है, वहां स्वनियमन का कोई मतलब नहीं है। सरकार को इनके लिए नियम बनाना चाहिए।'

सीसीआई की रिपोर्ट में ई-कॉमर्स कंपनियों के आंकड़ों की बात की गई है, जिसमें उन फैसलों के व्यापक और सूक्ष्म आंकड़े होंगे, जिनका असर पड़ता है।

सिरिल अमरचंद मंगलदास में पार्टनर अवंतिका कक्कड़ के मुताबिक आयोग ने उद्योग के स्वनियमन का सुझाव दिया है, जिसमें सर्च रैंकिंग के स्पष्ट मानदंड तय किए गए हैं। कक्कड़ ने ने कहा, 'खासकर जहां कमीशन से प्लेटफार्म पर रैंकिंग तय होती है। इसे लेकर आयोग ने साफ नीति का सुझाव दिया है। साथ ही अपारदर्शिता व पारदर्शिता में संतुलन पर जोर है, जिससे विभिन्न हिस्सेदारों के बीच टिकाऊ संतुलन बना रह सके।'

कक्कड़ ने कहा, 'आयोग की एक दिलचस्प सिफारिश कारोबारी समझौते के नियम व शर्तों को लेकर है। इसके बारे में कहा गया है कि नियम में बदलाव नोटिस अवधि खत्म होने पर ही लागू किया जाना चाहिए। और यह अवधि बदलाव की प्रकृति के अनुरूप होना चाहिए।' उन्होंने कहा कि आयोग ने छूट और उसके मानकों को लेकर स्पष्टता की बात कही है।

स्वनियमन के प्रस्ताव से नाखुश छोटे उद्यमी

- उद्योग के जानकारों का कहना है कि अपने ही अनुचित व्यवहार के स्वनियमन का अधिकार देने पर सवाल
- छोटे कारोबारियों के मुताबिक फिल्म उद्योग में स्वनिमयन, लेकिन कोई नहीं मानता
- वहीं कुछ का कहना है कि स्वनियम के साथ पारदर्शिता संबंधी नियम का सुझाव है, जो साबित होगा प्रभावी

एमेजॉन के प्रमुख की भारत यात्रा का विरोध करेंगे ट्रेडर

हजारों की संख्या में भारत के छोटे कारोबारी एमेजॉन डॉट कॉम इंक के संस्थापक जेफ बेजोस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की योजना बना रहे हैं। बेजोस अगले सप्ताह कंपनी की बैठक में हिस्सा लेने व सरकारी अधिकारियों के साथ बैठक करने भारत आ रहे हैं।

तीन सूत्रों ने बताया कि बेजोस नई दिल्ली में आयोजित एमेजॉन के एक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, जिसका मकसद छोटे और मझोले उद्यमों को जोड़ना है। इस मामले से जुड़े एक सूत्र ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य अधिकारियों के साथ उनकी बैठक की भी योजना बन रही है, जिसमें ई-कॉमर्स को लेकर चर्चा होगी। बेजोस की यात्रा की तिथि और वह कितने समय दिल्ली में रहेंगे, यह अभी साफ नहीं है। यात्रा की पुष्टि को लेकर पूछे गए सवाल पर एमेजॉन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। प्रधानमंत्री कार्यालय ने भी इसके बारे में कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं दी है। वहीं 7 करोड़ किराना दुकानों का प्रतिनिधित्व करने वाले कैट ने कहा है कि वह देश में बेजोस के खिलाफ 300 शहरों में प्रदर्शन करेगा। *रॉयटर्स*

मुंबई मेट्रो के लिए टीओटी मॉडल

अमृता पिल्लई
मुंबई, 12 जनवरी

मुंबई मेट्रोपोलियन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी (एमएमआरडीए) परिचालन में आने के बाद अपनी मेट्रो लाइनों को टोल ऑपरेट ट्रांसफर मॉडल के तहत डालने पर विचार कर रहा है। यह कवायद वैश्विक पेंशन फंडों को आकर्षित करने के लिए की जा रही है।

कुल 337 किलोमीटर लंबे मेट्रो नेटवर्क की योजना में दो लाइनों 2ए और 6 के इस साल चालू होने की संभावना है। एमएमआरडीए के मेट्रोपोलिटन कमिश्नर आरए राजीव को उम्मीद है कि परिचालन वाली लाइनों का आंशिक रूप से मुद्रीकरण किया जा सकेगा और शेष लाइनों के निर्माण के लिए धन जुटाया जा सकेगा।

राजीव ने कहा, 'हम पेंशन व सॉवरिन फंडों के साथ समझौता कर रहे हैं। कनाडा पेंशन फंड जैसे इन पेंशन फंडों ने 30 साल के लिए इसे लेने में दिलचस्पी दिखाई है, जहां सभी राजस्व किराया व गैर किराया, इस अवधि के लिए उन्हें दे दिया जाएगा। हम सिर्फ इस राजस्व के 70 प्रतिशत का मुद्रीकरण इन फंडों से करेंगे।'

बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए शहर 1.4 से 1.5 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाएं विकसित कर रहा है। इनमें मुंबई ट्रांसहार्बर लिंक (एमटीएचएल), पूरे शहर में मेट्रो नेटवर्क बनाना, जिसमें परिचालन वाली मेट्रो लाइन भी है, शामिल है। इन परियोजनाओं के बड़े हिस्से पर एमएमआरडीए काम करा रहा है। मेट्रोपोलिटन कमिश्नर ने कहा, 'एमएमआरडीए मॉडल ऐसा है कि इसमें राज्य और केंद्र से बुनियादी ढांचा विकास के लिए फंड नहीं लिया जाएगा।' उन्होंने कहा कि मेट्रो नेटवर्क की योजना के लिए ही 30,000 करोड़ रुपये के वित्तपोषण के लिए द्विपक्षीय व बहुपक्षीय वित्तपोषण एजेंसियों से बात चल रही है। बहरहाल अब से 2026 तक की महत्त्वाकांक्षी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए एमएमआरडीए को अभी और 80,000 करोड़ रुपये की जरूरत होगी।

राजीव ने कहा कि पेंशन फंडों के साथ विकास प्राधिकरण के पास भी करीब 14,000 से 15,000 करोड़ रुपये हैं। प्राधिकरण को सालाना 500-600 करोड़ रुपये राज्स सरकार से भी स्टांप शुल्क में हिस्सेदारी के रूप में मिलने की उम्मीद है, जो आसपास की परियोजनाओं पर लगेगा। इसके अलावा सालाना 1,000 करोड़ रुपये निर्माणाधीन रियल एस्टेट परियोजनाओं पर लगने वाले विकास शुल्क के रूप में आने की संभावना है। राजीव ने कहा, 'स्टांप शुल्क 2015 से लागू है, जबकि विकास शुल्क पिछले साल से लागू है।' उन्हें उम्मीद है कि बढ़ी हुई राशि जल्द मिलने लगेगी।

विकास प्राधिकरण भूमि बैंक के दीर्घावधि पट्टा व्यवस्था से भी धन जुटाने पर विचार कर रहा है, जिससे इन परियोजनाओं का वित्तपोषण हो सके। पट्टे पर जमीन की नीलामी के माध्यम से पिछले साल 2,000 करोड़ रुपये जुटाए गए थे।

मुद्रीकरण योजना

6,419 करोड़ रुपये मेट्रो लाइन 2 ए की परियोजना लागत

6,208 करोड़ रुपये मेट्रो लाइन 7 की परियोजना लागत

60-70 प्रतिशत निवेश की राशि टीओटी मॉडल से निकालने पर विचार कर रहा है एमएमआरडीए, इस राशि का इस्तेमाल शेष मेट्रो लाइनों के वित्तपोषण के लिए

कोयला आयात के लिए रूस, मंगोलिया से बात

भारत कोकिंग कोयले के आयात के लिए मंगोलिया तथा रूस से बातचीत कर रहा है। इससे देश की कोकिंग कोयले के आयात को कुछ देशों पर निर्भरता को कम किया जा सकेगा। केंद्रीय इस्पात तथा पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने यह जानकारी दी है। मंत्री ने कहा कि हम कोकिंग कोयले के आयात पर विचार कर रहा है। यह इस्पात विनिर्माण में काम आने वाला एक प्रमुख कच्चा माल है। प्रधान ने कहा कि हम उचित मूल्य पर कोकिंग कोयले का आयात करने की तैयारी कर रहे हैं।

भारत 2030-31 तक इस्पात उत्पादन को 30 करोड़ टन पर पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। प्रधान ने कहा, 'भारत द्वारा आस्ट्रेलिया से कोयले का आयात किया जा रहा है, जो अच्छा है। लेकिन मंगोलिया में भी अच्छी गुणवत्ता का कोयला उपलब्ध है। हमारी इस बारे में मंगोलिया सरकार से बातचीत चल रही है।' भाषा

18 प्रतिशत बढ़ सकता है रेलवे का पूंजीगत व्यय

शाइन जैकब
नई दिल्ली, 12 जनवरी

वित्त वर्ष 2020-21 में रेलवे के पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) में 18 प्रतिशत की बढ़ोतरी हो सकती है, जो चालू वित्त वर्ष के लिए 1.6 लाख करोड़ रुपये था। एक सरकारी अधिकारी ने कहा, 'हम उम्मीद करते हैं कि आगामी बजट 1.8 से 1.9 लाख करोड़ रुपये होगा। अगले 10 साल के दौरान रेलवे ने पूंजीगत व्यय में संयुक्त सालाना वृद्धि दर (सीएजीआर) करीब 18 प्रतिशत बढ़ाने का लक्ष्य रखा है।'

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा हाल में पेश नैशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन (एनआईपी) में 2020-25 के दौरान बुनियादी ढांचा पर कुल पूंजीगत व्यय 102 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा रहने का अनुमान लगाया गया है, जिसमें रेलवे की हिस्सेदारी 13 प्रतिशत या 13.7 लाख करोड़ रुपये रह सकती है।

अधिकारी ने कहा, 'हमारा ध्यान उच्च स्तर पर निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी के साथ यात्री सुविधाएं व माल ढुलाई सेवाएं और बेहतर करने पर है।'

उन्होंने कहा कि अगर वित्त मंत्रालय बोर्ड की उम्मीदों के मुताबिक चलता है तो अगले वित्त वर्ष में रेलवे के इतिहास में सबसे ज्यादा निवेश होगा। यह 2018-19 के 1.33 करोड़ रुपये के हासिल लक्ष्य से ऊपर होगा, जिसमें बजट 1.46 लाख करोड़ रुपये रखा गया था। बड़ी बुनियादी ढांचा पहल में 100 प्रतिशत विद्युतीकरण और ट्रैक का उन्नयन, सिगनल व्यवस्था और स्टेशनों को बेहतर बनाना और सुरक्षा व यात्रियों के अनुभव में सुधार शामिल है।

पिछले 5 साल के दौरान पूंजीगत व्यय धीरे धीरे बढ़ा है, लेकिन रेलवे के वित्त मंत्रालय की चिंता की वजह रेलवे के पूंजीगत व्यय में आंतरिक स्रोत से धन में आ रही कमी है। 2015-16 में यह हिस्सेदारी 18 प्रतिशत थी, जो 2019-20 में घटकर 6.5 प्रतिशत रह गई।

उद्योग के विशेषज्ञों के मुताबिक कमाई में कम वृद्धि की वजह औसत माल ढुलाई में कमी और कार्यशील पूंजी बढ़ना है। इसकी भरपाई बजट के अतिरिक्त संसाधनों से करनी पड़ रही है।

पिछले साल सरकार इस सेक्टर में 2030 तक 50 लाख करोड़ रुपये निवेश की योजना लेकर आई थी। एनआईपी में भी निजी क्षेत्र से मोटे निवेश का संकेत दिया गया है, जिसमें कॉर्गो की मात्रा का 30 प्रतिशत और 50 यात्री रेलगाड़ियों का अगले 5 साल में निजीकरण शामिल है।

पूर्वी और पश्चिमी समर्पित मालवहन गलियारे (डीएफसी) और कुछ उपभोक्ता के अनुकूल पहल के कारण माल ढुलाई की हिसस्सेदारी तब तक करीब 35 से 40 प्रतिशत होने की उम्मीद है।

हाल के आंकड़ों के मुताबिक माल ढुलाई से कमाई अप्रैल-नवंबर 2020 तक पिछले साल की तुलना में 4.32 प्रतिशत घटकर 71,800 करोड़ रुपये रह गई है। बहरहाल चिंता का बडा मसला कार्यशील पूंजी में समीक्षावधि के दौरान 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी है।

शुक्रवार को जारी इंडिया रिपोर्ट 2020 में अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (आईईए) ने 2050 तक परिवहन क्षेत्र में रेल की भूमिका बढ़ाने के की जरूरत पर जोर दिया है। रेलवे की भूमिका बढ़ने पर तेल की मांग प्रतिदिन 31 लाख बैरल प्रतिदिन कम हो सकती है, जिससे ईंधन पर 60 अरब डॉलर व्यय कम होगा और सालाना जीएचजी उत्सर्जन घटकर 585 एमटी सीओ-2 इक्यू और पीएम 2.5 उत्सर्जन 14,000 टन घटेगा।

यह लक्ष्य हासिल करने के लिए रेलवे नेटवर्क के आधुनिकीकरण करने के लिए निवेश प्रोत्साहन, जमीन के मूल्य, हाईस्पीड ट्रेन का काम पूरा करने, क्रॉस सब्सिडाइजेशन स्कीम को खत्म करने की वकालत की गई है।

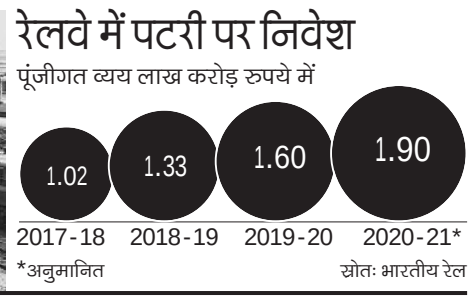

तेल 70 डॉलर से नीचे रहा तो नहीं बिगड़ेगा बजट

अरूप रॉयचौधरी
नई दिल्ली, 12 जनवरी

केंद्र सरकार के 2020-21 के बजट की तैयारियों में आर्थिक मंदी प्रमुखता पर है, वहीं पश्चिम एशिया में अस्थिरता और उसका कच्चे तेल पर पड़ने वाले असर को लेकर भी अनिश्चितता है।

बहरहाल विश्लेषकों और अर्थशास्त्रियों का कहना है कि जब तक कच्चे तेल का दाम 70 डॉलर प्रति बैरल तक के स्तर पर बना रहेगा, केंद्र के बजट या महंगाई को लेकर कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप सहित अगर वैश्विक नेताओं के हाल के बयानों को देखें तनाव कम करने पर जोर है, जो बजट बना रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है।

येद्व बैंक की मुख्य अर्थशास्त्री शुभदा राव ने कहा, 'अगर बजट बनाने वाले कच्चे तेल का दाम 65-70 डॉलर प्रति बैरल के हिसाब से बनाते हैं तो उनके राजकोषीय गणित के हिसाब से ठीक रहेगा। अहम बात यह है किराजकोषीय गणित ज्यादा विश्वसनीय होने की जरूरत है।'

इंडिया रेटिंग के मुख्य अर्थशास्त्री देवेंद्र कुमार पंत ने कहा, 'अर्थव्यवस्था और केंद्रीय बजट की गणना पर कोई असर पड़ने की संभावना नहीं है, अगर कच्चा तेल 70 डॉलर के नीचे बना रहता है। अगर यह कम अवधि के लिए इससे ऊपर भी जाता है तो भी कोई बड़ा असर नहीं पड़ेगा। अगर कच्चा तेल 2 महीने या इससे ज्यादा समय तक इसके ऊपर जाता है, तब समस्या होगी।'

- अमेरिका-ईरान में टकराव की तेजी के बाद कच्चा तेल माह के निचले स्तर पर
- विश्लेषकों का कहना है कि अगर कच्चा तेल 70 डॉलर प्रति बैरल पार करता है तो तेल व उर्वरक का बिल भी बढ़ेगा, महंगाई भी बढ़ेगी

अमेरिका और ईरान के बीच टकराव के बाद कच्चे तेल के दाम में थोड़ी तेजी आई थी, लेकिन फिर दाम माह के निचले स्तर पर पहुंच गए। इसके अलावा न्यूयॉर्क में गुरुवार को इसमें 1.6 प्रतिशत की गिरावट आई। राष्ट्रपति ट्रंप ने जब इराक में अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइल से हुए हमलों को कम करके बताया। जबकि एक दिन पहले इसमें 5 प्रतिशत की गिरावट आई थी। उस समय चिंता थी कि वाशिंगटन और तेहरान में टकराव बढ़ेगा। वास्तव में बाजार में तेल की आपूर्ति पर कोई असर नहीं पड़ा था।

फरवरी डिलिवरी के लिए वेस्ट टैक्सस इंटरमीडिएट 80 सेंट कमजोर होकर न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में 58.80 डॉलर प्रति बैरल हो गया, जो इसके पहले 1.2 प्रतिशत तक चढ़ा था। मार्च के लिए ब्रेंट फ्यूचर्स का सेटलमेंट 66 सेंट गिरकर आईसीई फ्यूचर्स यूरोप एक्सचेंज में 64.78 डॉलर प्रति बैरल हो गया, जो इसके पहले 1 प्रतिशत तक बढ़ा था।

संभवत: ओपेक क्षेत्र भी युद्ध जैसी स्थिति से बचना चाहता है क्योंकि इससे उनकी भी अर्थव्यवस्थाओं में अस्थिरता आएगी। राव ने कहा कि ट्रंप का राष्ट्रपति चुनाव को लेकर संदेश यह है कि वह युद्ध जैसी स्थिति से बचना चाहते हैं। उन्होने कहा कि इसमें किसी की दिलचस्पी नहीं है कि तेल के दाम बढ़ें।

उन्होंने कहा, 'वैश्विक रिकवरी अभी शुरुआती अवस्था में है और अगर आगे कुछ टकराव होता है तो उससे अमेरिका की अर्थव्यवस्था की रिकवरी पर भी असर पड़ सकता है। वैश्विक अर्थव्यवस्था अभी तेल के एक और झटके को बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है।'

पंत ने कहा कि अगर आने वाले महीनों में कच्चे तेल के दाम में अप्रत्याशित बढ़ोतरी होती है तो इससे न सिर्फ पेट्रोलियम और उर्वरक सब्सिडी बढ़ने से बजट की गणना बिगड़ेगी, साथ ही इससे महंगाई भी बढ़ेगी, जिसका असर मौद्रिक नीति के मोर्चे पर भी नजर आएगा।

राजमार्गों से धन जुटाने के लिए नीति आयोग ने पेश किए मॉडल

मेघा मनचंदा
नई दिल्ली, 12 जनवरी

राष्ट्रीय राजमार्गों को वित्तीय हिसाब से ज्यादा कुशल बनाने के लिए नीति आयोग ने कुछ विकल्प सुझाए हैं, जिनका इस्तेमाल सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) कर सकते हैं। इसमें विकास शुल्क वसूलना और राजमार्गों के किनारे सुविधाएं देने में हिस्सेदारी शामिल है।

यह विचार वैल्यू कैप्चर फाइनैंसिंग मॉडल का हिस्सा है, जिसका सुझाव सरकार के थिंक टैंक ने दिया था। इस मॉडल के तरह सार्वजनिक बुनियादी ढांचा तैयार करने वल आने वाली पूरी लागत या उसका एक हिस्सा निजी भूमि मालिकों या एनएचएआई के मामले में राज्य से लिया जाना शामिल है, जिनकी भूमि का मूल्य बढ़ने से उन्हें लाभ पहुंचता है, जबकि एजेंसी उस पर पूरा निवेश करती है। एनएचएआई द्वारा इस मद में किए जाने वाले खर्च की वसूली का प्रस्ताव है।

एक अधिकारी ने कहा कि नीति आयोग एनएचएआई के साथ मिलकर काम कर रहा है, जिससे वित्तीय स्थिरता और परियोजना की व्यावहारिकता सुनिश्चित हो सके। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में नीति आयोग ने कई मॉडल सुझाए हैं, जिनमें से कुछ एनएचएआई लागू करेगा।

इसमें टोल ऑपरेट ट्रांसफर (टीओटी) सहित संपत्ति के मुद्रीकरण की तकनीक और बुनियादी ढांचा निवेश ट्रस्ट (इनविट) के माध्यम से राजस्व जुटाना शामिल है। इन दोनों विचारों पर एनएचआई ने जोर दिया है।

यह भी सिफारिश की गई है कि वैल्यू कैप्चर फाइनैंस (वीसीएफ) को एनएचएआई की परिजनाओं में लगाया जाएगा। वीसीएफ के माध्यम से गैर टोल राजस्व को कई तरीकों से बढ़ाया जा सकता है, जिसमें खाली भूमि पर कर, विशेष आकलन कर, विकास अधिकारों का हस्तांतरण (टीडीआर) और लैंड पूलिंग आदि शामिल है।

इसमें यह भी सिफारिश की गई है कि अतिरिक्त राजस्व जुटाने के अन्य साधनों जैसे आईडीएफ, एनएचएआई एलए बॉन्ड का भी विकल्प अपनाया जा सकता है। परियोजना विशेष के लिए एसपीवी बनाने की भी सिफारिश की गई है।

वैल्यू कैप्चर फाइनैंस और ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट (टीओडी) पर भी एक मसौदा नीतिगत खाका भी सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय सहित कई मंत्रालयों को भेजा गया है। इस दस्तावेज मे वैल्यू कैप्चर फाइनैंस के माध्यम से राजस्व बढ़ाने के कई तरीके बताए गए हैं और अगर यह व्यवहार में आता है तो इससे एनएचएआई की वित्तीय स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हो सकता है।

टीओडी खासकर अहम है, जहां परियोजनाओं के आसपास वाणिज्यिक, आवासीय और संस्थानात्मक हिसाब से योजनाबद्ध बुनियादी ढांचा विकास होता है। इसके अलावा वीसीएफ का एक हिस्सा लैंड बॉन्ड है, जिसकी योजना एनएचएआई ने राज्यों से अधिग्रहीत भूमि के भुगतान के लिए बनाई है। इस व्यवस्था के तहत एनएचएआई भूमि अधिग्रहण के एवज में पहले भुगतान नहीं करेगा।

क्या है वीसीएफ?

वैल्यू कैप्चर फाइनैंसिंग (वीसीएफ) सार्वजनिक वित्तपोषण का एक तरीका है, जिसके माध्यम से सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के लिए पूरा या आंशिक धन निजी भूमि मालिकों से जुटाया जाता है। इसमें सार्वजनिक बुनियादी ढांचे पर आने वाले पूरे या आंशिक खर्च को निजी भूमि मालिकों या एनएचएआई के मामले में राज्यों व निजी भूमि मालिकों से जुटाया जाता है, जिनको इस बुनियादी ढांचे का लाभ मिलता हे और राजमार्गों की वजह से उनकी जमीन के दाम बढ़ जाते हैं, लेकिन पूरा निवेश एजेंसी करती है।

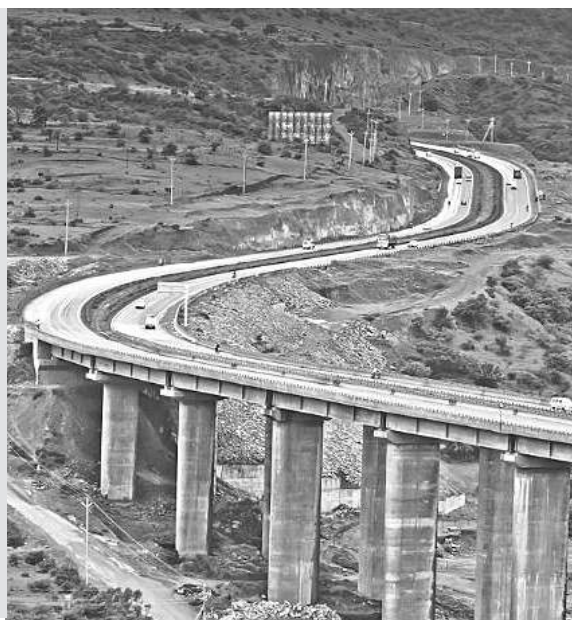

बीएस सूडोकू 3637

						3	2	
				6	8	4		
7				9			1	8
3				7		1	5	
5			4		6			7
	7	2		5				3
8	4			1				2
		7	9	8				
	9	1						

परिणाम संख्या 3636

7	2	9	1	5	3	6	8	4
5	6	1	7	4	8	3	2	9
8	4	3	6	2	9	7	5	1
1	8	4	5	3	7	9	6	2
9	5	2	4	6	1	8	3	7
3	7	6	8	9	2	1	4	5
2	1	7	3	8	4	5	9	6
6	9	8	2	7	5	4	1	3
4	3	5	9	1	6	2	7	8

कैसे खेलें?
हर रो, कॉलम और 3 बाई 3 के बॉक्स में एक से लेकर नौ तक की संख्या भरें।

आसान
★★☆☆☆

आर्थिक वृद्धि बहाली को लेकर अर्थशास्त्री आश्वस्त नहीं

इंदिवजल धस्माना
नई दिल्ली, 12 जनवरी

अर्थशास्त्रियों का मानना है कि आगामी केंद्रीय बजट आर्थिक वृद्धि दर बहाल करने में अहम भूमिका निभाएगा। उनका कहना है कि बेहतर स्थिति रहने पर भी 2020-21 में वृद्धि दर 6 प्रतिशत से ऊपर नहीं जा सकती है।

पूर्व मुख्य सांख्यिकीविद प्रणव सेन ने कहा कि आर्थिक बहाली केंद्रीय बजट में उठाए गए कदमों पर निर्भर होगी। सरकार की ओर से कॉर्पोरेशन कर में कटौती सहित पहले ही उठाए जा चुके कदमों के बारे में पूछे जाने पर सेन ने कहा कि कर की कम दरों का आर्थिक वृद्धि पर कोई असर नहीं होगा। उन्होंने कहा, 'व्यक्तिगत आयकर दरों में कटौती का भी आर्थिक वृद्धि पर ज्यादा असर नहीं होगा।' सेन ने कहा कि वृद्धि बढ़ाने के लिए रोजगार का सृजन और बजट में इस पर जोर दिया जाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि नई योजना की घोषणा के बगैर सरकार को पीएम किसान, मनरेगा और ग्रामीण इलाकों में सड़कों के निर्माण जैसी योजनाओं को मजबूत करने की जरूरत है।

- वृद्धि वित्त वर्ष 21 में 5 प्रतिशत के करीब बनी रह सकती है, अगर बजट में नहीं उठाए गए सकारात्मक कदम
- कॉर्पोरेट कर की कम दरों, व्यक्तिगत आयकर दरों में कटौती का भी आर्थिक वृद्धि पर ज्यादा असर नहीं होगा

सांख्यिकी कार्यालय द्वारा बनाई गई कई समितियों में रहे जाने माने अर्थशास्त्री सुदीप्त मंडल ने कहा कि आर्थिक वृद्धि इस पर निर्भर करती है कि सरकार वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाती है, लेकिन असल रिकवरी के लिए 2 साल इंतजार करना होगा। उन्होंने कहा कि इस हिसाब से बजट बहुत आलोचनात्मक है। सरकार के राजकोषीय घाटे के लक्ष्य पर बने रहने या अर्थव्यवस्था को गति देने के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि यह गलत चयन है। राजकोषीय लक्ष्य से समझौता किए बगैर व्यय को बढ़ावा देने के विकल्प हैं।

नैशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनैंस ऐंड पॉलिसी में प्रोफेसर एनआर भानुमूर्ति ने का मानना है कि अगले वित्त वर्ष में वृद्धि रफ्तार पकड़ लेगी, लेकिन अमेरिका-ईरान के बीच तनाव से यह उम्मीद धुंधली हो रही है। उन्होंने 2021 में वृद्धि दर 5 से 5.5 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। उनका कहना है कि अमेरिका-ईरान की स्थिति पैदा न होती तो 2020-21 में वृद्धि दर 6 प्रतिशत से ऊपर चली जाती।

बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 12 अंक 281

इंटरनेट की आजादी

देश की सर्वोच्च अदालत ने एक अहम घोषणा में कहा है कि देश के किसी भी हिस्से में, राज्य के किसी भी अधिकारी के आदेश से की जाने वाली इंटरनेट की बंदी अस्थायी होनी चाहिए और इसे समानता के सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए। गत सप्ताह अनुराधा भसीन बनाम भारत सरकार मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी और कारोबार-व्यापार करने की आजादी को संविधान के अनुच्छेद 19(1) के तहत संरक्षण प्राप्त है। उसने यह भी कहा कि इंटरनेट इन अधिकारों के इस्तेमाल का एक अहम जरिया है। अतीत में केरल उच्च न्यायालय ने भी यह घोषणा की थी कि शिक्षा के अधिकार और निजता के अधिकार का इस्तेमाल करने के लिए इंटरनेट तक पहुंच अनिवार्य है। दूसरे शब्दों में कहें तो अब इस बात के पर्याप्त न्यायिक दृष्टांत मौजूद हैं जिनसे यह संकेत मिलता है कि इंटरनेट तक पहुंच को कम करना या समाप्त करना मूलभूत अधिकारों के इस्तेमाल को प्रतिबंधित करने वाला है और इसलिए इस मामले में भी राज्य पर उचित सीमाएं लागू होनी चाहिए। भारत में ऐसे अधिकार संपूर्ण नहीं हैं और कड़े संवैधानिक मानकों में अनुरूप ही उनमें कटौती की जा सकती है।

अदालत का यह निर्णय कश्मीर में महीनों से चली आ रही इंटरनेट की सरकारी बंदी के संदर्भ में आया है। खासतौर पर मोबाइल इंटरनेट की बंदी को लेकर। इससे संपूर्ण जम्मू और कश्मीर क्षेत्र में संचार बाधित हुआ, लोगों की आजीविका तो प्रभावित हुई, परिवारों के सदस्य भी एक दूसरे से दूर रहने को विवश हुए। यह बंदी अनुच्छेद 370 समाप्त किए जाने और राज्य को दो केंद्रशासित प्रदेशों में बांटने के बाद लागू हुई थी। उस वक्त बड़ी तादाद में राज्य के शीर्ष राजनेताओं को बंदी भी बनाया गया था। दुर्भाग्यवश अदालत ने कश्मीर में केंद्र सरकार के कदमों को लेकर पर्याप्त तेजी नहीं दिखाई। अभी भी उसने घाटी में उन लोगों को पूरी राहत नहीं दी है जो गत वर्ष 4 अगस्त से अपने अधिकारों से वंचित हैं। बहरहाल, उसने ऐसी विशिष्ट बंदी की समीक्षा की राह खोल दनी है और भविष्य में की जाने वाली बंदियों की राह कठिन बना दी है। अदालत ने यह भी कहा कि 2017 के आईटी नियमों के तहत गृह सचिव एक सक्षम प्राधिकारी है और जब तक वह पुष्टि न करे तब तक किसी भी तरह की बंदी 24 घंटे से अधिक अवधि तक लागू नहीं होगी। सर्वोच्च न्यायालय का नजरिया स्वागतयोग्य है क्योंकि देश के विभिन्न हिस्सों में बार-बार इंटरनेट की बंदी हुई है और इनकी तादाद और अवधि में लगातार इजाफा हुआ है। अंतरराष्ट्रीय शोधकर्ताओं का भी कहना है कि भारत में ऐसी बंदियों की संख्या अधिक है।

खेद की बात है कि स्थानीय अधिकारियों ने यह तय कर लिया है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत उन्हें अपने क्षेत्रों में इंटरनेट बंद करने का अधिकार है। कई जगहों पर ऐसे निर्णयों के लिए 'राष्ट्रीय सुरक्षा' और 'कानून-व्यवस्था' की दलील दी गई। अदालत ने कहा है कि बंदी को चुनौती मिलना इसलिए भी प्रभावित हुआ क्योंकि अधिकारियों ने अपने निर्णयों को लेकर उचित पारदर्शिता नहीं दिखाई है।

इसका अर्थ यह हुआ कि समानता का परीक्षण लागू करना असंभव है जो कि देश के लोगों के बुनियादी अधिकार का उल्लंघन है। इसलिए उसने आदेश दिया है कि इसके पीछे की वजह को सार्वजनिक किया जाए, इसकी उचित समीक्षा हो और हर सात दिन में इसकी दोबारा समीक्षा हो।

अदालत को शायद और आगे बढ़कर समीक्षा समिति बनानी थी। तमाम अन्य देशों में ऐसी समितियां हैं जिनके सदस्य शासन के अन्य अंगों से आते हैं, न कि केवल अफसरशाही से।

अजय मोहंती

युवाओं की नाराजगी की शिकार मोदी सरकार

भारी जनादेश के साथ सत्ता में आने के छह माह के भीतर मोदी सरकार छात्रों से लड़ रही है। उसके सबसे बड़े समर्थक इस वक्त निराश, नाउम्मीद और एक हद तक क्रोधित हैं।

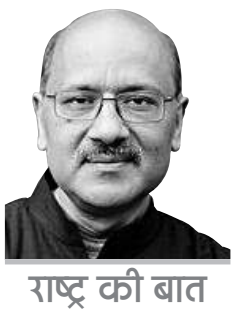

राष्ट्र की बात

शेखर गुप्ता

प्रतिस्पर्धी खेलों में लीग व्यवस्था होती है। ये लीग उच्च, मध्य, निम्न, वरिष्ठ और कनिष्ठ समेत तमाम वर्गों में विभाजित होती हैं। किसी प्रतिभागी का कद देखकर ही यह निर्णय होता है कि वह किस लीग में खेलेगा या खेलेगी। जो खिलाड़ी निचले स्तर की लीग में युवतर खिलाड़ियों (या कहें बच्चों) के साथ खेलता है, वह अपना ही कद कमजोर करता है।

देश की राजनीति पर भी इस बात को लागू किया जा सकता है। खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार छात्रों के विरोध प्रदर्शन से जिस तरह निपट रही है उसे देखते हुए ऐसा किया जा सकता है।

इसे समझने का एक सामान्य तरीका वह है जो हम पहलवान से अभिनेता बने दारा सिंह से सीख सकते हैं। दारा सिंह खुद को कुश्ती की चुनौती देने वालों से कहते थे कि पहले वह उनके भाई रंधावा को पराजित करे तभी वह उनसे कुश्ती लड़ पाएगा। मैंने उनसे सवाल किया कि वह ऐसा क्यों करते हैं तो उन्होंने जवाब दिया कि 'कोई भी लल्लू पंजू यह डींग हांकना चाहेगा कि वह दारा सिंह के साथ लड़ चुका है। मैं उन्हें खुश करने के लिए अपना कद क्यों छोटा करूं?'

वापस राजनीति की बात करते हैं। भाजपा की ताकतवर सरकार बीते एक महीने से यही कर रही है: वरिष्ठ, शक्तिशाली स्त्री और पुरुष, बच्चों से लड़ रहे हैं। उनकी नीतियों के विरोध में देश भर के शैक्षणिक परिसरों में आग भड़की हुई है। भाजपा जहां सत्ता में है वहां इसका मुकाबला वह पूरी शक्ति से कर रही है। इंटरनेट और संचार सीमित किया जा रहा है और उत्तर प्रदेश में तो सामूहिक जुर्माना तक लगाया गया है।

यदि इतने बहुमत से जीतकर आई सरकार छात्रों की बात सुनने के बजाय उनसे लड़ने लगती है तो तीन घटनाएं लाजिमी तौर पर घटती हैं:

सबसे पहले तो इससे अत्याचारी बनाम शोषित की कहानी बनती है।

दूसरा, इससे ऐसी तस्वीरें पैदा होती हैं जो वैश्विक स्तर पर भारत की छवि धूमिल करती हैं। इन्हें बाहर निकलने से किसी तरह रोका नहीं जा सकता है।

तीसरी और सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह है कि इससे युवाओं के बीच 'बच्चे बनाम अंकल/आंटी' वाला माहौल बनता है। इसे विस्तार से समझते हैं।

सन 2014 और 2019 के हर एक्जिट और ओपिनियन पोल में यही दर्शाया गया कि देश के युवा, खासतौर पर पहली बार मतदान करने वाले नरेंद्र मोदी के समर्थक हैं। मैंने सन 2019 के आम चुनाव के दौरान देश भर के युवाओं से बात की और वे केवल एक नेता का नाम लेते थे: मोदी।

मैंने नई दिल्ली में सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च की एक बहस में उन कारकों पर बात की थी जो मोदी की बड़ी जीत में योगदान कर रहे हैं। खासतौर पर इस बात का कि कैसे युवा पहचान आधारित बातों मसलन जाति, भाषा, जातीयता और कई मामलों में धर्म को भी परे रखकर मोदी को अपना रहे हैं।

उनकी आंखों में आशावाद, खुशी, बेहतर जीवन की आकांक्षा नजर आई। वे अपने परिवारों की पुरानी राजनीतिक वफादारी को इसलिए नहीं छोड़ रहे थे क्योंकि वे उनसे नफरत करते थे या डरते थे। यदि 2014 का चुनाव बेहतर जीवन की आशा का चुनाव था तो 2019 का चुनाव उस वादे के नवीनीकरण का चुनाव था।

बहरहाल, छह महीने के भीतर उन्हें लगा कि उन्हें कुछ अलग ही मिला है। अर्थव्यवस्था में जबरदस्त गिरावट आई है। गिरावट का सिलसिला लंबे समय से जारी है और वृद्धि एवं अच्छे दिन की बात अब कपोल कल्पना लग रही है।

युवाओं के बीच सन 1970 के दशक के मध्य जैसा निराशावाद और असहायता घर कर रही है। नए रोजगार नहीं हैं। भले ही हर रोजगार महत्त्वपूर्ण होता है लेकिन सच यही है कि कॉलेज में पढ़ने वाला हर युवा स्विगी या जोमैटो के लिए डिलिवरी करने या ओला अथवा उबर के लिए वाहन चलाने का इरादा नहीं रखता।

मोदी ने उनसे इसका वादा नहीं किया था। उनकी आकांक्षाएं और जरूरतें एकदम स्पष्ट हैं और वे पूरी नहीं हो रही हैं। जाहिर है इसकी भरपाई कश्मीर के एकीकरण और उस पर नियंत्रण से अथवा पाकिस्तान को सबक सिखाने से नहीं हो सकती है। न ही मुस्लिमों का भय दिखाने या प्रवासी मुस्लिमों से घृणा करने का दबाव बनाने से उनकी जरूरतें पूरी होंगी।

इनमें से कोई कदम ऐसा नहीं है जो उन्हें रोजगार दिला सके, बेहतर आजीविका सुनिश्चित कर सके या बेहतर जीवन दे सके। यकीनन तब तक नहीं जब तक कि वे आपके वैचारिक अनुयायी न हों। कॉलेज जाने वाले युवाओं के बीच मोदी को लेकर तेजी से मोहभंग हुआ है।

किसी के मन में यह गलत धारणा नहीं रहनी चाहिए कि ऐसा वाम और उदार रुझान वाले चुनिंदा सरकारी विश्वविद्यालयों में 'अर्बन नक्सल' की वजह से हो रहा है। अब यह गुस्सा महंगे निजी विश्वविद्यालयों में भी फैल चुका है। जबकि वहां किसी तरह की राजनीति या राजनीतिक संगठनों की जगह नहीं है। इन विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों के माता-पिता बहुत अधिक धन खर्च करके बच्चों को यहां पढ़ाते हैं। मैंने देश के कई हिस्सों में लोगों से बात की और पाया कि लोगों में वैसा ही गुस्सा है जैसा कि जेएनयू, जामिया अथवा बीएचयू में नजर आ रहा है।

छात्रों में यह भावना प्रबल हो रही है, 'हमने इसलिए तो मतदान नहीं किया था।' मैं सुनिश्चित तौर पर यह भी कह सकता हूं कि इन युवाओं में बड़ी तादाद उनकी है जिन्होंने मोदी को वोट दिया था और उनमें भी ज्यादातर ने पहली बार मतदान किया था।

द प्रिंट महीने में एक बार अभिव्यक्ति की आजादी के एक कार्यक्रम का आयोजन करता है जिसका नाम है 'डेमोक्रेसी वॉल'। यह आयोजन किसी प्रमुख शैक्षणिक परिसर में किया जाता है। इसकी विशेषताओं में एक विशालकाय बैनर शामिल है जो देखने में दीवार जैसा नजर आता है। छात्र अपने मन की बात उस पर लिखकर हस्ताक्षर कर सकते हैं। बीते छह महीनों में इस पर लिखी जाने वाली इबारत में बदलाव आया है। पिछले तीन महीनों में तो यह बदलाव नाटकीय रहा है।

ये सभी महंगे निजी विश्वविद्यालयों से हैं। हाल के दिनों में इनमें क्रोध और निराशा भी नजर आने लगी है। इस बीच चतुराई का प्रयोग भी होता है। मिसाल के तौर पर 'मेरा देश जल रहा है' लिखने के बाद हैशटैग के साथ ऑस्ट्रेलिया को बचाने की गुहार की जाती है। सबसे आम नजर आने वाला वाक्य है 'बुरे दिन वापस कर दो।' तीन महीने पहले तक कुछ आलोचना होती थी। आज तो तारीफ का एक शब्द देखने को नहीं मिलता।

ज्यादातर अवसरों पर राष्ट्रवाद, धर्म और किसी नेता के व्यक्तित्व के मिश्रण के बल पर एक चुनाव जीता जा सकता है। परंतु इसके बल पर लगातार दो चुनाव नहीं जीते जा सकते। मोदी के दूसरी बार सरकार बनाने के छह महीने के भीतर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को संवाददाताओं को संबोधित करके छात्रों को दंगाई और देशद्रोही बताना पड़ रहा है। मैं माफी चाहता हूं लेकिन सवाल यह भी है कि देश में पुलिस पर यकीन ही कौन करता है। कैबिनेट मंत्री टेलीविजन चैनलों पर बैठकर छात्र-छात्राओं को बता रहे हैं कि कैसा व्यवहार करें और कैसे देशभक्त बनें। लेकिन आज का युवा चतुर है।

तिरंगा लहराते हुए विरोध करके वे इन नेताओं को चुप करा देते हैं, वे बड़ी तादाद में एकत्रित होकर संविधान की प्रस्तावना पढ़ते हैं और राष्ट्रगान गाते हैं। महज छह महीने पहले बॉलीवुड का एक बड़ा तबका मोदी के साथ सेल्फी ले रहा था। आज उनमें से कई विरोध प्रदर्शन करने वालों के साथ हैं। जो शेष हैं, वे भी खामोश हैं। कोई फिल्मी सितारा सरकार के पक्ष में सामने नहीं आया है। यदि आपको संदेह है तो आप जांच लीजिए कि नागरिकता संशोधन अधिनियम के समर्थन में कैबिनेट मंत्री के मुंबई में आयोजित रात्रिभोज में कौन-कौन शामिल हुआ। कुछ नामों को पहचानने के लिए आपको गूगल की मदद लेनी पड़ सकती है।

इन तमाम बातों के बीच दीपिका पडुकोणे का मजाक उड़ाने और ताना मारने के लिए दूसरी बार मंत्री बनी स्मृति इरानी जैसी शख्सियतों को उतार दिया जाता है। याद रहे कि आप खेलने के लिए जिस लीग का चुनाव करते हैं उससे आपका कद पता चलता है।

राज्य जीएसटी में वृद्धि अनुमानों में भारी अंतर से पैदा होते सवाल

दिल्ली डायरी

ए के भट्टाचार्य

नवंबर 2019 के आखिरी सप्ताह में विपक्षी दलों द्वारा शासित पांच राज्यों ने एक बयान जारी किया। इसमें कहा गया कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) से घटते राजस्व का उनकी वित्तीय स्थिति पर असर पड़ना शुरू हो गया है। केंद्र ने राज्यों को हर्जाने के भुगतान में देरी कर दी थी। जीएसटी प्रणाली में उन राज्यों को यह हर्जाना देने का वादा किया गया है, जिनका इस नए कर से सालाना राजस्व 14 फीसदी से अधिक नहीं बढ़ पाएगा।

इन पांच राज्यों- पंजाब, केरल, दिल्ली, राजस्थान और पश्चिम बंगाल ने एक संयुक्त बयान में कहा, 'केंद्र सरकार को अगस्त और सितंबर महीनों के जीएसटी हर्जाने का भुगतान अक्टूबर में करना था, लेकिन इसका आज तक भुगतान नहीं किया गया है।' इन राज्यों ने दावा किया कि उनकी राजकोषीय स्थिति पर दबाव है और उनमें से कुछ पहले ही 'वेज ऐंड मीन्स एडवांस' का सहारा ले रहे हैं। 'वेज ऐंड मीन्स एडवांस' केंद्रीय बैंक द्वारा केंद्र और राज्यों को मुहैया कराए जाने वाले कर्ज की विशेष सुविधा है।

दिसंबर के पहले सप्ताह तक और बहुत से राज्य इस मांग के सुर में सुर मिलाने लगे थे कि केंद्र द्वारा जीएसटी हर्जाना जल्द जारी किया जाना चाहिए। अब ऐसे राज्यों (केंद्र शासित प्रदेशों समेत) की संख्या आठ हो चुकी थी। पहले के पांच राज्यों में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और पुदुच्चेरी भी शामिल हो चुके थे। इन राज्यों ने कहा कि अगर केंद्र ने बकाया हर्जाना जारी नहीं किया तो वे सर्वोच्च न्यायालय जाएंगे। ऐसा लगता है कि इस दबाव ने काम किया है। नई दिल्ली में 18 दिसंबर को जीएसटी परिषद की 38वीं बैठक से पहले केंद्र ने राज्यों को बकाया जीएसटी हर्जाने के रूप में 35,298 करोड़ रुपये जारी किए।

इससे राज्यों की एक अहम मांग पूरी हुई है, जो जीएसटी राजस्व में सुस्ती और केंद्र के हर्जाना जारी करने में देरी से प्रभावित हो रहे हैं। लेकिन इस देरी से केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों में खटास आई है। जीएसटी परिषद की 38वीं बैठक में लॉटरी पर कर की नई दर का फैसला लेने के लिए पहली बार मत विभाजन कराना पड़ा। इससे पहले जीएसटी परिषद में सभी फैसले सर्वसम्मति से लिए गए थे। हालांकि मत विभाजन का प्रावधान शुरू से ही मौजूद है।

यह साफ तौर पर जीएसटी राजस्व में सुस्ती को दर्शाता है, जिससे निस्संदेह केंद्र प्रभावित हुआ है। लेकिन राज्य भी इतने ही चिंतित हैं क्योंकि उनके राजस्व अनुमान गलत साबित हुए हैं। राज्य जीएसटी या एसजीएसटी संग्रह की राज्यों के कर राजस्व में 43 फीसदी से अधिक हिस्सेदारी है, इसलिए एसजीएसटी में किसी मंदी से राज्यों की वित्तीय स्थिति के लिए खतरे की घंटी बज जाती है।

राज्यों के लिए स्थिति कितनी गंभीर है? वर्ष 2019-20 में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने 2018-19 के 5.52 लाख करोड़ रुपये के संशोधित अनुमानों के मुकाबले एसजीएसटी में 11 फीसदी बढ़ोतरी का अनुमान लगाया था। वित्त वर्ष 2019-20 के पहले आठ महीनों में कुल एसजीएसटी संग्रह 2.01 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है, जो 6.13 लाख करोड़ रुपये के सालाना राजस्व संग्रह के लक्ष्य का करीब एक तिहाई है।

दूसरे शब्दों में राज्यों को अपने एसजीएसटी संग्रह में अहम गिरावट के लिए तैयार रहना होगा। चालू वर्ष की दो-तिहाई अवधि में संग्रहीत राजस्व लक्ष्य का महज एक-तिहाई रहा है। इसी वजह से हर्जाने की राशि जारी करने के लिए राज्यों के सुर तेज हो रहे हैं। लेकिन राज्यों को हर्जाने की मदद केवल 2017 से अगले पांच साल ही मिल पाएगी। अगर एसजीएसटी राजस्व में वृद्धि की रफ्तार वर्तमान समय की तरह सुस्त बनी रही तो वर्ष 2022 से राज्यों के राजस्व का क्या होगा?

हालांकि इन राज्यों में से कुछ ऐसे भी हैं, जो खुद को मौजूदा राजकोषीय मुश्किल में डालने की जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकते। कम से कम 14 राज्यों का अनुमान था कि 2019-20 में एसजीएसटी राजस्व में वृद्धि 14 फीसदी से अधिक रहेगी। यह अनुमानित वृद्धि दर 14 से 27 फीसदी थी। जब ये राज्य चालू वित्त वर्ष के लिए एसजीएसटी राजस्व वृद्धि की दरें तय कर रहे थे, तब उनके वित्त मंत्री क्या कर रहे थे?

निस्संदेह केंद्र भी उससे कहीं अधिक राजस्व वृद्धि का अनुमान लगाने के लिए दोषी है, जो उस समय के आर्थिक वृद्धि के माहौल में तर्कसंगत थी। लेकिन ये 14 राज्य भी फरवरी-मार्च में अपने-अपने बजट में उम्मीद से अधिक राजस्व के अनुमान तय करने के लिए कम दोषी नहीं हैं, जबकि उस समय आर्थिक वृद्धि में गिरावट आनी शुरू हो गई थी। उन राज्यों को आत्ममंथन करने की जरूरत है, जिन्होंने एसजीएसटी संग्रह की वृद्धि में बढ़ोतरी की ऊंची दर तय की थी। ऐसे राज्यों में केरल ने 26 फीसदी, राजस्थान ने 23 फीसदी और पंजाब और मध्य प्रदेश ने 20-20 फीसदी वृद्धि का अनुमान लगाया था। इस बात पर गौर किया जाना चाहिए कि ये सभी राज्य वही हैं, जो सबसे ज्यादा शिकायत कर रहे हैं।

ये सवाल उन राज्यों की एसजीएसटी राजस्व वृद्धि के अनुमान में इस्तेमाल की जाने वाली प्रक्रियाओं को लेकर भी उठाया जाना चाहिए, जिन्होंने 2019-20 में संग्रह में कमी का अनुमान लगाया था। इन राज्यों में उत्तराखंड, गोवा, असम, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ शामिल हैं। उन्होंने किस वजह से एसजीएसटी संग्रह में कमी का अनुमान जताया, जबकि कुछ अन्य राज्यों को राजस्व वृद्धि में 25 से 27 फीसदी की बढ़ोतरी की संभावना नजर आ रही थी? यह समझना रोचक होगा कि क्यों गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना और तमिलनाडु जैसे राज्यों ने एसजीएसटी की वृद्धि दर 14 से 16 फीसदी रहने का अनुमान लगाया। जीएसटी परिषद को इन सभी मुद्दों की व्यापक पड़ताल करनी चाहिए और एक स्थिति रिपोर्ट पेश करनी चाहिए।

कानाफूसी

बिहार चुनाव के मद्देनजर!

केंद्रीय मंत्रिमंडल में बदलाव की चर्चा जोर पकड़ती जा रही है। माना जा रहा है कि 14 जनवरी के बाद बदलाव हो सकता है। इस बीच सबसे अधिक दबाव भाजपा के साझेदार जनता दल यूनाइटेड की ओर से आ रहा है। ध्यान रहे कि झारखंड में भाजपा को मिली शिकस्त की सबसे बड़ी वजह जदयू को ही माना जा रहा है। अभी यह तय नहीं है कि मंत्रिमंडल में पार्टी कितनी जगह चाहती है। सूत्रों का कहना है कि पार्टी को राज्य मंत्री के तीन पद मिल सकते हैं। इनमें से एक को स्वतंत्र प्रभार वाला मंत्री बनाया जा सकता है। जदयू की ओर से जो नाम सुर्खियों में हैं उनमें राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह और रामचंद्र सिंह के नाम प्रमुख हैं। इनके अलावा संतोष कुशवाहा और सी पी चंद्रवंशी के नाम भी चर्चा में हैं। गत वर्ष लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद पार्टी ने कैबिनेट में शामिल नहीं होने का फैसला किया था।

होगी वापसी?

झारखंड विधानसभा चुनाव में भारी पराजय के बाद भारतीय जनता पार्टी की राज्य इकाई में बदलाव की संभावना नजर आ रही है। पार्टी ने यह सबक तो सीख लिया है कि राज्य में गैर आदिवासी मुख्यमंत्री बनाना उसके लिए कारगर नहीं रहने वाला है। अब चर्चा यह है कि पार्टी बाबूलाल मरांडी को वापस लाना चाहती है। एक समय पार्टी का चेहरा और आरएसएस पदाधिकारी रहे मरांडी ने झारखंड विकास मोर्चा के नाम से अपनी पार्टी बना ली थी। कहा जा रहा है कि मोर्चा के दोनों विधायक कांग्रेस के साथ संपर्क में हैं और वे उसमें शामिल होना चाहते हैं। मरांडी भी भाजपा में वापसी की संभावनाओं को नकार नहीं रहे हैं। गौरतलब है कि पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुआ भी अपनी सीट नहीं बचा पाए थे। रघुवर दास को भाजपा के बागी नेता सरयू राय के हाथों भारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था।

आपका पक्ष

कश्मीर में इंटरनेट की आजादी

जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 के कुछ प्रावधान हटाने तथा जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने के बाद घाटी में कई तरह के प्रतिबंध लगाए गए। वहां इंटरनेट पर पाबंदी के साथ-साथ कई जगहों में कई दिनों तक धारा 144 तथा कर्फ्यू भी लगाया गया। राजनीतिक दलों के नेताओं को नजरबंद किया गया। सरकार का यह कदम घाटी में शांति बहाल करने के लिए तथा आतंकवादी गतिविधियों को रोकने, हिंसा-पथराव को रोकने के लिए उठाया गया था। हालांकि कश्मीर में प्रतिबंध के खिलाफ शीर्ष न्यायालय में याचिका दाखिल की गई थी जिस पर अदालत ने इंटरनेट को मौलिक अधिकार बताया। उसने धारा 144 को अत्यधिक जरूरत पड़ने पर ही लगाने की बात कही। जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने के बाद वहां शांति बहाल करने के प्रयास जारी हैं। वहां प्रतिबंध के बाद सेना पर पथराव की घटनाओं में कमी आई है। आज इंटरनेट हर किसी के लिए महत्त्वपूर्ण है लेकिन सोशल मीडिया के जरिये अफवाहें उड़ाई जाती हैं। भीड़ को हिंसा करने के लिए उकसाया जाता है। इसका उदाहरण नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा में देखने को मिला है। इसके लिए सरकार हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में कुछ समय के लिए इंटरनेट पर पाबंदी लगाती है जो उचित प्रतीत होता है। लेकिन घाटी में पिछले कई महीनों से इंटरनेट पर पाबंदी से आम लोगों को काफी नुकसान हो रहा था। ऐसे में सरकार को घाटी में सभी प्रकार की सुविधाएं बहाल करनी चाहिए और आतंकवादियों पर लगाम के लिए कोई अन्य रास्ता निकालना चाहिए।

कृष्णा दुबे, नई दिल्ली

सरकार के अनुसार कश्मीर में अब पथराव की घटनाओं में काफी कमी आई है

जनसंख्या नियंत्रण कानून की बारी

मोदी सरकार ने अपनी पहली और दूसरी पारी में कुछ ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। अब मोदी सरकार को देश की बहुत सी समस्याओं की जड़ बढ़ती जनसंख्या के लिए भी कानून लाना चाहिए। भारत जनसंख्या के मामले में दुनिया में दूसरे पायदान पर पहुंच गया है। लेकिन देश में इसी रफ्तार से जनसंख्या बढ़ती गई तो भारत जनसंख्या के मामले में चीन को भी पीछे छोड़ देगा। बढ़ती आबादी ने बहुत सी समस्याओं को जन्म दिया है। जनसंख्या वृद्धि के लिए गरीब या अशिक्षित लोग ही जिम्मेदार नहीं हैं, बल्कि पढ़े लिखे अमीर तबके के लोग भी जिम्मेदार हैं जो कई तरह की रूढ़िवादी मानसिकता के शिकार हैं। जब तक लोग जनसंख्या वृद्धि के दुष्परिणामों के प्रति जागरूक नहीं होंगे तब तक समस्याएं खत्म नहीं हो सकती है। कुछ गरीब लोग अपनी कमाई बढ़ाने के लिए ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं लेकिन उनकी कमाई तो नहीं बढ़जी बल्कि गरीबी बढ़ जाती है। गरीब लोगों को तो जनसंख्या वृद्धि के नकारात्मक असर के बारे में जरूर बताना चाहिए, ताकि वह देश में गरीबी के आंकड़े बढ़ाने में अपना योगदान नहीं दें। अब समय आ चुका है कि सरकार देश में बढ़ती जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाकर इसे गंभीरता से लागू करे और इस कानून में सभी धर्मों, जाति के लोगों को लाया जाना चाहिए। यहां यह कहना उचित होगा कि भारत में गरीबी का मुख्य कारण जनसंख्या वृद्धि भी है।

राजेश कुमार चौहान, जालंधर

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिजनेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in
पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

जनता पर कम हो कर का प्रहार, जीएसटी में हों जरूरी सुधार

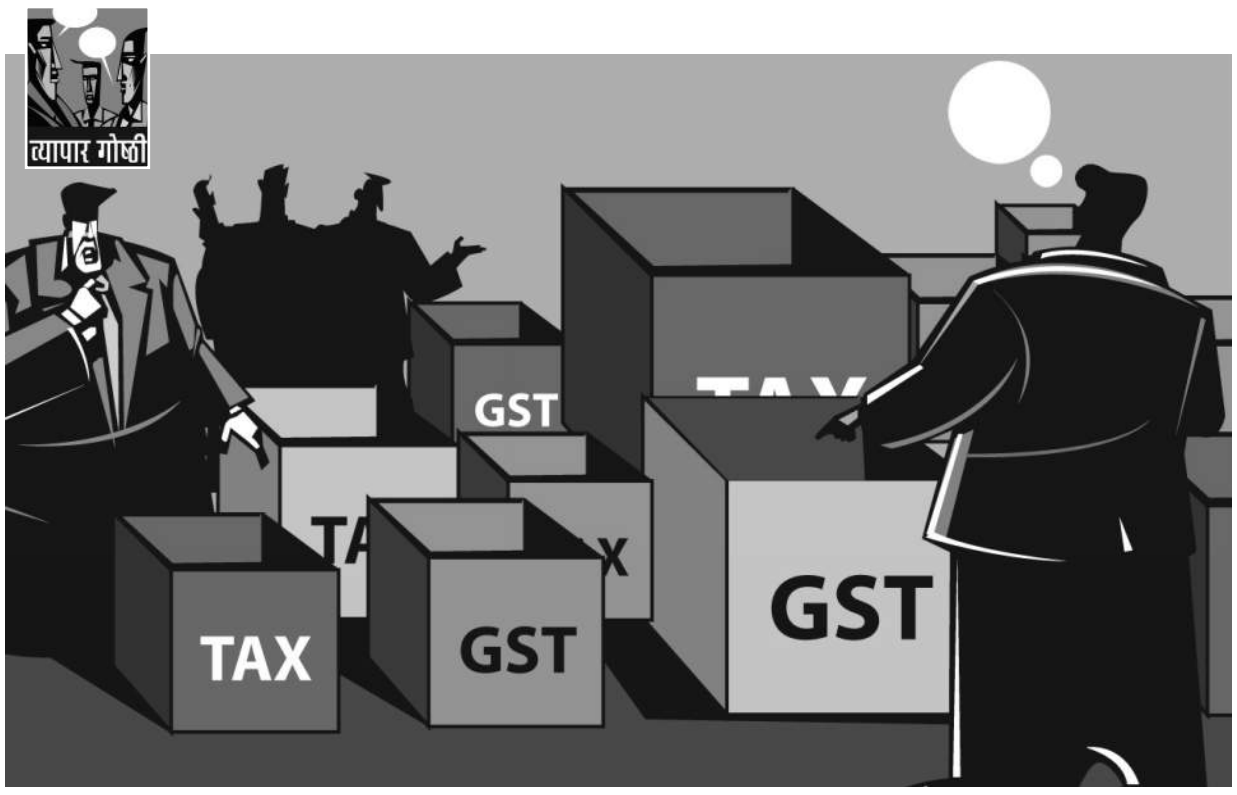

अजय मोहंती

मध्य व निम्न आय वर्ग को मिले राहत

अर्थव्यवस्था को सुधारने में करों की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। सभी क्षेत्रों में जिन घावों से अर्थव्यवस्था की स्थिति खराब हुई है, उन पर कर में राहत का मरहम लगाना जरूरी हो गया है। विभिन्न करों में कटौती कर अर्थव्यवस्था की स्थिति में बदलाव लाना आवश्यक है। करों में राहत के पश्चात इसकी वसूली प्रक्रिया भी सख्त व दुरुस्त होनी चाहिए। उच्च आय वर्ग के लिए करों में वृद्धि कर मध्यम व निम्न आय वर्ग को कर में राहत देकर उनकी क्रय व निवेश क्षमता को बढ़ाना आवश्यक है। विश्लेषकों के मुताबिक यदि व्यक्तिगत आयकर को समाप्त कर दिया जाए तो बचत में वृद्धि के साथ ही निवेश के प्रति रुचि जाग्रत होगी।

प्रदीप माथुर
अलवर, राजस्थान

करदाताओं में भरें उत्साह

करों को अगर ठीक ढंग से संग्रहित किया जाए तो इसके माध्यम से कई कार्य बड़ी आसानी से किए जा सकते हैं। लेकिन कर चोरी भारत में आम बात है। अर्थव्यवस्था वर्तमान में गोते लगा रही है और इसको बिना मजबूत किए हम भारत को एक शक्तिशाली और सक्षम अर्थव्यवस्था नहीं मान सकते। करों में सबसे महत्त्वपूर्ण बदलाव इसको लोचदार बनाया जाना है ताकि कोई इसकी उपेक्षा न करे और सभी उत्साह से कर भरें। जीएसटी दरें वस्तुओं की उपयोगिता को ध्यान में रखकर तय हो।

डॉ राम हर्ष गुप्ता
मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश

आम करदाता को मिले राहत

कंपनियों को कॉर्पोरेट कर में राहत देने के बाद अब केंद्र सरकार की ओर से मध्य वर्ग को भी आयकर दरों में बदलाव कर राहत दी जानी चाहिए। कार्यबल ने कर स्लैब में बदलाव कर मध्य वर्ग को भी राहत देने का सुझाव भी दिया है। खर्च करने योग्य आय में बढ़ोतरी और मध्यम वर्ग को राहत देने के लिए सरकार को व्यक्तिगत आयकर दरों को तर्कसंगत बनाने पर विचार करना चाहिए। 5 और 10 लाख रुपये के बीच कर योग्य आय वाले लोगों के लिए 10 प्रतिशत स्लैब पेश करना है। वर्तमान में यह स्लैब 20 प्रतिशत कर की दर को आकर्षित करता है। उपकर, अधिभार और कई कर दरों को हटाने और उच्चतम स्लैब की कर दर को 30 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत किया जाए। इससे खपत वृद्धि को बढ़ावा मिलेगा। सरकार ने कंपनियों को जो राहत दी है, इसका अगर वाकई कंपनियां इस्तेमाल नए पूंजीगत व्यय बढ़ाने या उत्पादों पर बड़े छूट देने में करेंगी तो निश्चित तौर पर इसका असर अर्थव्यवस्था में भी दिखेगा।

सुधीर कुमार सोमानी
देवास, मध्य प्रदेश

प्रगतिशील कराधान जरूरी

करारोपण सरकार की आय का महत्त्वपूर्ण स्रोत है। करदाता आयकर और कॉर्पोरेट कर के भार को ज्यादा महसूस करता है। इसलिए सरकार द्वारा प्रत्यक्ष करों को यथासंभव प्रगतिशील बनाने की चेष्टा की जाती है और कर इस प्रकार वसूल किया जाता है कि करदाता को न्यूनतम असुविधा हो। कॉर्पोरेट कर में कमी के बाद लोग आगामी बजट में आयकर में कमी की उम्मीद लगाए बैठे हैं। मंदी के लिए खपत में कमी को महत्त्वपूर्ण कारक माना जा रहा है। इसलिए खपत बढ़ाने हेतु बजट में करदाताओं को राहत देना हितकर होगा। जीएसटी आजादी के बाद का महत्त्वपूर्ण कर सुधार माना गया है। किंतु राजस्व संग्रह के उद्देश्य से यह बहुत ही सहायक नहीं रहा। इसमें पर्याप्त बदलाव की जरूरत है। रियल एस्टेट व पेट्रोलियम उत्पाद को जीएसटी के दायरे में लाने पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। करारोपण में इस बदलाव से अर्थव्यवस्था को सुधारने में मदद मिल सकती है।

डॉ. एम एस सिद्दीकी
फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश

दरों में कमी से होगी सुस्ती दूर

सितंबर 2019 में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कार्पोरेट कर में बड़ी कमी का ऐलान किया था। इसके जरिये उन्होंने कार्पोरेट जगत में खासा उत्साह बढ़ाकर यह सिद्ध कर दिया कि सरकार और वित्त मंत्रालय आर्थिक सुस्ती से निपटने हेतु दृढ़ संकल्पित है। अब सबकी नजर फरवरी में जारी होने वाले बजट और कर में छूट की तरफ है। सरकार की भी कोशिश यह रहेगी की खपत बढ़े और आर्थिक मंदी दूर हो। यदि बजट में करों में कटौती होती है तो इसका प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष फायदा देश के करीब तीन करोड़ करदाताओं को होगा। हो सकता है जीएसटी में भी कुछ बदलाव आने वाले समय में देखने को मिले।

संजय डागा हातोद
इंदौर, मध्य प्रदेश

केवल संशोधन हों, पूर्ण बदलाव नहीं

वर्तमान में कर इतना अधिक है कि कर चोरी विवशता बन चुकी है। अर्थव्यवस्था के लिए कर के आधार जीएसटी और आयकर में विभिन्न स्तरों पर संशोधन आवश्यक है। जीएसटी के तहत अत्यावश्यक व अनिवार्यताएं वाली वस्तुएं कर मुक्त हों या इन पर न्यूनतम कर दर हो। करों की संशोधित श्रृंखला में कर चोरी नहीं होने से अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी। आयकर दरों में भी संशोधन आवश्यक है क्योंकि अधिकतम दरों के कारण कर चोरी होती है। अधिकतम आय पर अधिकतम कर ही कर चोरी का मूल आधार है। कर दरों में संशोधित कर दरें ऐसी हों कि करदाता स्वयं ही चोरी न करें। इससे कर चोरी बंद होने से सरकार को अधिक कर मिलेगा और अर्थव्यवस्था न केवल संतुलित होगी, अपितु सुदृढ़ होगी। बदलाव केवल संशोधन के रूप में हो।

एम राज राकेश
अलवर, राजस्थान

खपत बढ़ाने को आयकर घटाना जरूरी

अर्थव्यवस्था के विकास की दर लगातार नीचे जा रही है। सरकार बढती महंगाई को भी नियंत्रित नहीं कर पा रही है। सरकार का कहना है कि चीजों की खपत कम हो रही है। अर्थव्यवस्था में बड़ा बदलाव नही हो रहा और गिरावट जारी है उसकी वजह ये है कि जुलाई के बजट के बाद सरकार ने जो कदम उठाए हैं वो संगठित क्षेत्र को लेकर हैं। असंगठित क्षेत्र के लिए कुछ खास नही हुआ। सरकार ने कॉर्पोरेट सेक्टर को 1.45 लाख करोड़ रुपये, बैंकों की हालत सुधारने के लिए 75 हजार करोड़ रुपये, रियल एस्टेट की हालत सुधारने के लिए 25 हजार करोड़ रुपये दिए गए लेकिन असंगठित क्षेत्र के लिए कुछ खास नहीं किया। सरकार को असंगठित क्षेत्र की मजबूती के लिए कुछ खास करने की जरूरत है जिससे आर्थिक गिरावट में कमी आ सके। आमदनी बढ़ाने का एक तरीका ये हो सकता है कि सरकार कर ढांचे की समीक्षा करे। व्यक्तिगत आय पर कर कम करने पर विचार किया जाए। इससे आने वाले पैसे को ग्रामीण क्षेत्रों में लगाया जाए जिससे किसानों को मदद मिलेगी, विकास दर बढ़ेगी और रोजगार के नए अवसर बनेंगे।

कुमारी कबिता
गोरखपुर, उत्तर प्रदेश

दूरदृष्टि से हो कर प्रणाली में बदलाव

अर्थव्यवस्था में तेजी व मंदी सामान्य पक्रिया है। आवश्यकता इस बात की है कि समझदारी पूर्वक व दूरगामी परिणाम को ध्यान में रखते हुए कर प्रणाली को बनाया जाए। यदि मंदी को ध्यान में रखकर कर दरों में कमी की जाती है तो सरकारी राजस्व में कमी होगी। परिणामत: सरकार को अपने खर्च में कटौती करनी पड़ेगी जिससे मंदी और गहरा सकती है। मंदी से निपटने के लिए कुछ राहत पैकेज दिए जा सकते हैं। किंतु करों में अत्यधिक कटौती जैसे कॉर्पोरेट कर में की गई कमी उपयुक्त उपाय नहीं हैं। अर्थव्यवस्था को गतिमान रखने और बृहद रोजगार सृजन के लिए सरकारी राजस्व भी उपयुक्त स्तर पर रखना चाहिए ताकि सरकार कुछ प्रगतिशील आर्थिक उपाय कर सके।

अजीत सिंह चौधरी
इंदौर, मध्य प्रदेश

मध्य वर्ग को मिले कर में सहूलियत

सरकार ने कॉर्पोरेट कर में कटौती करते हुए कॉर्पोरेट क्षेत्र को एक बड़ी मदद देने की कोशिश की। लेकिन, इसका भी भारतीय अर्थव्यवस्था पर कोई प्रभाव होता नहीं दिख रहा है। इससे भले ही कंपनियों के मुनाफे में सुधार हो जाए लेकिन इससे अर्थव्यवस्था में इस समय कमजोर मांग की समस्या दूर नहीं हो सकती है। ऐसे में सरकार को करों में ऐसे सुधार करने चाहिए जिससे मांग में सुधार हो। मांग तभी सुधर सकती है जब लोगों के पास पैसा हो। मांग बढ़ाने में भी अहम भूमिका मध्य आय वर्ग वालों की होगी। इसलिए सरकार को इस वर्ग को खासकर आयकर में बड़ी राहत देनी चाहिए। चाहे इसके लिए अमीरों से ज्यादा कर वसूला जाए। आयकर दरों में कॉर्पोरेट कर की तर्ज पर बड़ी कटौती की जरूरत है। सरकार को रोजगार बढ़ाने के उपाय भी करने चाहिए। नई नौकरियां पैदा होने से लोगों के हाथों में पैसा आएगा और वे इसे खर्च करेंगे जिससे बाजार में सामानों की खपत बढ़ेगी।

रविंद्र जैन
जयपुर, राजस्थान

करों में छूट से अर्थव्यस्था को पोषण

करों से होने वाले राजस्व को हम कमतर नहीं आंक सकते। जितनी भी सरकारी योजनाएं बनती हैं उनको कार्यान्वित करने में सभी प्रकार के कर बहुत ही सहायक होते हैं। पर इस समय सरकार का पूरा ध्यान अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने का होना चाहिए जिसके लिए जरूरी है कि वृहद अर्थशास्त्र के सिद्धांतों की जगह सूक्ष्म अर्थशास्त्र के नियमों का पालन करते हुए प्रति व्यक्ति आय को बढ़ावा दिया जाए। इसके लिए निम्न और मध्य आय वर्ग को करों में राहत देना चाहिए जिससे उनके बचत का हिस्सा बढ़े और उपभोक्तावाद भी बढ़े। उद्योगों को भी बढ़ावा दिया जाए और उद्यमिता को तो विशेष प्रोत्साहन दिए जाने पर ही अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ किया जा सकता है। प्रोत्साहन करों में छूट के रूप में भी हो सकती है।

डॉ आंजनेय गुप्ता
वाराणसी, उत्तर प्रदेश

जरूरी उत्पाद हों जीएसटी से बाहर

अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए कर सुधारों में कर से संबंधित जागरूकता, जीएसटी से बाहर रह गए उत्पादों को इसमें शामिल करना व कुछ अत्यावश्यक वस्तुओं को कर मुक्त करने की जरूरत है। जैसा कि सर्व विदित है कि जीएसटी के आने से करदाताओं की संख्या में वृद्धि हुई। कैश केडिंग प्रभाव भी खत्म हुआ, कई वस्तुओं के दामों में गिरावट देखी गई। लेकिन साथ ही छोटे कारोबारियों को जीएसटी में हो रहे लगातार बदलावों ने फजीहत में डाल दिया है जिसका कारण कर जागरूता में कमी, बुनियादी जरूरतों की अनुपलब्धता जैसे अप्रशिक्षित कर्मचारियों, ढांचागत विकास की कमी आदि है। पैकेट बंद दूध जैसे अत्यावश्यक वस्तुओं को भी कर मुक्त करना अत्यंत जरूरी है।

कृष्ण चंद्र त्रिपाठी
उज्जैन, मध्य प्रदेश

आयकर दरों को घटाये सरकार

अर्थव्यवस्था में लगातार सुस्ती का माहौल देखा जा रहा है। ऐसे में आगामी आम बजट अर्थव्यवस्था के लिए काफी महत्त्वपूर्ण साबित होने वाला है। मोदी सरकार ने आगामी आम बजट से पहले सुझाव मांगे हैं। सामान्य आयकरदाताओं के लिए आयकर दरों में कमी की मांग जोर पकड़ रही है। सरकार को कॉर्पोरेट कर की तरह सामान्य आयकर दरों में कमी करनी चाहिए क्योंकि अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए आम जन के हाथों में पैसा होना जरूरी है। ऐसा भारतीय अर्थव्यवस्था के उपभोग आधारित होने के कारण नितांत आवश्यक है। आयकर पक्रिया का सरलीकरण करना भी बहुत जरूरी है। जीएसटी परिषद को भी जीएसटी दरों में बदलाव कर अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ाने के प्रयास करने चाहिए। जीएसटी दरें कम रखने से कर चोरी पर अंकुश लग सकता है।

कल्पना माथुर
गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश

जीएसटी में हो व्यावहारिक बदलाव

सरकार ने कॉर्पोरेट करों में तो राहत दी है लेकिन इसका फायदा फर्म के रूप में काम करने वाले कारोबारियों को नहीं मिल पा रहा है। कारोबारी कह रहे हैं कि खरीदारों के पास पैसे की तंगी के कारण बाजार में मांग कमजोर है। ऐसे में अर्थव्यवस्था को सुस्ती से उबारने के लिए मांग बढ़ाना जरूरी है। इसके लिए एक तरफ सामान्य करदाताओं के लिए कर दरों में कमी कर उनकी बचत बढ़ाना जरूरी है। वहीं सुस्त कारोबार से परेशान कारोबारियों को राहत देने के लिए उच्च आयकर दरों में कमी करना भी बेहद आवश्यक है। उच्च श्रेणी में आने वाले कुछ उत्पादों पर जीएसटी दर घटनी चाहिए। सरकार को जीएसटी रिफंड के मामले जल्द निपटाने होंगे।

जयेंद्र सिंह
पटना, बिहार

बकौल विश्लेषक

अधिक पारदर्शी तथा सरल कर व्यवस्था बनाने से सुधरेगी स्थिति

वर्तमान में देश की गिरती अर्थिक सेहत ने एक बार फिर कर सुधारों पर ध्यान देने के लिए प्रेरित किया है, जिससे आर्थिक वृद्धि को बेहतर बनाया जा सके। हालांकि 'कर सुधार' आर्थिक सुधारों का केवल एक हिस्सा है लेकिन इसमें देश की अर्थव्यवस्था को दोबारा पटरी पर लाने की क्षमता है। सरकार ने कुछ समय पहले ही कॉर्पोरेट कर की दरों में कटौती की है जो सही दिशा में उठाया गया कदम है। केंद्र द्वारा गठित की गई विभिन्न समितियों ने आयकर कानून को सरल बनाने की अनुशंसा की है जिसके तहत विभिन्न छूट कम की जाएं और अनावश्यक प्रावधानों को हटाया जाए। प्रत्यक्ष कर संहिता को लाया जाना इस दिशा में बढ़ाया गया एक कदम है और आगामी बजट में इसका विस्तृत विश्लेषण उपलब्ध कराया जा सकता है। अधिकांश सामानों पर वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) की दरें प्रभावी स्तर तक लाने के लिए अनेक प्रयास किए गए। फिलहाल इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का लाभ उठाने एवं जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रियाओं को और सरल बनाया जाए। पेट्रोलियम उत्पादों तथा बिजली को जीएसटी के तहत लाने और जीएसटी की संरचना में कम दर वाली स्लैब में अधिकांश वस्तुएं लाने की आवश्यकता है। फिलहाल पेट्रोलियम उत्पादों तथा विद्युत को जीएसटी से बाहर रखा गया है लेकिन इनका उपयोग करने वाले उद्योग जीएसटी के तहत आते हैं। इससे कारोबार की लागत बढ़ जाती है क्योंकि वे आईटीसी का दावा नहीं कर पाते। इसी तरह, जीएसटी में चार दरें तथा कुछ उत्पादों पर सेस लगाया गया है जिसे और सरल बनाया जा सकता है। 12 प्रतिशत तथा 18 प्रतिशत वाली श्रेणी को मिलाकर 15 प्रतिशत की एक श्रेणी बनाई जा सकती है। इनपुट टैक्स क्रेडिट प्रक्रिया को सरल बनाने पर भी काम किया जाए। जीएसटी रिटर्न प्रक्रिया को कई बार बदला जा चुका है और अब सरकार को एक स्थायी प्रक्रिया निर्धारित करनी चाहिए जिससे छोटे कारोबारियों को परेशानी का सामना न करना पड़े। अगर देश की अर्थव्यवस्था 7-9 प्रतिशत की वृद्धि दर से आगे बढ़ती है तो इससे न सिर्फ कर संग्रह बढ़ेगा बल्कि अधिक रोजगार, उपभोग में वृद्धि एवं बुनियादी ढांचे में अधिक निवेश का मार्ग प्रशस्त होगा।

बातचीत: **वीरेश्वर तोमर**

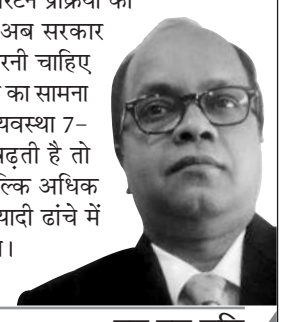

एम एस मणि
पार्टनर (अप्रत्यक्ष कर), डेलॉयट इंडिया

एक कुशल कर प्रणाली की अपेक्षा

पिछले एक वर्ष में अर्थव्यवस्था ने विभिन्न चुनौतियों और नए अवसरों को देखा है। भारतीय अर्थव्यवस्था भी वैश्विक विकास में सुस्ती के कारण कठिन दौर से गुजर रही है। अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए सरकार को कराधान के मोर्चे पर 22 प्रतिशत की कम नई कॉर्पोरेट कर दर का विकल्प चुनने वाली कंपनियों के लिए एमएटी क्रेडिट का कैरी फॉरवर्ड लाभ जारी रखना चाहिए। जिन कंपनियों ने एमएटी क्रेडिट को उपयोग नहीं किया है, उन्हें नई कर दरों के तहत कैरी फॉरवर्ड करने की अनुमति दी जानी चाहिए। यह मौजूदा कॉर्पोरेट्स के लिए फायदेमंद होगा और आने वाले समय में निवेश को बढ़ावा देगा। लाभांश आय 10 लाख से अधिक होने पर अतिरिक्त 10 प्रतिशत की लेवी को भी वापस लिया जाए। इसके अलावा, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स की प्रभावी दर को 10 प्रतिशत/15 प्रतिशत तक कम किया जा सकता है, ताकि कंपनियों के अंत में अधिक लिक्विडिटी (पूंजी तरलता) प्राप्त हो। आयकर कानून ने 54ईसी के तहत दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर बचत बांड के संबंध में प्रति निर्धारिती 50 लाख रुपये की सीमा निर्धारित की है। ऐसे बान्डों पर ब्याज आय पूरी तरह से कर योग्य है। इसलिए बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए इस सीमा को या तो हटा दिया जाना चाहिए या बहुत बढ़ा दिया जाए। शेयरों पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स 1 साल के बाद होल्डिंग पीरियड के लिए 10 प्रतिशत, 2 साल के बाद 5 प्रतिशत और 3 साल के बाद 0 प्रतिशत होना चाहिए क्योंकि जब एसटीटी लगाया गया था तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स से छूट मिली थी। सरकार को नई आयकर स्लैब दरों पर टास्क फोर्स की सिफारिश के अनुसार बदलाव करना चाहिए। इससे लोगों की आय में वृद्धि होने से बचत बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।। रेंटल हाउसिंग को प्रोत्साहित करने के लिए रियल एस्टेट डेवलपर्स को किराये के आवास से अर्जित लाभ पर 10 साल की छूट दी जाए। आर्थिक सुधारों का सिंक्रोनाइजेशन बहुत जरूरी है क्योंकि हम इस समय बहुत नाजुक मोड़ पर हैं। इसलिए केंद्रीय बजट 2020-21 में इन उपायों पर अमल से अर्थव्यवस्था और देश को सबसे अधिक लाभ होगा।

बातचीत: **रामवीर सिंह गुर्जर**

डॉ. डी. के. अग्रवाल
अध्यक्ष, पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स ऐंड इंडस्ट्री

पुरस्कृत पत्र

कर के आतंक से मिले छुटकारा

आचार्य चाणक्य ने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में प्रगतिशील कर व्यवस्था के बारे में कहा था कि कर की दरें तार्किक और उसकी वसूली का तरीका सहज होना चाहिए, तभी राज्य आर्थिक समृद्धि प्राप्त कर सकता है। दरअसल, वर्तमान कर व्यवस्था अनेक चुनौतियों का सामना कर रही है। जीएसटी लागू करके अप्रत्यक्ष कर सुधार की दिशा में कदम बढ़ाया गया। मगर अपनी कुछ तकनीकी खामियों के चलते यह अभी तक अपेक्षित परिणाम प्रस्तुत नहीं कर सका है। वर्षों से लंबित प्रत्यक्ष कर संहिता को शीघ्र ही मूर्त रूप देना चाहिए। सुधारों की कड़ी में ही कर-आधार को बढ़ाने के लिए कर स्लैब को बढ़ाया जा सकता है। भारतीय व विदेशी दोनों कंपनियों के लिए एक समान निगम-कर व्यवस्था हो। टैक्स टेररिज्म की स्थिति को टैक्स ह्यूमैनिज्म में परिवर्तित किया जाए, निरीक्षण की व्यवस्था फिजिकल के बजाय डिजिटल बने।

1

द्विजेंद्र कौशिक 'बटोही'
अलवर, राजस्थान

पुरस्कार राशि 500 रुपये

श्रेष्ठ पत्र

अनिल कोथुलकर
इंदौर, मध्य प्रदेश

आमूल चूल बदलाव की दरकार

नोटबंदी, जीएसटी और वैश्विक आर्थिक मंदी की वजह से आमजन और कारोबारी त्रस्त रहे जिसका व्यापक असर अर्थव्यवस्था पर हुआ। रियल एस्टेट कारोबार और वाहन उद्योग में भारी मंदी रही जिसके लिए सरकार को इन दोनों क्षेत्रों को आर्थिक पैकेज देना पड़ा। इसके बावजूद भी अर्थव्यवस्था डगमगा रही है। जीएसटी की जटिल प्रणाली से कारोबारी हैरान रहे। इनपुट क्रेडिट के लिए लाए गए प्रावधान को तुरंत स्थगित किए जाने की जरूरत है। मासिक विवरणी में की गई गलती को अगली विवरणी में सुधारने की सुविधा होनी चाहिए न कि दंड। आयकर की दरें और श्रेणियों में सुधार करने के साथ छूट सीमा को भी 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये किया जाए। उच्च आयकर दर घटकर 25 फीसदी हो।

दिव्या 'प्रीत' सेठी
नोएडा, उत्तर प्रदेश

न हो कर की दर में कोई फेरबदल

विगत वर्ष 2019 में कॉर्पोरेट कर तथा आयकर की दरों में बदलाव किए गए जिसकी वजह से बहुत से ऋणी लोगों के कर एक तरह से माफ ही हुए क्योंकि कर के बोझ के तले दबी कंपनियां कर का भुगतान करने में ढिलाई और ढुलमुल रवैया अपना रहीं थीं। आयकर तथा जीएसटी दोनों ही राजस्व और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में कारगर सिद्ध हो सकते हैं बस इसे सुचारू रूप से व्यवस्थित करने की जरूरत है। वैसे अभी आयकर की दरों में कोई भी फेरबदल करों के भुगतान में एक बहुत बड़ा अड़ंगा साबित हो सकता है क्योंकि देश की आर्थिक स्थिति को पुनर्जीवित किए जाने की कोशिश हो रही है। ऐसे में करों के उतार-चढ़ाव से जीडीपी, राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय और मुद्रास्फीति आदि के कारण अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी।

राजेश कुमार चौहान
जालंधर, पंजाब

जागरूकता अभियान की जरूरत

मोदी सरकार ने देश में आर्थिक कर में पारदर्शिता लाने के लिए जीएसटी जैसा कड़वा फैसला लिया था। लेकिन इसमें कुछ कमियां थी, जिनके कारण बार बार नियम बदलने पड़े थे। देश की आर्थिक व्यवस्था को सुधारने में कर प्रणाली का बहुत बड़ा योगदान होता है। लेकिन कर व्यवस्था में जनभागीदारी बढ़ाने के लिए और लोगों के दिल दिमाग से कर के प्रति रहने वाले खौफ को निकालने के लिए सरकार को प्रयास करने चाहिए। अगर सरकार देश के हरेक नागरिक को अच्छी व आधुनिक शिक्षा दे, बेरोजगारों को उनकी योग्यता के अनुसार भत्ता या नौकरी का इंतजाम करे और बुढ़ापे को सुरक्षित करने के लिए गंभीरता दिखाए तो आमजन भी करों को देने में रुचि दिखाएगा।

डॉ रसिकेश नवजात
जौनपुर, उत्तर प्रदेश

आयकर नहीं उपभोग कर लगाया जाए

वित्तीय वर्ष 2019-20 में पहले नौ महीनों के अंदर जो बदलाव सामने आए वह कॉर्पोरेट कर तथा आयकर के थे। लोगों को कर दायित्वों को पूरा करने के लिए आयकर की वर्तमान दरों में बदलाव की जरूरत है। अर्थव्यवस्था को अगर सुधार की दिशा में ले जाना है और लोगों को कर जमा करने के दायित्वों के प्रति प्रोत्साहित करना है तो आयकर की जगह उपभोग कर लगाया जाए। यह कर अधिक कारगर और लोकप्रिय होगा क्योंकि वस्तुओं का उपभोग तो बंद होगा नहीं जिसके फलस्वरूप राजस्व के रूप में एक बड़ी राशि भी एकत्रित होती रहेगी तथा कर चोरी करने वालों की जेबों पर उलटवार भी होगा। अर्थव्यवस्था में वस्तुओं की मांग व आपूर्ति के लिए भी उपभोग कर फायदेमंद साबित होगा।

... और यह है अगला मुद्दा

हर सोमवार को हम सम-सामयिक विषय पर व्यापार गोष्ठी नाम का विशेष पृष्ठ प्रकाशित करते हैं। इसमें आपके विचारों को प्रकाशित किया जाता है। साथ ही, होती है दो विशेषज्ञों की राय।

इस बार का विषय है - **सरकारी अस्पतालों की बदहाली कैसे हो दूर?**

अपनी राय अपने टेलीफोन नंबर और पूरे पते के साथ हमें इस पते पर भेजें: बिज़नेस स्टैंडर्ड (हिंदी), नेहरू हाउस, 4 बहादुरशाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली-110002

फैक्स नंबर- 011-3720201 या फिर ई-मेल करें goshthi@bsmail.in

जमानत राशि रोक सकता है मध्यस्थ पंचाट

एमजे एंटनी

उच्चतम न्यायालय ने पिछले सप्ताह व्यवस्था दी कि अगर किसी ठेकेदार का कोई काम जांच के दायरे में है तो मध्यस्थता पंचाट नियोक्ता को उसकी किसी अन्य परियोजना की जमानत राशि रोकने की अनुमति दे सकता है। न्यायालय ने गुजरात राज्य बनाम अंबर बिल्डर्स वाद में यह फैसला दिया। इस मामले में ठेकेदार ने गुजरात लोक कार्य अनुबंध विवाद मध्यस्थ पंचाट की शक्तियों को चुनौती दी थी। यह राज्य कानून कार्य के अनुबंधों पर विवादों पर मध्यस्थता को अनिवार्य बनाता है। ठेकेदार कंपनी ने एक सड़क बनाई थी लेकिन यह बारिश में बह गई। सरकार ने इसकी मरम्मत का जिम्मा नई कंपनी को दिया और पिछली कंपनी की जमानत राशि रोक दी। पुरानी कंपनी ने सरकार की इस कार्रवाई को उच्च न्यायालय में चुनौती दी। उच्च न्यायालय ने कंपनी के रुख को सही ठहराया जिसे राज्य सरकार ने उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी। उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालय के फैसले को खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि राज्य के कानून और केंद्र के कानून में कोई टकराव नहीं है और पंचाट अंतरिम आदेश जारी कर सकता है। उच्चतम न्यायालय ने साथ ही कहा कि एक अन्य मामले में पहले दिया गया फैसला गलत था। उस मामले में अदालत ने कहा था कि राज्य सरकार को अदालती फैसला आने से पहले ठेकेदार द्वारा दावा की गई जमानत राशि को रोकने का कोई अधिकार नहीं है।

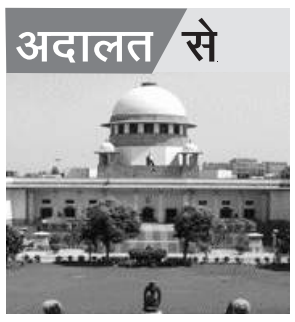

चेक के मामले में अग्रिम जमा वैध

बैंक खाते में पर्याप्त राशि के बिना चेक जारी करने की सजा पर रोक राशि के एक हिस्से का भुगतान करने की शर्त पर लगाई जा सकती है। उच्चतम न्यायालय ने पिछले सप्ताह सुरिंदर सिंह बनाम विरेंदर वाद में यह व्यवस्था दी। सुरिंदर और अन्य विरेंदर के साथ बुनियादी क्षेत्र की एक कंपनी में साझेदार थे। बाद में विरेंदर सेवानिवृत्त हो गए। सेवानिवृत्ति के बकाये के तौर पर कंपनी ने उन्हें 64 चेक जारी किए। इनमें से सभी बाउंस हो गए जिस पर मजिस्ट्रेट के समक्ष 28 शिकायतें दर्ज की गईं। दो साझेदारों को दोषी करार दिया गया और उन्हें दो साल जेल की सजा सुनाई गई। उन्हें पूरे बकाये का भुगतान करने को भी कहा गया। इसके खिलाफ उन्होंने सत्र न्यायाधीश में अपील की और सजा पर रोक लगाने की मांग की। अदालत ने मुआवजे के 25 फीसदी हिस्से के भुगतान की शर्त पर सजा पर रोक लगाने का आदेश दिया। उन्होंने इसका भुगतान नहीं किया और पहले उच्च न्यायालय तथा फिर उच्चतम न्यायालय में अपील की। दोनों जगह उन्हें निराशा हाथ लगी। फिर दूसरे दौर का मुकदमा चला और एक बार फिर उच्चतम न्यायालय ने उनकी अपील खारिज करते हुए उनकी सजा को बरकरार रखा।

बैंक गारंटी का पालन होना चाहिए

अगर बैंक गारंटी को भुनाने की शर्त अनुबंध में दी गई है तो फिर बैंक को यह तय करने का अधिकार नहीं है कि इसका इस्तेमाल करना सही है या नहीं। बैंक खुद यह फैसला नहीं कर सकता है कि किसी मामले में धोखाधड़ी या कोई अन्याय हुआ है। उच्चतम न्यायालय ने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक बनाम हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन वाद में यह फैसला दिया। बैंक द्वारा साइमन कार्व्स इंडिया लिमिटेड की तरफ से संयंत्र और उपकरण की आपूर्ति के अग्रिम के रूप में कॉरपोरेशन को दी गई दो बैंक गारंटियों पर विवाद हुआ। सामइन उपकरण की आपूर्ति करने में नाकाम रही और काम रुकने से भारी नुकसान हुआ। इस पर कॉरपोरेशन ने गारंटी को भुनाने की मांग की। जब बैंक ने ऐसा करने से मना किया तो मामला कलकत्ता उच्च न्यायालय में पहुंच गया जिसने इन्हें भुनाने की अनुमति दे दी। बैंक की अपील को उच्चतम न्यायालय ने खारिज कर दिया। न्यायालय ने कहा कि धोखाधड़ी या असाध्य अन्याय की गैरमौजूदगी में यह मामला अदालत के हस्तक्षेप के लायक नहीं है।

दोनों वाहन और बीमा कंपनियां बनें पक्ष

दो वाहनों की भिडंत के कारण हुई मौत के मामले में मुआवजे के दावे के लिए दोनों पक्षों और उनकी बीमा कंपनियों को पंचाट के समक्ष पक्ष बनाया जाना चाहिए। अन्यथा मुआवजे की राशि कम हो सकती है। उच्चतम न्यायालय ने पिछले सप्ताह रामखिलाड़ी बनाम यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी वाद में अपने फैसले में यह बात कही। इस दुर्घटना में मारे गए मोटरसाइकिल सवार की विधवा ने केवल वाहन का बीमा करने वाली कंपनी से मुआवजे का दावा किया। उन्होंने अपने पति की मोटरसाइकिल से टकराने वाली दूसरी बाइक की बीमाकर्ता कंपनी से मुआवजा नहीं मांगा। विधवा ने मोटर वाहन कानून की धारा 163 ए का सहारा लिया जिसके तहत मामले में शामिल सभी लोगों का पता लगाए बिना दावा किया जाता है। उन्होंने दूसरी बाइक के मालिक या चालक से मुआवजा नहीं मांगा। बीमा कंपनी ने दलील दी कि मृतक मुआवजा पाने का हकदार नहीं था क्योंकि उसने किसी और से वाहन मांगा था। पंचाट ने विधवा के पक्ष में फैसला दिया लेकिन राजस्थान उच्च न्यायालय ने इसे खारिज कर दिया। अपील पर उच्चतम न्यायालय ने विधवा को एक लाख रुपये का मुआवजा दे दिया जबकि विधवा ने संशोधित कानून के तहत 5 लाख रुपये के मुआवजे का दावा किया था। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि मुआवजा बढ़ाने का संशोधन घटना की तारीख के बाद किया गया था।

ओएनजीसी की अपील खारिज

बंबई उच्च न्यायालय ने सीजीजी सर्विसेज के साथ विवाद के मामले में पंचाट के फैसले को चुनौती देने वाली ऑयल ऐंड नैचुरल गैस कॉरपोरेशन की अपील खारिज कर दी है। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी ने दुनियाभर में जमीन और समुद्र के भौगोलिक आंकड़ों में विशेषज्ञता रखने वाली फ्रांसीसी कंपनी की सेवाएं ली थीं। भुगतान पर दोनों के बीच मतभेद हो गया और तीन सदस्यीय मध्यस्थता पंचाट ने खासकर न्यूनतम गारंटी कार्य के ज्वलंत सवाल पर फ्रांसीसी कंपनी के पक्ष में फैसला दिया। ओएनजीसी ने इसे उच्च न्यायालय में चुनौती दी लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। उच्च न्यायालय ने कहा कि किसी पंचाट के फैसले को तभी खारिज किया जा सकता है जब वह भारतीय कानून की बुनियादी नीति के खिलाफ हो या भारत के हित या न्याय या नैतिकता के विरुद्ध हो। न्यायालय ने कहा कि पंचाट ने निष्पक्ष कार्य किया और उसके फैसले में कोई अवैध बात नहीं है।

एसबीआई ने खोए गिरवी जमीन के कागज

राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग ने भारतीय स्टेट बैंक की अपील को खारिज कर दिया है। एक कारोबारी ने ऋण लेने के लिए बैंक में जमीन के कागज गिरवी रखे थे जिन्हें बैंक ने खो दिया। बैंक को काम में लापरवाही बरतने पर 5 लाख रुपये का मुआवजा देने को कहा गया। एसबीआई ने अमितेश मजूमदार को दस्तावेजों की एक प्रमाणित प्रतिलिपि देने, जमीन के कागज खोने की स्वीकारोक्ति के लिए एक दस्तावेज देने और इस बारे में अखबारों में प्रकाशन की पेशकश की थी। लेकिन आयोग ने कहा कि अगर वह अपनी जमीन बेचना चाहेगा तो ये सारे उपाय काम नहीं आएंगे। न्यायालय ने कहा, 'कोई भी मौजूदा बाजार कीमत का भुगतान करके ऐसी अचल संपत्ति नहीं खरीदना चाहेगा जिसके मूल दस्तावेज उसे नहीं मिलेंगे।'

कर विवादों को निपटाने में आगामी बजट से कैसे मिलेगी मदद

एक दमदार विवाद निपटान प्रणाली से सरकार को कर राजस्व जुटाने में मदद मिलेगी और इससे कारोबारी सुगमता भी बेहतर होगी

सुदीप्त दे और दिलाशा सेठ

कॉरपोरेशन कर दरों को तार्किक बनाए जाने के बाद भारतीय उद्योग जगत आगामी बजट में एक विश्वसनीय विवाद निपटान प्रणाली के खाके का इंतजार कर रहा है। उद्योग जगत को उम्मीद है कि इससे कर विवादों और मुकदमेबाजी को सक्रियतापूर्वक निपटाने का रास्ता साफ होगा। विवाद के मामले में कंपनियों की नजर अदालत के बाहर सुलह के लिए व्यवस्था में व्यापक निश्चितता और मुकदमेबाजी के लिए समयबद्ध प्रक्रिया पर होती है। आकलन वर्ष 2017-18 के अंत तक आयकर, सेवाकर और उत्पाद शुल्क से संबंधित कर विवादों की रकम बढ़कर 7,77,322 करोड़ रुपये तक पहुंच गई थी।

सबसे अधिक विवाद (70 फीसदी) आयकर आयुक्त (अपील) के साथ मुकदमेबाजी से संबंधित हैं जबकि करीब 20 फीसदी विवाद विभिन्न ट्रिब्यूनल में और शेष मामले उच्च न्यायालयों एवं सर्वोच्च न्यायालय में हैं। वर्ष 2018-19 की आर्थिक समीक्षा में उल्लेख किया गया है कि राजस्व विभाग सबसे बड़ा वादी है जबकि 65 फीसदी मामलों में उसे हार का सामना करना पड़ता है।

कर संबंधी मुकदमेबाजी पर लगाम लगाने के लिए सरकार कर विवादों में अपील दायर करने की सीमा को बढ़ाती रही है। पिछले साल केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने कर विवादों में अपील दायर करने की सीमा को आयकर अपीलीय ट्रिब्यूनल के लिए 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये, उच्च न्यायालयों के लिए 50 लाख रुपये से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये और सर्वोच्च न्यायालय के लिए 1 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपये कर दिया था।

ईवाई के पार्टनर एवं नैशनल टैक्स लीडर सुधीर कपाडिया के अनुसार, निपटान आयोग में मामलों को निपटाने की रफ्तार बढ़ाने की गुंजाइश है। निपटान आयोग में करीब 50 फीसदी मामले लंबित हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग (एएआर) में मामलों के निपटान में तेजी लाना महत्त्वपूर्ण है क्योंकि वहां कुछ मामले तीन-चार साल से लंबित पड़े हैं। जबकि कानून के तहत मामलों को छह महीने के भीतर निपटाने के निर्देश दिए गए हैं। कपाडिया ने कहा, 'इस एकमात्र उपाय से व्यापक निश्चितता सुनिश्चित करने और प्रणाली में संभावित विवादों को दूर करने में उल्लेखनीय मदद मिलेगी।'

अधिकारियों ने कहा कि सरकार कर मुकदमेबाजी कम करने के लिए करदाताओं और सीबीडीटी के बीच मध्यस्थता ढांचा तैयार करने की कोशिश कर रही है। इसके तहत करदाताओं को मसौदा आदेश जारी किए जाने से पहले आयुक्तों के एक समूह के समक्ष निपटान के लिए बातचीत शुरू करने का अवसर दिया जा सकता है। एक अधिकारी ने कहा, 'मध्यस्था व्यवस्था से करदाता और प्रशासन के बीच विश्वास बेहतर करने में मदद मिलेगी जिससे न केवल मुकदमेबाजी में कमी आएगी बल्कि अनुपालन बेहतर करने में भी मदद मिलेगी।' घरेलू विवाद समाधान पर संयुक्त राष्ट्र की समिति ने भी पिछले साल करदाताओं और कर अधिकारियों के बीच बातचीत के जरिये प्रशासनिक मध्यस्थता प्रक्रिया की वकालत की थी।

सूत्रों के अनुसार, सरकार एक अन्य उपाय पर विचार कर रही है जिसके तहत पूरी कर मुकदमेबाजी प्रक्रिया के प्रबंधन के लिए एक मुकदमा प्रबंधन इकाई स्थापित करने की बात कही गई है। इसमें अपील दायर करने की संबंधी निर्णय से लेकर किसी मामले में बचाव के लिए रणनीति तैयार करने तक की प्रक्रिया शामिल होगी। प्रत्यक्ष कर संहिता (डीटीसी) पैनल ने यह सुझाव दिया है।

सरकारी अधिकारियों ने कहा कि मूल्य हस्तांतरण मामलों के लिए एक अलग कार्यात्मक आकलन इकाई स्थापित की जा सकती है। उन्होंने कहा कि रिटर्न संशोधित करने के लिए जुर्माना माफ करने की योजना का उद्देश्य भी मुकदमेबाजी पर लगाम लगाना है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि कर विवादों पर लगाम लगाने के लिए कर कानून बनाने पर ध्यान देने की जरूरत है। बीएमआर लीगल के मैनेजिंग पार्टनर मुकेश भुटानी ने कहा, 'कारोबारियों के साथ उचित विचार-विमर्श के बिना कर कानूनों का मसौदा तैयार किया गया है और ऐसे में वे एकपक्षीय हैं।'

बहरहाल, सरकार को कर प्रशासन प्रणाली में सुधार से संबंधित मामलों में कुछ सख्त निर्णय लेने की जरूरत है। भुटानी ने कहा, 'कर प्रशासन संबंधी कार्यप्रणाली को कर नीति/प्रशासन एवं कर अनुपालन/कार्यान्वयन में बांटने की आवश्यकता है।' विशेषज्ञों का कहना है कि ये दोनों गतिविधियां राजस्व विभाग के तहत आने से हितों के टकराव की स्थिति पैदा हो जाती है। उन्होंने कहा कि कुछ मामलों में कर आकलन की देखरेख करने वाले अधिकारी ही कर नीति के लिए जिम्मेदार होते हैं।

विशेषज्ञों ने फील्ड ऑफीसर के लिए व्यापक जवाबदेही सुनिश्चित करने की आवश्यकता को उजागर किया ताकि वे आकलन एवं ऑडिट की भूमिका में कहीं अधिक न्यायसंगत हो सकें। इसी प्रकार, जब प्रथम अपील अधिकारी कानून एवं तथ्यों के आधार पर विवाद पर गौर करेंगे तो प्रणाली में व्यापक जवाबदेही सुनिश्चित करने की जरूरत है। भुटानी ने कहा, 'पिछले दो दशक के दौरान प्रथम अपील फोरम की भूमिका घटकर स्टांपिंग अधिकारी की रह गई है।'

जहां तक कर संधि विवादों का सवाल है तो विशेषज्ञ भारत में लंबी अदालती प्रक्रिया के दौरान संधि साझेदारों के निवास के पक्ष में नहीं हैं। भुटानी ने कहा, 'भारत को दोहरी कर संधियों के तहत विवादों से निपटने के लिए अनिवार्य मध्यस्थता प्रक्रिया को बेहतर करने के लिए संधि के तहत अपनी स्थिति पर नए सिरे से विचार करना चाहिए।'

कर प्रशासन सुधार आयोग ने भी आयकर अधिनियम में मध्यस्थता एवं सुलह प्रक्रिया को लागू करने की सिफारिश की है। विशेषज्ञों का कहना है कि तथ्यों के सामान्य प्रश्नों को सुलह के लिए भेजा जाना चाहिए जबकि कानून एवं तथ्य दोनों से संबंधित प्रश्नों को मध्यस्थता के लिए भेजा जाना चाहिए।

मध्यस्थता व्यवस्था
कर मुकदमेबाजी पर लगाम लगाने के लिए करदाताओं व सीबीडीटी के बीच मध्यस्थता

मुकदमेबाजी प्रबंधन
इकाई की स्थापना ताकि कर मुकदमेबाजी की पूरी प्रक्रिया पर नजर रखी जा सके

अलग कार्यात्मक
आकलन इकाई की स्थापना से मूल्य हस्तांतरण मामलों में मिलेगी मदद

इम्यूनिटी स्कीम
रिटर्न को संशोधित करने के लिए जुर्माना माफ करने पर हो सकती है चर्चा

विभिन्न कर विवादों में फंसी रकम
(आकलन वर्ष 2017-18 के अनुसार) *करोड़ रुपये में*

आय एवं व्यय पर कर	**623,539**
कॉरपोरेशन कर	399,188
कॉरपोरेशन कर के इतर आय पर लगने वाला कर	224,351
जिंस एवं सेवा पर कर	**153,783**
सीमा शुल्क	10,401
केंद्रीय उत्पाद शुल्क	55,317
सेवा कर	88,065
कुल	**777,322**

स्रोतः बजट रिसीट, 2019-20

अपील के लंबित मामले

सीआईटी (ए): आयकर आयुक्त-कर (अपील), आईटीएटीः आयकर अपील ट्रिब्यूनल, एचसीः उच्च न्यायालय, एससीः सर्वोच्च न्यायालय

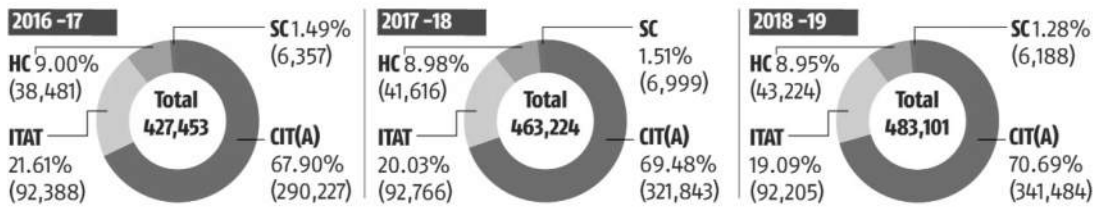

संकलनः ईवाई स्रोतः राज्य सभा में सवाल-जवाब, दिनांकः 23 जुलाई 2019

विदेशी फंड को भारत के अनुकूल बनाने की उम्मीद

भारतीय फंड मैनेजरों के लिए विदेशी फंड को आसान बना सकता है आगामी केंद्रीय बजट

ऐश्ली कुटिन्हो

आगामी केंद्रीय बजट भारत केंद्रित विदेशी फंडों को भारत लाने की कोशिश करने वाले फंड मैनेजरों की राह आसान करने के उद्देश्य से नियमों में फेरबदल कर सकता है।

1 अप्रैल 2016 से लागू आयकर अधिनियम की धारा 9ए के तहत इस प्रकार के फंडों के लिए एक विशेष कराधान प्रणाली मुहैया कराई गई है। इसके तहत किसी पात्र निवेश फंड की फंड प्रबंधन गतिविधि का भारत में कारोबारी जुड़ाव नहीं होगा। उस फंड को केवल इस वजह से भारतीय नहीं माना जाएगा कि उसका फंड मैनेजर भारत में है।

आयकर अधिनियम में इस धारा को शामिल करने का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि भारत के बाहर प्रबंधित विदेशी फंड को किसी वृद्धिशील कर का भुगतान न करना पड़े। इस धारा के बिना भारत से प्रबंधित होने वाले विदेशी फंड को भारत में कराधान का सामना करना पड़ता था। पीडब्ल्यूसी इंडिया के पार्टनर तुषार सचाडे ने कहा, 'इस स्थिति में उसे संधि के सभी संभावित लाभ से वंचित होना पड़ेगा और 10 लाख रुपये से अधिक की लाभांश आय के लिए 10 फीसदी अतिरिक्त कर का भुगतान करना पड़ेगा।'

आयकर अधिनियम की धारा 9ए के तहत किसी विदेशी फंड के फंड मैनेजर को परिचालन संबंधी अधिक आजादी दी गई है। ध्रुव एडवाइजर्स के पार्टनर सौमिल शाह ने कहा, '25 फीसदी निवेशी कंपनी संबंधी पाबंदियां लागू नहीं होंगी और विदेशी निवेश से पहले सेबी की मंजूरी की जरूरत नहीं होगी।' उन्होंने कहा कि विदेशी फंड द्वारा भुगतान किए जाने के मामले में प्रबंधन शुल्क पर जीएसटी लागू नहीं होता है।

पिछले साल बजट में धारा 9ए के तहत दो मामूली शर्तों को आसान बनाया गया था। पहला, फंड के शुरू होने से लेकर पिछले साल के खत्म होने अथवा छह महीने में से जो भी बाद हो, तक 100 करोड़ रुपये की निधि तैयार करने की समयावधि में छूट दी गई। दूसरा, किसी फंड द्वारा फंड मैनेजर को दिए जाने वाले पारिश्रमिक को बाजार के चलन से कम न होने के प्रावधान को खत्म कर दिया गया और उसे सीबीडीटी द्वारा न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारित करने का प्रस्ताव दिया गया।

हालांकि अभी कुछ ही फंडों को धारा 9ए के तहत निर्देश दिए गए हैं। लेकिन एक महत्त्वपूर्ण आवश्यकता यह है कि भारत में निवास करने वाले व्यक्तियों का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष तौर पर कुल निवेश फंड की निधि की 5 फीसदी से अधिक नहीं होनी चाहिए।

विशेषज्ञों ने कहा कि उन मामलों में जहां पात्र निवेश फंड ओपन-एंडेड फंड हो अथवा विदेशी स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध हो तो भारतीय निवासियों की भागीदारी का सत्यापन व्यावहारिक तौर पर असंभव होता है। शाह ने कहा, 'मौजूदा दिशानिर्देशों से अप्रत्यक्ष शब्द को हटाकर निवासियों द्वारा फंड में अप्रत्यक्ष भागीदारी को खत्म करना चाहिए।'

सचाडे के अनुसार, अधिकतर विदेशी फंडों में निवेशक के तौर पर भारतीय नहीं हैं। उन्होंने कहा, 'वास्तव में मुझे लगता है कि जब तक एनआरआई को विशेषतौर पर फंड की मार्केटिंग नहीं की जाएगी तब तक 5 फीसदी की सीमा को पार नहीं किया जा सकता है।' मौजूदा प्रावधानों के तहत कहा गया है कि धारा 9ए का लाभ हासिल करने वाले फंड का परिचालन शुरू होने से पहले वर्ष के भीतर न्यूनतम निधि 100 करोड़ रुपये होनी चाहिए। जबकि उद्योग जगत का कहना है कि इस समय-सीमा को बढ़ाकर 5 वर्ष किया जाना चाहिए।

एवेंडस कैपिटल पब्लिक मार्केट्स अल्टरनेट स्ट्रैटेजिज के सह-सीईओ वैभव सांघवी ने कहा, 'यदि किसी फंड का स्थापित विदेशी ट्रैक रिकॉर्ड न हो तो उसके लिए पहले वर्ष के भीतर 100 करोड़ रुपये की निधि तैयार करना कठिन है।'

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि धारा 9ए के तहत विशेष कर लाभ की पेशकश किए बिना एफपीआई पर अतिरिक्त पाबंदियां लगाई गईं तो एफपीआई भारतीय फंड मैनेजरों की सेवाएं नहीं लेंगे। शाह ने कहा, 'इसे स्पष्ट किया जाना चाहिए कि पात्रता शर्तें एफपीआई पर लागू नहीं होंगी और सेबी में पंजीकृत एफपीआई द्वारा किसी भारतीय फंड मैनेजर की नियुक्ति से मौजूदा कर ढांचे में कोई बदलाव नहीं होगा।'

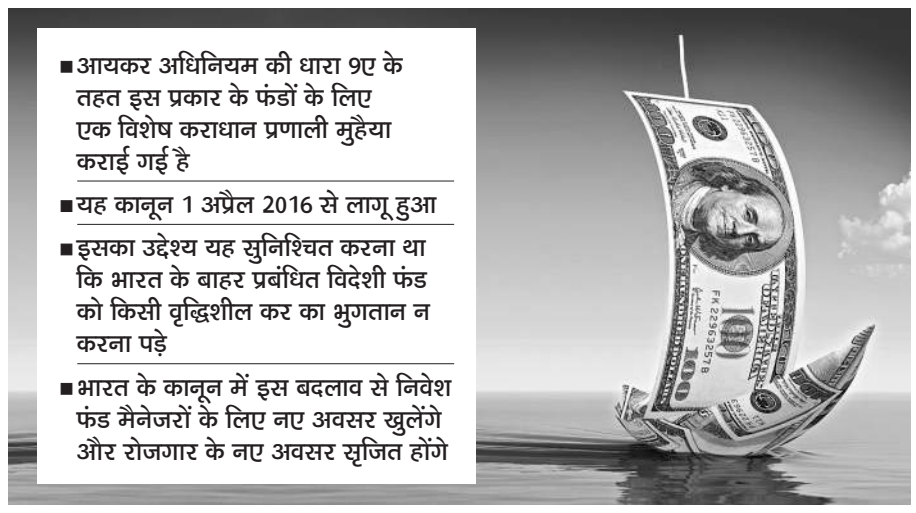

पृष्ठ 1 का शेष...

गैर-सूचीबद्ध फर्मों के लिए आएगी अधिग्रहण संहिता

विशेषज्ञों के अनुसार अधिग्रहण संहिता के सूचीबद्ध होने के बाद उदाहरण के तौर पर टाटा ट्रस्ट्स जैसी इकाइयां जिसकी टाटा संस में 66 फीसदी हिस्सेदारी है, वह समूह की अन्य कंपनियों के साथ इस प्रावधान का उपयोग कर 75 फीसदी हिस्सेदारी हासिल करने का विकल्प अपना सकती है और अल्पांश शेयरधारकों की हिस्सेदारी लेने के लिए एनसीएलटी में जा सकती है। हालांकि इस तरह के अधिग्रहण की लागत काफी ज्यादा हो सकती है।

एनसीएलएटी के अनुमान के अनुसार टाटा संस की अल्पांश शेयरधारक शापूरजी पलोनजी के पास 18 फीसदी हिस्सेदारी है, जिसका वर्तमान मूल्य करीब 1 लाख करोड़ रुपये है। इस बीच, केंद्रीय विधि मंत्रालय प्रस्तावित अधिग्रहण संहिता का अध्ययन कर रहा है।

कॉरपोरेट प्रोफेशनल्स में पार्टनर अंकित सिंघी ने कहा, 'वर्तमान में गैर सूचीबद्ध कंपनियों का अधिग्रहण नियमकीय मंजूरी के दायरे में नहीं आता है। सरकार अधिग्रहण के मामले में अल्पांश शेयरधारकों को बहुलांश शेयरधारकों की तरह ही अपने शेयर बेचने की सहूलियत दे सकती है, औरयह एनसीएलटी की अनुमति पर निर्भर करेगा।'

वर्तमान में सेबी द्वारा अधिसूचित अधिग्रहण संहिता केवल सार्वजनिक सूचीबद्ध कंपनियों पर ही लागू होता है। इसके मुख्य मकसद में से एक छोटे शेयरधारकों के हितों की रक्षा करना है।उद्योग से जुड़े विशेषज्ञों का कहना है कि नीति के तहत बाजार संचालित कॉरपोरेट नियंत्रण होना चाहिए और सरकार का हस्तक्षेप ककेवल इस तरह की व्यवस्था के विफल रहने पर ही होना चाहिए।

शार्दुल अमरचंद मंगलदास में वरिष्ठ रिसर्च फेलो प्रतीक दत्ता ने कहा, 'अल्पांश शेयरधारकों के हितों की रक्षा के लिए सरकार के नियमन से बाजार पर कॉरपोरेट नियंत्रण को समृद्ध करने में ही मदद करेगा। हमें इस पहलू से अधिग्रहण के नियमन की जरूरत पर विचार करना चाहिए, खास तौर पर तब जब अल्पांश शेयरधारकों की सुरक्षा के लिए पहले से ही वैकल्पिक कानूनी प्रणाली उपलब्ध है।'

कंपनी अधिनियम की धारा 237 में कहा गया है कि अगर अधिग्रहणकर्ता के पास एकीकरण, शेयरों की अदला-बदली, प्रतिभूति में बदलाव या अन्य वजहों से कुल जारी शेयर पूंजी का 90 फीसदी हिस्सेदारी हो जाती है, तो उन्हें कंपनी को शेष शेयर खरीदने के बारे में सूचित करना होगा। इस तरह के अधिग्रहण में अधिग्रहणकर्ता को पंचाट में नहीं जाना होता है। 90 फीसदी शेयर होने पर उसके पास अन्य शेष शेयर खरीदने का अधिकार होता है।

प्रस्तावित संहिता के तहत 75 फीसदी हिस्सेदारी वाला अन्य अल्पांश शेयरों को खरीदने के लिए पंचाट में जा सकता है। अधिकारी ने कहा, 'हम सभी शेयरधारकों के हितों की रक्षा करना चाहते हैं। पंचाट यह देखेगा कि पेशकश अल्पांश शेयरधारकों के लिहाज से पर्याप्त है या नहीं।'

पृष्ठ 1 का शेष...

फिर आएगी रियायत योजना!

विभाग को इस सीमा से नीचे की राशि के मामलों में अपील दायर नहीं करने और इस कर प्रभाव से नीचे के मामलों में अपील वापस लेने को कहा गया है। आय कर विभाग के लिए पंचाट के समक्ष अपील हेतु कर प्रभाव सीमा को 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये, उच्च न्यायालय के लिए 50 लाख रुपये से बढ़ाकर एक करोड़ रुपये और उच्चतम न्यायालय के लिए एक करोड़ रुपये से बढ़ाकर दो करोड़ रुपये कर दी गई थी। नए कर प्रभाव परिपत्र के जारी होने के बाद विभाग ने बड़ी संख्या में लंबित अपीलों को वापस ले लिया है।

अप्रत्यक्ष कर के लिए माफी योजना की सफलता भी उत्साहजनक रही है जिससे केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड को 30,000 से 35,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व हासिल हो चुका है। सरकार ने पिछले साल सितंबर में सबका विश्वास विरासत विवाद समाधान योजना शुरू की गई थी और इसमें उत्पाद एवं सेवा कर से जुड़े विवाद और देनदारियां शामिल की गई हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार सबका विश्वास विरासत विवाद समाधान योजना की तर्ज पर प्रत्यक्ष कर के लिए माफी योजना पर विचार कर सकती है। ईवाई में पार्टनर और नैशनल टैक्स लीडर सुधीर कपाड़िया ने कहा, 'अगर प्रत्यक्ष कर समाधान योजना में ब्याज और जुर्माना माफ कर दिया जाता है और विवादित राशि के 50 फीसदी हिस्से के भुगतान का विकल्प दिया जाता है तो करदाता इसे हाथोंहाथ ले सकते हैं।'

ऐक्सिस बैंक में चौधरी के लिए उतार-चढ़ाव भरा दौर

एमडी और सीईओ के तौर पर उनके पहले साल में रिटेल परिसंपत्तियों की बेहतर भागीदारी, बट्टाखाता संबंधित मानकों में सुधार सकारात्मक था, लेकिन परिसंपत्ति गुणवत्ता में ज्यादा तेज गति से सुधार नहीं आना चिंताजनक रहा

हंसिनी कार्तिक

जब अमिताभ चौधरी ने पिछले साल जनवरी में ऐक्सिस बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्याधिकारी की कमान संभाली थी तो बाजार को उनसे बड़ी उम्मीदें थीं। एक साल बाद न सिर्फ इस बैंक के शेयर में 18 प्रतिशत तक की तेजी आ चुकी है बल्कि यह सही दिशा में भी तेजी से बढ़ रहा है। इसके अलावा, तीन अन्य कारकों का भी बैंक के लिए अनुकूल योगदान रहा है। इनमें उसके खुदरा ऋणों में सुधार, बट्टेखाते से संबंधित बेहतर व्यवस्था और आय की बेहतर गुणवत्ता शामिल हैं।

रिटेल परिसंपत्तियों में वृद्धि

रिटेल परिसंपत्तियों पर ध्यान केंद्रित करने से सेगमेंट को 20 प्रतिशत से ज्यादा वृद्धि दर्ज करने में मदद मिली और ताजा आंकड़ों के अनुसार उसकी भागीदारी सितंबर तिमाही में बढ़कर 52 प्रतिशत हो गया। इसके अलावा, जो अन्य उत्साहजनक कारक है, वह यह कि ज्यादातर सुधार सुरक्षित ऋणों (खासकर आवास ऋण) की भागीदारी बढ़ने से आया है जिसका योगदान खुदरा ऋणों में 37 प्रतिशत है। भले ही असुरक्षित ऋण सुरक्षित ऋणों की तुलना में तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन रिटेल से संबंधित अंतर ऋण बुक के 1.5 प्रतिशत से कम है, जो 2-2.5 प्रतिशत के उद्योग मानक से नीचे है। इसके अलावा, रिटेल परिसंपत्तियां भी कॉरपोरेट ऋणों की तुलना में तेजी से बढ़ रही हैं और ऐक्सिस बैंक की शुल्क आय में रिटेल ऋणों का योगदान दूसरी तिमाही में 64 प्रतिशत दर्ज किया गया, जो अब तक सबसे ज्यादा है। जब कड़ी प्रतिस्पर्धा बरकरार है और बैंकों की मूल्य निर्धारण ताकत सीमित हो रही है, शुल्क आय से योगदान में वृद्धि एक सकारात्मक कदम है। रिटेल ऋणों के अलावा, खुदरा जमाओं की भागीदारी 46 प्रतिशत से बढ़कर बढ़कर कुल जमाओं के 60 प्रतिशत पर पहुंच गई है। इन जमाओं को मियादी जमाओं से मदद मिली। ये जमाएं बड़ी जमाओं के मुकाबले ऊंची कूपन दर से जुड़ी हुई हैं। अन्य पहलू यह है कि ऐक्सिस बैंक सस्ती सीएएसए जमाओं पर पकड़ खो रहा है और इनकी भागीदारी एक पहले के 47 प्रतिशत से घटकर दूसरी तिमाही में 41 रह गई है।

बट्टेखाते की प्रक्रिया

वित्त वर्ष 2017 में शुरू हुई इस प्रक्रिया को बरकरार रखते हुए बैंक ने 'ए' और उससे ऊपर की रेटिंग वाले ग्राहकों के लिए उधारी पर अपना ध्यान बढ़ाया है। अपेक्षाकृत कम जोखिम से जुड़े इन ऋणों की भागीदारी दूसरी तिमाही में बढ़कर 80 प्रतिशत हो जाने से संकेत मिलता है कि ऐक्सिस बैंक के कॉरपोरेट ऋणों से संबंधित संभावित समस्याएं पहले की तुलना में कम हो सकती हैं। हालांकि इसका यह मतलब नहीं है कि परिसंपत्ति गुणवत्ता की समस्या पूरी तरह समाप्त हो चुकी है। दरअसल, जहां शुद्ध निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) अनुपात दूसरी तिमाही में पिछले साल के 2.54 प्रतिशत से घटकर 1.99 प्रतिशत रह गया, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक की तुलना में परिसंपत्ति गुणवत्ता में सुधार की रफ्तार काफी धीमी (एक साल पहले के 3.65 प्रतिशत की तुलना में दूसरी तिमाही में 1.6 प्रतिशत) पड़ी है। इसके अलावा कम निवेश ग्रेड वाले बहीखाते से दबाव भी ऐक्सिस बैंक के लिए बना हुआ है। इससे उसकी शेयर कीमत पर भी कुछ हद तक दबाव पड़ रहा है। ऐंजल ब्रोकिंग के विश्लेषकों का कहना है, 'हमारा मानना है कि बैंक की ऋण लागत तब तक ऊंचे स्तर पर बनी रहेगी जब तक कि कुल फंसे कर्ज की पहचान एनपीए के तौर पर नहीं हो जाती।' ऐंटीक स्टॉक ब्रोकिंग के विश्लेषकों को वित्त वर्ष 2021 तक ऋण लागत सामान्य हो जाने का अनुमान है।

वर्ष 2020 में ऐक्सिस के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्याधिकारी अमिताभ चौधरी के लिए विकास की रफ्तार बनाए रखना बड़ी चुनौती है

बेहतर आय प्रोफाइल

खुदरा ऋणों की रफ्तार मजबूत बनी हुई है और परिसंपत्ति गुणवत्ता पर दबाव धीरे धीरे घट रहा है। वहीं आय की गुणवत्ता में भी पिछले साल सुधार आया। जहां वित्त वर्ष 2019 में पूंजी पर प्रतिफल (आरओई) 7.3 प्रतिशत पर था, वहीं वित्त वर्ष 2020 में यह सुधरकर 7.8 प्रतिशत हो गया है। जहां शुद्ध ब्याज मार्जिन दिसंबर 2018 के अंत में 3.4 प्रतिशत से सुधरकर वित्त वर्ष 2020 की दूसरी तिमाही में 3.5 प्रतिशत हो गया। इससे प्रतिस्पर्धा के बावजूद अपनी मूल्य निर्धारण ताकत मजबूत बनाने की बैंक की क्षमता का संकेत मिलता है।

कुल मिलाकर, कार्यालय में पहला वर्ष चौधरी के लिए अच्छा रहा है। रिटेल और कॉरपोरेट सेगमेंट्स में वृद्धि की रफ्तार इस साल बनाए रखना उनके लिए चुनौतीपूर्ण है। वित्त वर्ष 2021 के 2 गुना पर कारोबार कर रहे ऐक्सिस बैंक के शेयर ने निवेशकों को अच्छा अवसर दिया है। लेकिन आपको परिसंपत्ति गुणवत्ता दबाव को ध्यान में रखे जाने की जरूरत होगी।

बाजार हलचल

बजट में सामान्य केवाईसी चाहते हैं फंड

म्युचुअल फंड उद्योग का मानना है कि सरकार आम बजट में एक सामान्य केवाईसी (अपने ग्राहक को जानिए) ढांचे के लिए प्रावधान पेश करेगी। एक फंड हाउस के अधिकारी ने कहा, 'इससे उद्योग को बैंकों को पहले से दिए गए मौजूदा केवाईसी विवरण का इस्तेमाल करने की अनुमति मिलेगी, जिससे नए ग्राहकों को जोड़ना आसान होगा।' उद्योग ने 10 साल में 100 लाख करोड़ रुपये की परिसंपत्तियों का लक्ष्य रखा है और जानकारों का मानना है कि एक सामान्य केवाईसी इस उद्योग का आकार मौजूदा 26 लाख करोड़ रुपये से चार गुना बढ़ाने के लिए बेहद जरूरी होगा। *– जश कृपलानी*

बजट में एलटीसीजी से राहत की उम्मीद!

बजट नजदीक है और उद्योग को उम्मीद है कि सरकार एक साल बाद शेयर की बिक्री पर लगने वाले 10 प्रतिशत के दीर्घावधि पूंजीगत लाभ (एलटीसीजी) कर को समाप्त करेगी या इसमें कुछ कमी करेगी। बाजार कारोबारियों का कहना है कि इससे संस्थागत पूंजी प्रवाह, खासकर विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों से निवेश बढ़ेगा। यह भी उम्मीद है कि 20-35 प्रतिशत के लाभांश वितरण कर डीडीटी) को तर्कसंगत बनाया जाएगा। डीडीटी मुनाफे से लाभांश पर लगने वाला कर है और इसे कंपनी द्वारा चुकाया जाता है। 2017 में 10 लाख रुपये सालाना से अधिक की लाभांश आय के लिए करदाताओं पर 10 प्रतिशत का अतिरिक्त आय कर लगाया गया था। *– ऐश्ली कुटिन्हो*

अमेरिका-चीन सौदे से वाहन कलपुर्जा निर्माताओं को उम्मीद

राम प्रसाद साहू

पिछले लगभग तीन हफ्तों से वाहन कल-पुर्जा निर्माता कंपनियों के शेयर घरेलू बाजार में अपने प्रतिस्पर्द्धियों के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन करते आ रहे हैं। मदरसन सूमी, भारत फोर्ज और बालकृष्ण इंडस्ट्रीज जैसे शेयरों में 14 प्रतिशत तक तेजी आई है। वाहन कंपनियों में टाटा मोटर्स का शेयर भी 18 प्रतिशत तक उछला है। टाटा मोटर्स देश की दिग्गज वाहन कंपनी है, जिसकी विदेशी बाजारों में भी गहरी पैठ है।

अमेरिका और चीन के बीच पहले चरण के व्यापार समझौते को मंजूरी इन शेयरों में तेजी की एक प्रमुख वजह मानी जा रही है। इससे उन कंपनियों को खासी राहत मिली है, जो वैश्विक स्तर पर वाहन बाजार से जुड़े हुए हैं। एक घरेलू ब्रोकरेज कंपनी के विश्लेषक ने कहा कि चीन कारोबार करने और मुनाफा अर्जित करने दोनों के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है। उन्होंने कहा कि चीन के वाहन बाजार में कारोबार सुधरने से वाहन कंपनियों और उनके कल-पुर्जा आपूर्तिकर्ताओं को लाभ होगा। हालांकि समझौते की महीन बातों की औपचारिक घोषणा 15 जनवरी को होगी, विश्लेषकों का मानना है कि मांग की हालत में दीर्घकालिक सुधार के लिए व्यापार समझौता पहला कदम है। चाइना ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन के अनुसार चीन में कमजोर माहौल के कारण कंपनियों एवं वितरकों के पास जमा वाहनों का जखीरा भी अब कम होने लगा है। चीन में नए उत्सर्जन नियम-शर्तें लागू होने से अगली दो तिमाहियों में स्थिति और सुधर जाएगी।

यूरोपीय बाजार में हालत सुधरने की उम्मीदों से भी इन शेयरों में तेजी दिखी है। जेएम फाइनैंशियल के विश्लेषक कहते हैं,'ब्रेक्सिट से जुड़ी अनिश्चितता समाप्त होने, अमेरिका-चीन में समझौते की पहल और यूरोपीय संघ के देशों में नियामकीय मुद्दों के समाधान साथ ही बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन एवं हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कारों के खंड में नए उत्पाद आने से अगला साल कैलेंडर वर्ष 2019 के मुकाबले बेहतर रह सकता है। इस लिहाज से मदरसन सूमी और टाटा मोटर्स को यूरोपीय संघ में सुधार से सर्वाधिक लाभ मिलेगा।'

अमेरिका और चीन के बीच समझौते और यूरोपीय बाजार में स्थिति में बदलाव आने से कई शेयरों में आई है शानदार तेजी

न्यू रियल ड्राइविंग इमिशंस (आरडीई) अपनाने की दिशा में कदम बढ़ने से यूरोपीय संघ में कारोबार की स्थिति सुधरी है। कैलेंडर वर्ष 2019 की दूसरी छमाही में सुधार से जनवरी से नवंबर में बिक्री में कमी 0.3 प्रतिशत के साथ मामूली रही। कैलेंडर वर्ष 2019 की पहली छमाही में कार कंपनियों की बिक्री में यूरोपीय संघ में 3.1 प्रतिशत की गिरावट आई। वैश्विक कार निर्माता एवं कुल-पुर्जा निर्माता कंपनियों ने संकेत दिए हैं कि कैलेंडर वर्ष 2020 में यूरोपीय संघ के बाजारों में तेजी रहेगी।

स्थितियां सुधरने से कल-पुर्जा निर्माता कंपनियों में मदरसन सूमी को सर्वाधिक लाभ मिलेगा। सितंबर तिमाही में मजबूत प्रदर्शन और वैश्विक स्तर पर वाहन बाजार में मांग सुधरने से कंपनी के शेयर में पिछले तीन महीनों से 48 प्रतिशत तेजी आई है। गोल्डमैन सैक्स के विश्लेषकों का मानना है कि नए संयंत्र और नए कारोबारी सौदों के क्रियान्वयन की बदौलत मदरसन सूमी की कमाई वित्त वर्ष 2021 में सबसे अधिक रह सकती है। जिंस कीमतों में नरमी और इसकी सहायक इकाई एसएमपी में सुधार से भी कंपनी को लाभ होगा। हालांकि कीमतों में तेजी के मद्देनजर निवेशक निचले स्तर शेयर खरीदने पर विचार कर सकते हैं। माहौल में सुधार से बालकृष्ण इंडस्ट्रीज को भी लाभ मिल रहा है। कंपनी विशेष इस्तेमाल के लिए टायर बनाती है। अमेरिकी एवं यूरोपीय संघ के बाजारों के दम पर नवंबर में कृषि एवं ऑफ-द-रोड (ओटीआर) खंडों में टायर की मांग में 12 प्रतिशत की तेजी देखी गई। यह पिछले 14 महीनों की सर्वाधिक तेजी रही। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के निशांत वास का मानना है कि कैलेंडर वर्ष 2020 में अमेरिका-चीन में समझौता होने के बाद वितरकों का उत्साह बढ़ेगा और वाहनों के उत्पादन में दोबारा तेजी आनी शुरू हो जाएगी। विश्लेषकों के अनुसार हाल की तेजी के बावजूद शेयर में और 25 प्रतिशत तक तेजी आ सकती है।

भारत फोर्ज के लिए संभावनाएं थोड़ी मिलीजुली लग रही हैं। उसके सबसे बड़े खंड-व्यावसायिक वाहन- में निकट अवधि से जुड़ी चुनौतियां अधिक हैं। भारत और अमेरिका दोनों बाजारों में कंपनी के इस खंड को चुनौती का सामना करना पड़ रहा है।

कोल इंडिया: नई कंपनियों से फिलहाल दबाव नहीं

श्रीपाद ऑटे

खुले बाजार में बिक्री के लिए अन्य कंपनियों को कोयला खनन की अनुमति देने वाले अध्यादेश को सरकार की मंजूरी से कोल इंडिया के शेयर पर दबाव देखने को मिला था।

खनन की अनुमति के ताजा घटनाक्रम से स्थिति और बदतर हुई है और इससे कोल इंडिया के व्यवसाय पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने की आशंका है। 2020 के पहले 9 महीनों के दौरान कंपनी की बिक्री कमजोर रही है और इस अवधि में उत्पादन तथा उठाव में लगभग 6 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई। हालांकि यह प्रभाव दीर्घावधि में दिखने का अनुमान है, लेकिन इससे अल्पावधि में कोल इंडिया को किसी तरह का नुकसान पहुंचने की आशंका नहीं है और उसकी बिक्री का बड़ा हिस्सा सुरक्षित बना हुआ है। नार्नोलिया फाइनैंशियल एडवाइजर्स में शोध प्रमुख विनीता शर्मा ने कहा, 'कोल इंडिया के व्यवसाय का बड़ा हिस्सा दीर्घावधि ईंधन आपूर्ति समझौते (एफएसए) से संबंधित है, जिस पर प्रभाव नहीं दिखेगा।' वित्त वर्ष 2019 में 60 करोड़ टन से अधिक की कुल बिक्री में 85 प्रतिशत एफएसए के तहत हुई थी। शेष 15 प्रतिशत बिक्री से जोखिम जुड़ा हुआ है। एक घरेलू ब्रोकिंग हाउस का मानना है कि नई कंपनियों को उत्पादन शुरू करने में कम से कम 5-6 साल लगेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि कोल इंडिया का अल्पावधि परिदृश्य ज्यादा उत्साहजनक नहीं है क्योंकि वित्त वर्ष 2020 के लिए उत्पादन और उठाव में वृद्धि की रफ्तार कमजोर रहने की आशंका है।

ईंधन आपूर्ति समझौते ने कंपनी के व्यवसाय को प्रतिस्पर्धा से काफी हद तक सुरक्षित बनाया है

फिल्म निर्देशक जोया अख्तर (बाएं), विरोध प्रदर्शन में बैठे अनुराग कश्यप समेत फिल्म जगत की कई हस्तियां (नीचे बाएं) और अदाकार फरहान अख्तर (नीचे दाएं)

जन आंदोलन के सुर बुलंद करता बॉलीवुड

बॉलीवुड कारोबारी हितों के लिए राजनीतिक झंझावातों से खुद को अछूता रखने पर जोर देता रहा है पर इस दफा उद्योग के लोगों ने अप्रत्याशित तौर पर सक्रियता दिखाई है

अरुंधति दासगुप्ता और अमृता पिल्लई

बॉलीवुड सितारों की चमचमाती दुनिया के हर घंटे का लेखा-जोखा होता है। उनके बारे में लोग ट्वीट भी करते हैं लेकिन राजनीति के लिए यहां थोड़ी ही गुंजाइश दिखती है। अमूमन इन सितारों की जिंदगी प्यार, फिल्में, फिटनेस, जोड़ियों के लक्ष्य के इर्द-गिर्द ही घूमती रहती है और वे खुद सोशल मीडिया पर हल्की-फुल्की बातें ही साझा करते हैं। हालांकि इस लिहाज से पिछला हफ्ता थोड़ा अलग रहा।

बॉलीवुड की सामान्यतौर पर अच्छी और आकर्षक लगने वाली चीजों की जगह जुलूस, विरोध प्रदर्शन से जुड़ी कविताएं और विद्रोह गीत ने ले ली जिससे अभियान में जोश बढ़ गया। फिल्म जगत से जुड़े कई लोगों ने बोलना शुरू किया और विरोध प्रदर्शन में शिरकत करने के लिए अपने सुरक्षित दायरे से बाहर निकले और उन्होंने धरना और जुलूस से जुड़ी सूचनाओं को रिट्वीट करना शुरू कर दिया। इंस्टाग्राम टाइमलाइन पर आलिया भट्ट ने लिखा, 'जब छात्र, शिक्षक और शांति से रहने वाले नागरिक रोजमर्रा आधार पर शारीरिक हमले का शिकार होते हैं तब यह मान लेना गलत है कि सबकुछ ठीक है। हमे सच से आंख से आंख मिलाकर जरूर देखना चाहिए और यह स्वीकार करना चाहिए कि हमारे घर में ही युद्ध जैसी स्थिति है।'

बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा दीपिका पडुकोणे की फिल्म छपाक इस शुक्रवार को रिलीज हुई। उन्होंने मुंबई की एक रैली में हिस्सा लेने के बाद कहा, 'यह देखना सुखद है कि लोग सड़कों पर निकल रहे हैं। मुझे इस बात का गर्व है कि लोग अपने विचारों को उठा रहे हैं चाहे वह सड़क से उठाते हों या फिर अपने घर से।' वह केवल इस बयान तक ही सीमित नहीं रहीं बल्कि उन्होंने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में हिंसक हमले का शिकार हुए छात्रों के समर्थन में विश्वविद्यालय परिसर में जाने का फैसला लिया और

वे प्रदर्शनकारियों के साथ खड़ी नजर आईं।

मशहूर निर्देशक और संगीतकार विशाल भारद्वाज अपनी फिल्मों और संगीत के अलावा शायद ही कभी किसी विषय पर बोलते हैं लेकिन उन्हें नागरिकता संशोधन कानून और छात्रों के पर हिंसक कार्रवाई के खिलाफ एक रैली में मुंबई के कार्टर रोड पर कविता पाठ करते हुए सुना गया। उन्होंने प्रदर्शनकारियों से कहा कि सुबह होने से पहले हमेशा अंधेरा छाया रहता है ऐसे में आप अपना भरोसा बुलंद रखें। विरोध प्रदर्शन के इस जुलूस में अनुराग कश्यप, वरुण ग्रोवर, स्वरा भास्कर, जावेद अख्तर, फरहान अख्तर, जावेद जाफरी के साथ कई अन्य लोग भी नजर आए।

ऐसा नहीं है कि फिल्मी जगत से जुड़े ज्यादातर कलाकार केवल प्रदर्शनकारियों के समर्थन में अपनी आवाज उठा रहे हैं बल्कि इनमें कुछ ऐसे हैं जो सरकार के कदमों का समर्थन भी कर रहे हैं। मशहूर अभिनेत्री जूही चावला ने नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) द्वारा मुंबई में आयोजित एक रैली में हिस्सा लिया वहीं अभिनेता अजय देवगन ने कहा कि वह तथ्यों के सामने आने तक इंतजार करेंगे। बॉलीवुड के लोकप्रिय अभिनेता अक्षय कुमार और अमिताभ बच्चन अपनी चुप्पी की वजह से सुर्खियों में रहे।

फिल्मी जगत की दुनिया कई झंझावातों में भी खुद को बखूबी बचाने का हुनर जानती हैं लेकिन इस बार

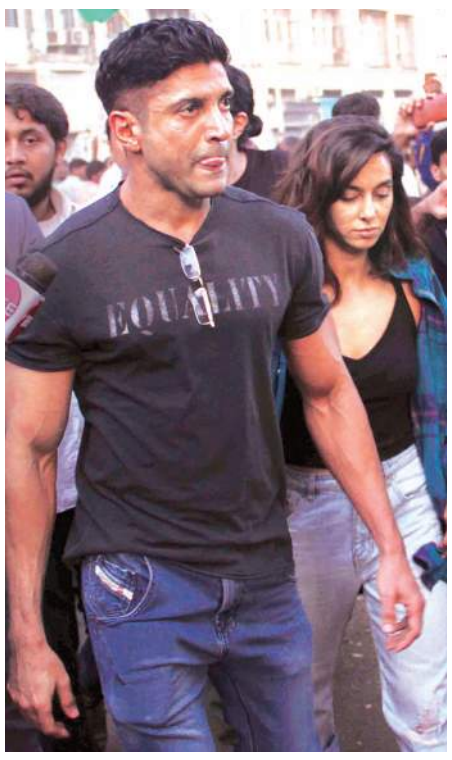

एक राजनीतिक मुद्दे पर इस उद्योग के लोगों की आवाज बुलंद होना अप्रत्याशित है। कला और थियेटर को बढ़ावा देने वाले एक मंच जुनून की संस्थापक संजना कपूर कहती हैं, 'छात्र आंदोलन के उभार और लोगों के बाहर निकलने और आवाज उठाने की आजादी पर अंकुश लगने जैसी स्थिति का सामना करने के लिए मेरे भीतर साहस जरूर है। यह महसूस करना अच्छा है कि कोई अकेला नहीं है और किसी को चुप नहीं कराया जा सकता।'

पेशे से जुड़े जोखिम

इंडिया फाउंडेशन फॉर दि आर्ट्स (आईएफए) की कार्यकारी निदेशक अरुंधती घोष का कहना है कि अपनी आवाज उठाने के लिए साहस की जरूरत होती है। आवाज उठाने का पेशागत नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। मुमकिन है कि ऐसी सक्रियता की वजह से किसी निर्माता की फिल्म को पहले सप्ताहांत में दर्शक भी न मिलें और किसी अभिनेता/अभिनेत्री को काम न मिले। इसके अलावा भी कई चिंताएं हैं जो खासतौर पर उन लोगों से जुड़ी हैं जो लोग किसी ब्रांड के साथ करार करते हैं या फिर किसी सामाजिक अभियान से जुड़े हैं। मिसाल के तौर पर एक ऑनलाइन दवा कंपनी मेडलाइफ के साथ दीपिका का ब्रांड करार है लेकिन जेएनयू में उनकी मौजूदगी की वजह से लोगों ने उन पर भद्दी टिप्पणी करने के साथ यह धमकी तक दे डाली की वे ऐप को अपने टाइमलाइन से डिलीट कर देंगे। दीपिका की आलोचना करने के साथ-साथ फिल्म 'छपाक' का बहिष्कार करने का भी लोगों ने ऐलान कर दिया।

ऑर्मेक्स कंज्यूमर एक्सप्रेस के सीईओ प्रिया लोबो कहती हैं कि हमारे यहां स्कूल, घर या दफ्तरों में ऐसा महौल नहीं है कि लोगों को अपनी आवाज उठाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। वह कहती हैं, 'सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि देश के सोशल मीडिया का अर्थ लोगों को ट्रोल करना है और मुझे लगता है कि लोग इसमें फंसना भी नहीं चाहते। किसी भी अभिनेता/अभिनेत्री के लिए सबसे आसान यह है कि वे जलवायु परिवर्तन (या लड़कियों की शिक्षा, जल संरक्षण) जैसे मुद्दों के लिए अपने चेहरे का इस्तेमाल कर संदेश दे दें और कई लोगों ने सरकारी योजनाओं के समर्थन में ऐसा किया भी है।' लेकिन राजनीतिक और वैचारिक मसला बिल्कुल अलग ही बात है। कई लोगों का कहना है कि मतभेद वाली स्थिति इस वजह से भी बनती है क्योंकि कला भले ही राजनीति से जुड़ी है लेकिन कारोबार के साथ ऐसी बात नहीं है। शायद इसी वजह से काफी पहले से ही बॉलीवुड ने कारोबार की वजह से राजनीति से दूर रहने का फैसला किया। लेकिन थियेटर की दुनिया में ऐसा नहीं है जहां भेदभाव वाली नीतियों के खिलाफ और उसके लिए प्रदर्शन काफी लंबे समय से होता रहा है। मुंबई के एक थियेटर समूह 'तमाशा' के सह संस्थापक सुनील शानबाग और सपन शरण का कहना है कि थियेटर जगत में कलाकारों की बिरादरी छात्रों के समर्थन में है और वे इन मुद्दों पर गीत गाने, कविता लिखने के साथ रात भर धरने में बैठते भी हैं। उनका कहना है कि पहले के मुकाबले बड़ी तादाद में लोगों का हुजूम उमड़ रहा है।

नागरिकता संशोधन कानून और छात्रों पर हमला विरोध का प्रमुख मुद्दा रहा। फिल्म निर्देशक तनुजा चंद्रा का मानना है कि नाराजगी और रोष की वजह से उनके जैसे लोग सड़कों पर निकल रहे हैं। वह कहती हैं, 'छात्रों पर निरंकुश और गैरकानूनी तरीके से हमला किया गया और शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया कई निर्दोष लोगों की जान चली गई। मैं इस बात पर हैरान हूं कि प्रशासन ने किस तरह जन प्रतिरोध दबाने की कोशिश की और मुझे लगता है कि फिल्म जगत के लोग भी इस बात पर नाराज होंगे।'

महिलाएं आगे

बॉलीवुड ने जहां असंतोष के सुर को पहचानने की कोशिश की है वहीं इस उद्योग की प्रमुख महिलाएं इस सुर को प्रबलता दे रही हैं। आलिया भट्ट और दीपिका जैसी अभिनेत्रियों ने इस विरोध प्रदर्शन को सुर्खियों में लाने का काम किया वहीं ऋचा चड्ढा, तापसी पन्नू, स्वरा भास्कर, कोंकणा सेन शर्मा विरोध-प्रदर्शन के समय के बारे में पोस्ट करने के साथ-साथ पोस्टर लगा रही हैं और देश भर से प्रदर्शन की खबरों को रिट्वीट कर रही हैं। मशहूर निर्देशक जोया अख्तर भी मुंबई की रैलियों में हिस्सा लेते हुए नजर आईं।

अक्षय कुमार की छात्रों की हिंसा के खिलाफ कोई टिप्पणी न करने की वजह से आलोचना की गई तब उनकी पत्नी और अदाकारा ट्विंकल खन्ना ने ट्वीट किया, 'भारत में गाय को छात्रों के मुकाबले ज्यादा सुरक्षा दी जाती है और यह एक ऐसा देश है जो अब झुकने के लिए तैयार नहीं है।' महिला प्रदर्शनकारी पुलिस के सामने दृढ़ता से खड़ी होकर, निडरता से गाकर और ठंड में पूरी रात धरने में बैठकर इस पूरे अभियान को परिभाषित कर रही हैं। जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय की दो छात्रों लदीदा फरजाना और आयशा रेन्ना अपने पुरुष दोस्तों को दिल्ली पुलिस से बचाती हुई नजर आईं जबकि सर में पट्टी बांधे जेएनयू छात्र संघ की अध्यक्ष आइशी घोष भीड़ को संबोधित करती नजर आईं।

ममता पर मोदी का तीखा प्रहार

फोटो:पीटीआई

105 साल के पेंशनभोगी का सम्मान करते प्रधानमंत्री मोदी

अभिषेक रक्षित

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच शनिवार को हुई मुलाकात के ठीक एक दिन बाद मोदी ने उनके ही राज्य में ममता पर कटाक्ष किए और कहा कि राज्य केंद्र सरकार की योजनाओं को लागू नहीं कर रहा है क्योंकि इससे दूसरे गुटों को कोई लाभ नहीं होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि आयुष्मान भारत तथा किसानों के बैंक खाते में सीधे रुपये भेजने वाली प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना से बड़े पैमाने पर लोगों को लाभ पहुंचा है और अभी तक किसानों के खातों में 43,000 करोड़ रुपये पहुंचाए जा चुके हैं। मोदी ने कहा, 'मैं नहीं जानता कि यहां (पश्चिम बंगाल) ये दिए जा रहे हैं लेकिन अगर ये दिए गए तो इससे लोगों को लाभ पहुंचेगा।'

उन्होंने कहा, 'लाभार्थियों के खाते में प्रत्यक्ष धन अंतरण में बीच में किसी तरह की पैसों की कटौती नहीं होती है (जैसा कि राजनेताओं तथा दूसरे प्रभावशाली लोगों द्वारा आरोप लगाए गए थे)। साथ ही इस प्रणाली में किसी तरह की सेंधमारी नहीं हो सकती।' मोदी ने आरोप लगाया कि इन वजहों से ही पश्चिम बंगाल सरकार ये योजनाएं लागू करने की इच्छुक नहीं है।

राज्य में मोदी ने कोलकाता बंदरगाह का नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह रखने की घोषणा की है

प्रधानमंत्री मोदी ने प्रत्यक्ष तौर पर ममता का नाम लिए बिना कहा, 'मैं नीति निर्धारक को सद्बुद्धि देने के लिए भगवान से प्रार्थना करूंगा। मैं चाहता हूं कि लोग इन योजनाओं से लाभान्वित हों। मैं लोगों के गुस्से को भी समझता हूं। मैं जानता हूं कि अब लोगों को इन योजनाओं का लाभ लेने से कोई नहीं रोक सकता।' पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत की तर्ज पर राज्य की 'स्वास्थ्य साथी' तथा स्वच्छ भारत के स्थान पर 'निर्मल बंगाल' योजनाएं चल रही हैं। राज्य में पिछले साल 'कट-मनी घोटाला' सामने आया था जिसके बाद ममता ने कमीशन के जरिये कमाए गए पैसे को लौटाने का आदेश दिया था।

छात्रों के खिलाफ हुई हिंसा की निंदा करने और सीएए का विरोध करने के बावजूद ममता नई दिल्ली में कांग्रेस तथा विपक्षी दलों की बैठक में शामिल नहीं हुई और कोलकाता में प्रधानमंत्री से मुलाकात की।

ममता ने मुलाकात को शिष्टाचार भेंट बताया। हालांकि शनिवार को मोदी से मुलाकात के बाद कांग्रेस-वाम दलों की ओर से ममता पर दोहरा चरित्र रखने का आरोप लगाया गया। हालांकि ममता ने इन आरोपों को नकार दिया और कहा कि उन्होंने सीएए पर पुनर्विचार तथा इसे वापस लेने के लिए मोदी से मुलाकात की।

प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद ममता सीएए तथा एनआरसी के खिलाफ कोलकाता में चल रहे प्रदर्शन में शामिल हुईं।

कोलकाता बंदरगाह के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में ममता को प्रधानमंत्री मोदी के साथ मंच साझा करने के लिए आमंत्रित किया गया लेकिन वह शामिल नहीं हुईं। यहां मोदी ने घोषणा की कि देश में जलमार्गों के विकास में योगदान को देखते हुए बंदरगाह का नाम बदलकर डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह किया जाएगा।

मोदी ने कहा, 'मुखर्जी और बाबा साहेब आंबेडकर ने स्वतंत्र भारत में नीतियों को दिशा दी जिसमें जलमार्गों के विकास तथा तटीय स्थानों पर जहाज से यात्रा पर भी जोर दिया गया था। दुर्भाग्य से उनके सुझावों पर अधिक गौर नहीं किया गया।'

रजनीकांत की लोकप्रियता भुना रहे दिग्गज ब्रांड

एयरटेल, बुकमाईशो, स्पाइसजेट, कैडबरी सहित कई अन्य ब्रांड ने रजनीकांत की नई फिल्म पर दांव लगाने का फैसला किया है

गिरीश बाबू

मशहूर अदाकार रजनीकांत 2019 की फोर्ब्स इंडिया सेलिब्रिटी 100 की सूची में 13वें पायदान पर हैं। रजनीकांत का फिल्मी सितारों के बीच अहम स्थान है। ब्रांड रजनीकांत की ताकत को न तो उनकी उम्र से और न ही उनके रूप रंग से कोई फर्क पड़ता है। तमिल फिल्मों में अपनी शुरुआत करने के 45 सालों के बाद भी इस 69 साल के अभिनेता का जलवा फीका नहीं पड़ा है और अब भी यह आलम है कि नई फिल्म के रिलीज होने से पहले ब्रांड बड़ी बेसब्री से उनकी फिल्म का इंतजार करते हैं। उनकी नई फिल्म 'दरबार' पिछले हफ्ते रिलीज हुई। फिल्म निर्माता का कहना है कि फिल्म रिलीज से काफी पहले ही कई ब्रांड में उनकी फिल्म से जुड़ने की होड़ लग चुकी थी।

उनका जलवा विभिन्न पीढ़ी के दर्शकों के बीच कायम है और वह न केवल दक्षिण में बल्कि देश भर और दुनिया के विभिन्न हिस्से में मौजूद भारतीयों के बीच लोकप्रिय हैं। रजनीकांत किसी भी उत्पाद के लिए विज्ञापन करार नहीं करते हैं ऐसे में उनकी फिल्में, उनसे जुड़े मीम और जोक्स भी उनकी ताकत को बयां करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि ये सब ही एकमात्र ऐसा तरीका है जिसके जरिये ब्रांड उनकी लोकप्रियता का फायदा उठा सकते हैं।

दर्शकों में उत्साह

'दरबार' के निर्माता लाइका प्रोडक्शंस का कहना है कि उनसे पहले से ही चार बड़े ब्रांड जुड़ चुके थे और आखिरी दौर में कुछ छोटे ब्रांडों से भी बातचीत हुई। एयरटेल, बुकमाईशो, स्पाइसजेट और कैडबरी (मॉन्डलेज) ने इस फिल्म से जुड़ा एक विज्ञापन तैयार किया ताकि रजनीकांत के प्रशंसकों को लुभाया जा सके जो आमतौर पर उनकी फिल्म के रिलीज के मौके पर काफी उत्साह में रहते हैं।

भारती एयरटेल (तमिलनाडु और केरल) के मुख्य कार्याधिकारी (सीईओ) मनोज मुरली कहते हैं, 'इस प्रक्रिया में हम पैसा नहीं कमा पाते हैं। मैं ग्राहकों को मुफ्त की सामग्री देता हूं। उनके लिए एयरटेल देखने और ब्रांड के साथ जुड़े रहने की रजनीकांत प्रमुख वजह बन जाते हैं।' पहले भी एयरटेल ने रजनीकांत की दूसरी फिल्मों 'कबाली' और 'काला' के लिए भी करार किया था। मुरली का कहना है कि रजनीकांत की लोगों में इतनी अपील है कि कई लोग एयरटेल एक्सस्ट्रीम ऐप को केवल थलाइवा को देखने के लिए डाउनलोड करते हैं।

दरबार एक 'एक्शन थ्रिलर' फिल्म है जिसके निर्देशक ए आर मुर्गदास हैं। यह फिल्म गुरुवार को देश और विदेश के करीब 7,000 स्क्रीन पर रिलीज हुई। एयरटेल ने इस फिल्म और इसके नायक से जुड़े क्विज और विशेष ऑफर की

गुरुवार को चेन्नई के एक सिनेमाघर में रजनीकांत के प्रशंसक

फोटो: पीटीआई

पेशकश की जबकि बुकमाईशो ने विशेष छूट दी। विमानन कंपनी स्पाइसजेट ने तो फिल्म में रजनीकांत के किरदार की बड़ी तस्वीर विमान पर विशेषतौर पर डिजाइन करा दी। मॉन्डलेज विज्ञापन और अन्य मीडिया साधनों के जरिये अपने करार का फायदा उठाने की कोशिश में है।

ब्रांडिंग के परंपरागत तरीके के जरिये फायदा उठाने के साथ-साथ विभिन्न ब्रांड सोशल मीडिया पर भी इस फिल्म को लेकर चर्चा कर रहे हैं। मुख्य परिचालन अधिकारी (सीओओ) पी कानन कहते हैं, 'इस गठजोड़ से मीडिया खर्च का प्रबंधन करने में मदद मिल सकती है। यह ब्रांड और फिल्म निर्माता के लिए जीत वाली स्थिति है।' लाइका रजनीकांत प्रोडक्शन का हिस्सा रही है और उसका कहना है कि ब्रांड गठजोड़ फिल्म निर्माण का एक अहम हिस्सा है।

फोर्ब्स इंडिया सेलिब्रिटी 100 की सूची में रजनीकांत 13वें पायदान पर हैं और फिल्मी सितारों के बीच उनका एक अहम दर्जा है। उनकी लोकप्रियता दक्षिण तक ही सीमित नहीं है और उनके प्रशंसक केवल किसी खास उम्र वर्ग तक ही सीमित नहीं हैं।

डिजिटल क्षेत्र में दखल

विशेषज्ञों का कहना है कि ब्रांड रजनीकांत ने डिजिटल क्षेत्र में भी बड़ी आसानी से अपनी दखल बढ़ाई है। उनके चुटीले मीम और सुपरहीरो वाली छवि के जोक्स की वजह से वह उन लोगों के बीच भी जाना-पहचाना नाम हैं जिन्होंने उनकी फिल्में कभी नहीं देखी हैं। उनके प्रशंसकों के 5-7 फैन क्लब हैं जिनके लाखों सदस्य हैं और वे एक दिन में तकरीबन 100 पोस्ट करते हैं जिनमें से ज्यादातर प्रशंसकों का रजनीकांत के प्रति समर्पण का भाव नजर आता है।

रजनीकांत को लेकर ब्रांडों में एक अलग तरह का आकर्षण हैं लेकिन वह किसी भी ब्रांड का चेहरा नहीं बनते हैं ऐसे में फिल्में ही एक तरीका हैं जिसके जरिये नए विकल्पों को भुनाया जा सकता है। दो चार्टड अकाउंटेंट और लेखक पी सी बालासुब्रमण्यम और राम एन रामकृष्णन ने ग्रैंड ब्रांड रजनी नाम की किताब लिखी है। इस किताब में बताया गया है कि ब्रांड रजनी खुद को बेचता है। उनके प्रशंसक उनकी फिल्में नहीं बल्कि उन्हें देखने के लिए जाते हैं।